रजिस्ट्री सं. डी. (डी. एन.)—73

REGISTERED NO. D. (D. N.)—73

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1] नई दिल्ली, शनिवार, जनवरी 5, 1985/पौष 15, 1906
No. 1] NEW DELHI, SATURDAY, JANUARY 5, 1985/PAUSA 15, 1906

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

(रक्षा मंत्रालय को छोड़ कर) भारत सरकार के मंत्रालयों द्वारा जारी किये गये सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं
Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence)

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय

(विधि कार्य विभाग)

नई दिल्ली, 18 दिसम्बर, 1984

सूचना

का.आ. 1.—नोटरीज नियम, 1956 के नियम 6 के अनुसरण में सक्षम प्राधिकारी द्वारा यह सूचना दी जाती है कि श्री एन जी केटान, सालिसिटर और एडवोकेट, 1 बी, पुराना डाकखाना गली, कलकत्ता-700001, ने उक्त प्राधिकारी को उक्त नियम 4 के अधीन एक आवेदन इस बात के लिए दिया जा रहा है कि उसे कलकत्ता और नई दिल्ली व्यवसाय करने के लिए नोटरी के रूप में नियुक्त किया जाए।

2. उक्त व्यक्ति की नोटरी के रूप में नियुक्ति पर किसी भी प्रकार का आक्षेप इस सूचना के प्रकाशन के चौदह दिन के भीतर लिखित रूप में मेरे पास भेजा जाए।

[सं. फा. 5(61)/84-न्या.]

एस. गुप्तु, सक्षम प्राधिकारी

MINISTRY OF LAW, JUSTICE & CO. AFFAIRS

(Department of Legal Affairs)

New Delhi, the 18th December, 1984

NOTICE

S.O. 1.—Notice is hereby given by the Competent Authority in pursuance of rule 6 of the Notaries Rules, 1956, that application has been made to the said Authority, under rule 4 of the said Rules, by Shri N. G. Khaitan, Solicitor & Advocate, 1B Old Post Office Street Calcutta-700001, for appointments as a Notary to practise in Calcutta and New Delhi.

2. Any objection to the appointment of the said person as a Notary may be submitted in writing to the undersigned within fourteen days of the publication of this Notice.

[No. F. 5(61)/84-Judl.]

S. GOOPTU, Competent Authority

गृह मंत्रालय

नई दिल्ली, 20 नवम्बर, 1984

का.आ. 2.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 77 के खंड (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अधिप्रमाणन

(आदेश और अन्य लिखित) नियम, 1958 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम अधिप्रमाणन (आदेश और अन्य लिखित) (सातवां संशोधन) नियम, 1984 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. अधिप्रमाणन (आदेश और अन्य लिखित) नियम, 1958 में, (i) खंड 20 में, "संयुक्त सचिव और प्रारुपकार" "अपर प्रारुपकार", "उप प्रारुपकार" और "सहायक प्रारुपकार" शब्दों के स्थान पर, जहां-जहां वे आते हैं, क्रमशः "संयुक्त सचिव और विधायी परामर्शी", "अपर विधायी परामर्शी", उप विधायी परामर्शी "और सहायक विधायी परामर्शी" शब्द रखे जाएंगे ;

(ii) अनुसूची में, शीर्षक और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:-

"विधि न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय (विधायी विभाग) : राजभाषा खंड — संयुक्त सचिव और विधायी परामर्शी

[सं. 23/7/84-पब्लिक]

एस. आर. आर्य, संयुक्त सचिव

टिप्पणी :

मूल नियम, भारत के राजपत्र भाग 2, खंड 3, उपखंड (ii) में, अधिसूचना सं. 2297 तारीख 3 नवम्बर 1958 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और पश्चात्वर्ती संशोधन भारत के राजपत्र भाग 2, खंड 3, उपखंड (ii) में अधिसूचना सं. का. आ. 3406 द्वारा किए गए और निम्नलिखित द्वारा समय समय पर संशोधन किए गए हैं :-

(1)	का. आ. सं. 1270	तारीख 27-3-1971
(2)	का. आ. सं. 1271	तारीख 27-3-1971
(3)	का. आ. सं. 1521	तारीख 10-4-1971
(4)	का. आ. सं. 1668	तारीख 24-4-1971
(5)	का. आ. सं. 2996	तारीख 11-8-1971
(6)	का. आ. सं. 5079	तारीख 3-11-1971
(7)	का. आ. सं. 5239	तारीख 26-11-1971
(8)	का. आ. सं. 5252	तारीख 29-11-1971
(9)	का. आ. सं. 5594	तारीख 30-12-1971
(10)	का. आ. सं. 210(ख)	तारीख 18-3-1972
(11)	का. आ. सं. 299(अ)	तारीख 18-4-1972
(12)	का. आ. सं. 327(अ)	तारीख 29-4-1972
(13)	का. आ. सं. 513(अ)	तारीख 31-7-1972
(14)	का. आ. सं. 568(अ)	तारीख 30-8-1972
(15)	का. आ. सं. 716(अ)	तारीख 18-11-1972
(16)	का. आ. सं. 23(अ)	तारीख 17-01-1973
(17)	का. आ. सं. 507(अ)	तारीख 19-9-1973
(18)	का. आ. सं. 519(अ)	तारीख 26-9-1973
(19)	का. आ. सं. 552(अ)	तारीख 19-10-1973
(20)	का. आ. सं. 724(अ)	तारीख 1-12-1973
(21)	का. आ. सं. 263(अ)	तारीख 26-4-1973
(22)	का. आ. सं. 321(अ)	तारीख 24-5-1974
(23)	का. आ. सं. 26[illegible](अ)	तारीख 18-6-1975
(24)	का. आ. सं. 14[illegible](अ)	तारीख 25-2-1976
(25)	का. आ. सं. 195(अ)	तारीख 15-3-1976
(26)	का. आ. सं. 348(अ)	तारीख 14-5-1976
(27)	का. आ. सं. 480(अ)	तारीख 19-7-1976
(28)	का. आ. सं. 493(अ)	तारीख 24-7-1976
(29)	का. आ. सं. 599(अ)	तारीख 6-9-1976
(30)	का. आ. सं. 698(अ)	तारीख 30-10-1976
(31)	का. आ. सं. 19(अ)	तारीख 12-1-1977
(32)	का. आ. सं. 228(अ)	तारीख 18-3-1977
(33)	का. आ. सं. 255(अ)	तारीख 24-3-1977
(34)	का. आ. सं. 408(अ)	तारीख 23-6-1977
(35)	का. आ. सं. 603(अ)	तारीख 2-8-1977
(36)	का. आ. सं. 649(अ)	तारीख 3-9-1977
(37)	का. आ. सं. 320(अ)	तारीख 12-5-1978
(38)	का. आ. सं. 419(अ)	तारीख 30-6-1978
(39)	का. आ. सं. 2914	तारीख 7-10-1978
(40)	का. आ. सं. 598(अ)	तारीख 10-10-1978
(41)	का. आ. सं. 576(अ)	तारीख 17-2-1979
(42)	का. आ. सं. 1020	तारीख 24-3-1979
(43)	का. आ. सं. 338(अ)	तारीख 7-6-1979
(44)	का. आ. सं. 3569	तारीख 27-10-1979
(45)	का. आ. सं. 852(अ)	तारीख 18-12-1979
(46)	का. आ. सं० 245(अ)	तारीख 11-4-1980
(47)	का. आ. सं. 543(अ)	तारीख 7-8-1981
(48)	का. आ. सं. 768(अ)	तारीख 23-10-1981
(49)	का. आ. सं. 917(अ)	तारीख 28-12-1981

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

New Delhi, the 20th December, 1984

S.O. 2.—In exercise of the powers conferred by clause (2) of article 77 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Authentication (Orders and Other Instruments) Rules, 1958, namely :—

1. (1) These rules may be called the Authentication (Orders and Other Instruments) (Seventh Amendment) Rules, 1984.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Authentication (Orders and other Instruments) Rules, 1958 :—

(i) in clause 20, for the words "Joint Secretary and Draftsman" "Additional Draftsman" "Deputy Draftsman" and "Assistant Draftsman", wherever they occur, the words "Joint Secretary and Legislative Counsel", "Additional Legislative Counsel", "Deputy Legislative Counsel", and "Assistant Legislative Council", shall respectively be substitued;

(ii) in the Schedule for the heading and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely :—

"MINISTRY OF LAW, JUSTICE

AND COMPANY AFFAIRS

(LEGISLATIVE DEPARTMENT)

Official Languages Wing

Jt. Secy. and
Lgislative Counsel"
[No. 23/7/84-Public]
S. R. ARYA, Jt. Secy.

Note : Principal rules published vide notification No. 2297, dated the 3rd November, 1958, Gazette of India, Part, II Section 3, Sub-section (ii), Subsequently amended vide notification No. S.O. 3406 dated 24th October, 1970 published in Part II, Section 3 sub-section (ii) have been amended from time to time vide :—

1. S.O. No. 1270 dated 27-3-1971.
2. S.O. No. 1271 dated 27-3-1971.
3. S.O. No. 1521 dated 10-4-1971.
4. S.O. No. 1668 dated 24-4-1971.
5. S.O. No. 2996 dated 11-8-1971.
6. S.O. No. 5079 dated 3-11-1971.
7. S.O. No. 5239 dated 23-11-1971.
8. S.O. No. 5252 dated 29-11-1971.
9. S.O. No. 5594 dated 30-12-1971.
10. S.O. No. 210(E) dated 18-3-1972.
11. S.O. No. 299(E) dated 18-4-1972.
12. S.O. No. 327(E) dated 29-4-1972.
13. S.O. No. 513(E) dated 31-7-1972.
14. S.O. No. 568(E) dated 30-8-1972.
15. S.O. No. 716(E) dated 18-11-1972.
16. S.O. No. 23(E) dated 17-1-1973.
17. S.O. No. 507(E) dated 19-9-1973.
18. S.O. No. 519(E) dated 26-9-1973
19. S.O. No. 552(E) dated 19-10-1973.
20. S.O. No. 724(E) dated 1-12-1973.
21. S.O. No. 263(E) dated 26-4-1973.
22. S.O. No. 321(E) dated 24-5-1974.
23. S.O. No. 265(E) dated 18-6-1975.
24. S.O. No. 140(E) dated 25-2-1976.
25. S.O. No. 195(E) dated 15-3-1976.
26. S.O. No. 348(E) dated 14-5-1976.
27. S.O. No. 480(E) dated 19-7-1976.
28. S.O. No. 493(E) dated 24-7-1976.
29. S.O. No. 599(E) dated 6-9-1976.
30. S.O. No. 698(E) dated 30-10-1976.
31. S.O. No. 19(E) dated 12-1-1977.
32. S.O. No. 228(E) dated 10-3-1977.
33. S.O. No. 255(E) dated 24-3-1977.
34. S.O. No. 408(E) dated 23-6-1977.
35. S.O. No. 603(E) dated 2-8-1977.
36. S.O. No. 649(E) dated 3-9-1977.
37. S.O. No. 320(E) dated 12-5-1978.
38. S.O. No. 419(E) dated 30-6-1978.
39. S.O. No. 2914 dated 7-10-1978.
40. S.O. No. 598(E) dated 19-10-1978.
41. S.O. No. 576 dated 17-12-1979.
42. S.O. No. 1020 dated 24-3-1979.
43. S.O. No. 338(E) dated 7-6-1979.
44. S.O. No. 3569 dated 27-10-1979.
45. S.O. No. 852(E) dated 18-12-1979.
46. S.O. No. 245(E) dated 11-4-1980.
47. S.O. No. 543(E) dated 7-8-1981.
48. S.O. No. 768(E) dated 23-10-1981.
49. S.O. No. 917(E) dated 28-12-1981

नई दिल्ली, 20 नवम्बर, 1984

का. आ. 3.—संविधान के अनुच्छेद 258 के खण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति, मेघालय सरकार की सहमति से एतद्द्वारा, मेघालय सरकार के अधीन (1) पुलिस अधीक्षक, ईस्ट खासी हिल्स डिस्ट्रिक्ट, (2) पुलिस अधीक्षक वैस्ट खासी हिल्स डिस्ट्रिक्ट (3) पुलिस अधीक्षक, जैन्तिया हिल्स डिस्ट्रिक्ट और (4) पुलिस अधीक्षक ईस्ट गारो हिल्स डिस्ट्रिक्ट, को भी अपने अपने अधिकार क्षेत्र में विदेशी व्यक्ति (अधिकरण) आदेश, 1964 के पैरा 2 के उप-पैरा (1) के अधीन केन्द्रीय सरकार के कर्तव्य निम्नलिखित शर्तों के साथ सौंपते हैं, अर्थात् :—

(क) कि ऐसे कर्तव्यों का पालन करने में उक्त पुलिस अधीक्षक, मेघालय सरकार या केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए सामान्य या विशेष निदेशों का पालन करेंगे; और

(ख) कि इस सुपुर्दगी के बावजूद यदि केन्द्रीय सरकार किसी मामले में ऐसा करना उचित समझे तो वह स्वंय भी उक्त कर्तव्यों में से किसी कर्तव्य का पालन कर सकती है।

[संख्या 14011/25/83-एफ. III]
एच. एस. गाबा, अवर सचिव

New Delhi, the 20th November, 1984

S.O. 3.—In exercise of the powers conferred by clause (1) of Article 258 of the Constitution, the President, with the consent of the Government of Meghalaya, hereby entrusts also to (1) the Superintendent of Police, East Khasi Hills District, (2) the Superintendent of Police, West Khasi Hills District, (3) The Superintendent of Police, Jaintia Hills District, (4) The Superintendent of Police, West Garo Hills District and (5) The Superintendent of Police, East Garo Hills District under the Government of Meghalaya within their respective jursidiction the functions of the Central Government under sub-paragraph (1) of paragraph 2 of the Foreigners (Tribunals) Order, 1964, subject to the following conditions, namely :—

(a) that in the exercise of such functions the said Superintendents of Police shall comply with such general or special directions as the Government of Meghalaya or the Central Government may from time to time issue; and

(b) that notwithstanding this entrustment, the Central Government may itself exercise any of the said functions should it deem fit to do so in any case.

[No. 14011|25|83-F. III]
H. S. GABA, Under Secy.

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

नई दिल्ली, 26 नवम्बर, 1984

(आयकर)

का. आ. 4.—इस कार्यालय की दिनांक 25-9-1980 की अधिसूचना सं. 3673 (फा. सं. 203/176/80-आ. क. नि.-11 के सिलसिले में, सर्वसाधारण की जानकारी के लिए एतद्द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि विहित प्राधिकारी, अर्थात् विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, नई दिल्ली ने निम्नलिखित संस्था को आयकर नियम 1962 के नियम 6 के साथ पठित आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 की उपधारा (i) के खंड (iii) के प्रयोजनों के लिए "संस्था" प्रवर्ग के अधीन निम्नलिखित शर्तों पर अनुमोदित किया है, अर्थात :—

1. यह कि लोक विकास और प्रशिक्षण संस्थान, नई दिल्ली वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए उसके द्वारा प्राप्त राशियों का पृथक लेखा रखेगा।

2. यह कि उक्त संस्थान अपने वैज्ञानिक अनुसंधान संबंधी क्रियाकलापों का वार्षिक विवरणी, विहित प्राधिकारी को प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संबंध में प्रति वर्ष 30 अप्रैल, तक ऐसे प्ररुप में प्रस्तुत करेगा जो इस प्रयोजन के लिए अधिकथित किया जाए और उसे सूचित किया जाए।

3. यह कि उक्त संस्थान अपनी कुल आय तथा व्यय दर्शाते हुए अपने संपरीक्षित वार्षिक लेखों की तथा अपनी परिसंपत्तियाँ, देनदारियाँ दर्शाते हुए तुलन पत्र की एक- एक प्रति प्रतिवर्ष 30 जून तक विहित प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगा तथा इन दस्तावेजों में से प्रत्येक की एक-एक प्रति संबंधित आयकर आयुक्त को भेजेगा।

संस्था

"लोक विकास और प्रशिक्षण संस्थान, नई दिल्ली"

यह अधिसूचना 1-10-1983 से 31-3-1986 तक की अवधि के लिए प्रभावी है।

[सं. 6057 फा. सं. 203/202/84-आ. क. नि.-II]

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

New Delhi, the 26th November, 1984

INCOME-TAX

S.O. 4.—In continuation of this Office Notification No. 3673 (F. No. 203/176/80-ITA. II) dated 25-9-1980, it is hereby notified for general information that the Institution mentioned below has been approved by Department of Science and Technology, New Delhi, the Prescribed Authority for the purposes of clause (iii) of sub-section (1) of Section35 of the Income-tax Act, 1961 read with Rule 6 of the Income-tax Rules, 1962 under the category "Institution" subject to the following conditions :—

(i) That the People's Institute for Development and Training, New Delhi will maintain a separtae account of the sums received by it for scientific research.

(ii) That the said Institute will furnish annual returns of its scientific research activities to the Prescribed Authority for every financial year in such forms as may be laid down and intimated to them for this purpose by 30th April each year.

(iii) That the said Institute will submit to the Prescribed Authority by 30th June each year a copy of their audited annual accounts showing their total income and expenditure and balance sheet showing its assets and liabilities with a copy of each of these documents to the concerned Commissioner of Income-tax.

INSTITUTION

"People's Institute For Development And Training, New Delhi".

This notification is effective for a period from 1-10-1983 to 31-3-1986.

[No. 6057 (F. No. 203/202/84-ITA. II]

का. आ. 5.—सर्वसाधारण की जानकारी के लिए एतद्द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि विहित प्राधिकारी, अर्थात् विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, नई दिल्ली ने निम्नलिखित संस्था को आयकर नियम 1962 के नियम 6 के साथ पठित आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 की उपधारा (1) के खंड (ii) के प्रयोजनों के क्षेत्र में "संगम" प्रवर्ग के अधीन नम्नलिखित शर्तों पर अनुमोदित किया है, अर्थात्:—

1. यह कि दि एडिक्शन रिसर्च सेन्टर वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए उसके द्वारा प्राप्त राशियों का पृथक लेखा रहेगा।

2. यह कि उक्त संस्था अपने वैज्ञानिक अनुसंधान संबंध क्रियाकलापों की वार्षिक विवरणी, विहित प्राधिकारी को प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संबंध में प्रति वर्ष 30 अप्रैल, तक ऐसे प्ररुप में प्रस्तुत करेगा जो इस प्रयोजन के लिए अधिकथित किया जाए और उसे सूचित किया जाए।

3. यह कि उक्त अनुसंधान केन्द्र अपनी कुल आय तथा व्यय दर्शाते हुए अपने संपरीक्षित वार्षिक लेखों की तथा अपनी परिसंपत्तियां, देनदारियाँ दर्शाते हुए तुलन-पत्र की एक-एक प्रति, प्रति वर्ष 30 जून तक विहित प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगा तथा इन दस्तावेजों में से प्रत्येक की एक-एक प्रति संबंधित आयकर आयुक्त को भेजेगा।

संस्था

"एडिक्शन रिसर्च सेंटर, मद्रास"

यह अधिसूचना 1-4-1984 से 31-3-1986 तक के लिए प्रभावी है।

[सं. 6056 (फा. सं. 203/148/84-आ. क. नि-II]

S.O. 5.—It is hereby notified for general information that the Institution mentioned below has been approved by Department of Science and Technology, New Delhi, the Prescribed Authority for the purposes of clause (ii) of sub-section (1) of Section 35 of the Income-tax Act, 1961 read with Rule 6 of the Income-tax Rules, 1962 under the category "Association" subject to the following conditions :—

(i) That the Addiction Research Centre will maintain a separate account of the sums received by it for scientific research.

(ii) That the said Foundation will furnish annual returns of its scientific research activities to the Prescribed Authority for every financial year in such forms as may be laid down and intimated to them for this purpose by 30th April each year.

(iii) That the said Research Centre will submit to the Prescribed Authority by 30th June each year a copy of their audited annual accounts showing their total income and expenditure and balance sheet showing its assets and liabilities with a copy of each of these documents to the concerned Commissioner of Income-tax.

INSTITUTION

"Addiction Research Centre, Madras".

This notification is effective for a period from 1-4-1984 to 31-3-1986.

[No. 6056 (F. No. 203/148/84-ITA. II)]

का. आ. 6:—इस कार्यालय की दिनांक 19-8-1981 की अधिसूचना सं. 4169 (फा. सं. 203/61/81- आ. क. नि.-II) के सिलसिले में, सर्वसाधारण की जानकारी के लिए एतद्द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि विहित प्राधिकारी, अर्थात् विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, नई दिल्ली ने निम्नलिखित संस्था को आयकर नियम 1962 के नियम 6 के साथ पठित आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35

की उपधारा (1) के खंड (ii) के क्षेत्र में "संस्था" प्रवर्ग के अधीन निम्नलिखित शर्तों पर अनुमोदित किया है, अर्थात्:—

1. यह कि विवेकानन्द निधि, कलकत्ता वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए उसके द्वारा प्राप्त राशियों का पृथक लेखा रखेगा।

2. यह कि उक्त संस्थान अपने वैज्ञानिक अनुसंधान संबंधी क्रियाकलापों की वार्षिक विवरणी, विहित प्राधिकारी को प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संबंध में प्रति वर्ष 30 अप्रैल तक, ऐसे प्ररूप में प्रस्तुत करेगा जो इस प्रयोजन के लिए अधिकथित किया जाए और उसे सूचित किया जाए।

3. यह कि उक्त संस्थान अपनी कुल आय तथा व्यय दर्शाते हुए अपने संपरीक्षित वार्षिक लेखों की तथा अपनी परिसंपत्तियाँ, देनदारियाँ दर्शाते हुए तुलन-पत्र की एक-एक प्रति, प्रतिवर्ष 30 जून तक विहित प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगा तथा इन दस्तावेजों में से प्रत्येक की एक-एक प्रति संबंधित आयकर आयुक्त को भेजेगा।

संस्था

"विवेकानन्द निधि, कलकत्ता"

यह अधिसूचना 19-8-1984 से 31-3-1985 तक के लिए प्रभावी है।

[(सं. 6059 (फा. सं. 203/205/84-आ. क. नि.-II)]

S.O. 6.—In continuation of this Office Notification No. 4169 (F. No. 203/61/81-ITA. II) dated 19-8-1981, it is hereby notified for general information that the institution mentioned below has been approved by Department of Science and Technology, New Delhi, the prescribed authority for the purposes of clause (iii) of sub-section (1) of Section 35 of the Income-tax Act, 1961 read with Rule 6 of the Income-tax Rules, 1962 under the category "Institution" subject to the following conditions :—

(i) That the Vivekananda Nidhi, Calcutta will maintain a separate account of the sums received by it for scientific research.

(ii) That the said Institute will furnish annual returns of its scientific research actiivties to the Prescribel Authority for every financial year in such forms as may be laid down and intimated to them for this purpose by 30th April each year.

(iii) That the said Institute will submit to the Prescribed Authority by 30th June each year a copy of their audited annual accounts showing their total income and expenditure and balance sheet showing its assets and liabilities with a copy of each of these documents to the concerned Commissioner of Income-tax.

INSTITUTION

"Vivekananda Nidhi, Calcutta".

This notification is effective for a period from 19-8-1984 to 31-3-1985.

[No. 6059 (F. No. 203/205/84-ITA. II)]

का. आ. 7 :— इस कार्यालय की दिनांक 31-10-1981 की अधिसूचना सं. 4287 (फा. सं. 203/138/81-आ. क. नि.-II) के सिलसिले में, सर्वसाधारण की जानकारी के लिए एतद्द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि विहित प्राधिकारी, अर्थात् विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, नई दिल्ली ने निम्नलिखित संस्था को आयकर नियम, 1962 के नियम 6 के साथ पठित आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 की उपधारा (1) के खंड (ii) के प्रयोजनों के क्षेत्र में "संस्था" प्रवर्ग के अधीन निम्नलिखित शर्तों पर अनुमोदित किया है, अर्थात् :—

1. यह कि दि टाइम्स रिसर्च फाउण्डेशन, नई दिल्ली वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए उसके द्वारा प्राप्त राशियों का पृथक लेखा रखेगा।

2. यह कि उक्त संस्थान अपने वैज्ञानिक अनुसंधान संबंधी क्रियाकलापों की वार्षिक विवरणी, विहित प्राधिकारी को प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संबंध में प्रति वर्ष 30 अप्रैल, तक ऐसे प्ररूप में प्रस्तुत करेगा जो इस प्रयोजन के लिए अधिकथित किया जाए और उसे सूचित किया।

3. यह कि उक्त संस्थान अपनी कुल आय तथा व्यय दर्शाते हुए अपने संपरीक्षित वार्षिक लेखों की तथा अपनी परिसंपत्तियाँ, देनदारियाँ दर्शाते हुए तुलन-पत्र की एक-एक प्रति, प्रतिवर्ष 30 जून तक विहित प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगा तथा इन दस्तावेजों में से प्रत्येक की एक-एक प्रति संबंधित आयकर आयुक्त को भेजेगा।

संस्था

"दि टाइम्स रिसर्च फाउण्डेशन, नई दिल्ली"

यह अधिसूचना 1-4-1984 से 31-3-1986 तक के लिए प्रभावी है।

[सं० 6058 (फा० सं० 203/88/84-आ०क०नि०-II)]

S.O. 7.—In continuation of this Office Notification No. 4287 (F. No. 203/138/81-ITA. II) dated 31-10-1981, it is hereby notified for general information that the institution mentioned below has been approved by Department of Science and Technology, New Delhi, the prescribed authority for the purposes of clause (iii) of sub-section (1) of Section 35 of the Income-tax Act, 1961 read with Rule 6 of the Income-tax Rules, 1962 under the category "Institute" subject to the following conditions :—

(i) That The Times Research Foundation, New Delhi will maintain a separate account of the sums received by it for scientific research.

(ii) That the said Institute will furnish annual returns of its scientific research activities to the Prescribed Authority for every financial year in such forms as may be laid down and intimated to them for this purpose by 30th April each year.

(iii) That the said Institute will submit to the Prescribed Authority by 30th June each year a copy of their audited annual accounts showing their total income and expenditure and balance sheet showing its assets and liabilities with a copy of each of these

documents to the concerned Commissioner of Income-tax.

INSTITUTION

"The Times Research Foundation, New Delhi".

This notification is effective for a period from 1-4-1984 to 31-3-1986.

[No. 6058 (F. No. 203/88/84-ITA. II)]

का.आ. . . . . 8.—इस कार्यालय की दिनांक 4-10-1982 की अधिसूचना सं. 4932 (फा.सं. 203/50/82-आ.क.नि.-II) के सिलसिले में, सर्वसाधारण की जानकारी के लिए एतद्द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि विहित प्राधिकारी, अर्थात् विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, नई दिल्ली ने निम्नलिखित संस्था को आयकर नियम, 1962 के नियम 6 साथ पठित आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 की उपधारा (1) के खंड (ii) के प्रयोजनों के लिए "संस्था" प्रवर्ग के अधीन निम्नलिखित शर्तों पर अनुमोदित किया है, अर्थात्:—

1. यह कि सामाजिक अनुसंधान केन्द्र, नई दिल्ली, अपने वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए उसके द्वारा प्राप्त राशियों का पृथक् लेखा रखेगा।

2. यह कि उक्त केन्द्र अपने वैज्ञानिक अनुसंधान संबंधी क्रियाकलापों की वार्षिक विवरणी, विहित प्राधिकारी को प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संबंध में प्रति वर्ष 30 अप्रैल, तक ऐसे प्ररूप में प्रस्तुत करेगी जो इस प्रयोजन के लिए अधिकथित किया जाये और उसे सूचित किया जाए।

3. यह कि उक्त केन्द्र अपनी कुल आय तथा व्यय दर्शाते हुए अपने संपरीक्षित वार्षिक लेखों की तथा अपनी परिसंपत्तियां, देनदारियां दर्शाते हुए तुलन-पत्र की एक-एक प्रति, प्रतिवर्ष 30 जून तक विहित प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगी तथा इन दस्तावेजों में से प्रत्येक की एक-एक प्रति संबंधित आयकर आयुक्त को भेजेगा।

संस्था

"सामाजिक अनुसंधान केन्द्र, नई दिल्ली।"

यह अधिसूचना 16-9-1983 से 31-3-1986 तक की अवधि के लिए प्रभावी है।

[सं. 6060 (फा.सं. 203/192/83-आ.क.नि.-II)]

S.O. 8.—In continuation of this Office Notification No. 4932 (F. No. 203/50/82-ITA. II) dated 4-10-1982, it is hereby notified for general information that the institution mentioned below has been approved by Department of Science and Technology, New Delhi, the prescribed authority for the purposes of clause (iii) of sub-section (1) of Section 35 of the Income-tax Act, 1961, read with Rule 6 of the Income-tax Rules, 1962 under the category "Institution" subject to the following conditions :—

(i) That the Centre For Social Research, New Delhi will maintain a separate account of the sums received by it for scientific research.

(ii) That the said Centre will furnish annual returns of its scientific research activities to the Prescribed Authority for every financial year in such forms as may be laid down and intimated to them for this purpose by 30th April each year.

(iii) That the said Centre will submit to the Prescribed Authority by 30th June each year a copy of their audited annual accounts showing their total income and expenditure and balance sheet showing its assets and liabilities with a copy of each of these documents to the concerned Commissioner of Income-tax.

INSTITUTION

"Centre for Social Research, New Delhi."

This notification is effective for a period from 16-9-1983 to 31-3-1986.

[No. 6060 (F. No. 203/192/83-ITA. II)]

नई दिल्ली, 15 दिसम्बर, 1984

का.आ. . . . 9.—इस कार्यालय की दिनांक 3-6-1981 की अधिसूचना सं. 4007 (फा.सं. 203/69/79-आ० क० नि०-II) के सिलसिले में, सर्वसाधारण की जानकारी के लिए एतद्द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि विहित प्राधिकारी, अर्थात विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, नई दिल्ली के निम्नलिखित संस्था को आयकर नियम, 1962 के नियम 6 के साथ पठित आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 की उपधारा (1) के खंड (ii) के प्रयोजनों के क्षेत्र में "संस्था" प्रवर्ग के अधीन निम्नलिखित शर्तों पर अनुमोदित किया है, अर्थात:—

1. यह कि संगीत महाभारती, बम्बई वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए उसके द्वारा प्राप्त राशियों का पृथक लेखा रखेगा।

2. अनुमोदन अवधि के दौरान, आयकर अधिनियम की धारा 35 (1) (ii) के अधीन एकत्रित दान की राशियों को, जयारी प्रोसैसिंग टैक-नीक, टेबल स्याही एप्लिकेशन टैकनीक और रिवर्स एप्लिकेशन टैकनीक, सीअरिंग प्रोसैस फार इन्स्ट्रूमेंट, और इलैक्ट्रोनिक मैट्रोनोम, आदि जैसी वैज्ञानिक अनुसंधान परियोजनाओं को पूरा करने के लिए खर्च किया जाएगा।

3. यह कि उक्त संस्था अपने वैज्ञानिक अनुसंधान संबंधी क्रियाकलापों की वार्षिक विवरणी, विहित प्राधिकारी को प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संबंध में प्रति वर्ष 30 अप्रैल तक ऐसे प्ररूप में प्रस्तुत करेगी जो इस प्रयोजन के लिए अधिकथित किया जाए और उसे सूचित किया जाए।

4. यह कि उक्त संस्था अपनी कुल आय तथा व्यय दर्शाते हुए अपने संपरीक्षित वार्षिक लेखों की तथा अपनी परिसंपत्तियां, देनदारियां दर्शाते हुए तुलना-पत्र की एक-एक प्रति, प्रतिवर्ष 30 जून तक विहित प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगी तथा इन दस्तावेजों में से प्रत्येक की एक-एक प्रति संबंधित आयकर आयुक्त को भेजेगा।

संस्था

"संगीत महाभारती, बम्बई"

यह अधिसूचना 7-3-1984 से 31-3-1985 तक के लिए प्रभावी है।

[सं. 6073 (फा.सं. 203/74/83-आ.क.नि.II)]

गिरीश दवे, अवर सचिव

New Delhi, the 15th December, 1984

S.O. 9.—In continuation of this Office Notification No. 4007 (F. No. 203/69/79 ITA. II) dated 3-6-1981, it is hereby notified for general information that the Institution mentioned below has been approved by Department of Science & Technology, New Delhi the Prescribed Authority for the purposes of clause (ii) of sub-section (1) of Section 35 of the Income-tax Act, 1961 read with Rule 6 of the Income-tax Rules, 1962 under the category "Institution" subject to the following conditions :—

(i) That the Sangit Mahabharati, Bombay will maintain a separate account of the sums received by it for scientific research.

(ii) That the collected donations under section 35(1)(ii) of the Income-tax Act during the period of approval will be spent for carrying out scientific research projects such as Jawari Processing Technique, Table Syahi application technique & reverse application technique, Seasoning process for instrument, and Electronics Metronome etc.

(iii) That the said Institution will furnish annual returns of its scientific research activities to the Prescribed Authority for every financial year in such forms as may be laid down and intimated to them for this purpose by 30th April each year.

(iv) That the said Institution will submit to the Prescribed Authority by 30th June each year a copy of their audited annual accounts showing their total income and expenditure and balance sheet showing its assets and liabilities with a copy of each of these documents to the concerned Commissioner of Income-tax.

INSTITUTION

Sangit Mahabharati, Bombay".

This notification is effective for a period from 7-3-1984 to 31-3-1985.

[No. 6073 (F. No. 203/74/83 ITA. II)]
GIRISH DAVE, Under Secy.

नई दिल्ली, 20 दिसम्बर, 1984

आयकर

का. आ. 10.—आयकर अधिनियम, 1961 (1961का43) की धारा 2 के खण्ड (44) के उपखण्ड (iii) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा श्री के.सी. श्रीमाली को, जो केन्द्रीय सरकार के राजपत्रित अधिकारी है, उक्त अधिनियम के अंतर्गत कर वसूली अधिकारी की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करती है।

यह अधिसूचना, श्री के. सी. श्रीमाली द्वारा कर वसूली अधिकारी के रूप में कार्यभार ग्रहण किए जाने की तारीख 8-10-1984 से लागू होगी।

[सं. 6077/फा.सं. 398/9/83-आ.क. (ब.)]

New Delhi, the 20th December, 1984

INCOME-TAX

S.O. 10.—In pursuance of sub-clause (iii) of clause (44) of section 2 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby authorises Shri K. C. Shrimali being a gazetted Officer of the Central Government to exercise the powers of a Tax Recovery Officer under the said Act.

2. This Notification shall come into force with effect from 8-10-1984 when Shri K. C. Shrimali took over charge as Recovery Officer.

[No. 6077/F. No. 398/9/83-IT(B)]

का.आ. 11.—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 2 के खण्ड (44) के उपखण्ड (iii) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा श्री आर.एस. पारीख को, जो केन्द्रीय सरकार के राजपत्रित अधिकारी हैं, उक्त अधिनियम के अंतर्गत कर वसूली अधिकारी की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करती है।

2. यह अधिसूचना, श्री आर.एस. पारीख द्वारा कर वसूली अधिकारी के रूप में कार्यभार ग्रहण किए जाने की तारीख 12-10-84 से लागू होगी।

[सं० 6079(फा०सं०398/9/83-आ०क०ब०)]
बी०ई० अलैक्जैंडर, अवर सचिव

S.O. 11.—In pursuance of sub-clause (iii) of clause (44) of section 2 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby authorises Shri R. S. Pareekh being a gazetted Officer of the Central Government to exercise the powers of a Tax Recovery Officer under the said Act.

2. This Notification shall come into force with effect from 12-10-84 when Shri R. S. Pareekh took over charge as Recovery Officer.

[No. 6079/F. No. 398/9/83-IT(B)]
B. E. ALEXANDER, Under Secy.

(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

नई दिल्ली, 14 सितम्बर, 1984

आयकर

का. आ. 12.—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 122 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा इस संबंध में ऐसे समर्थ बनाने वाली अन्य सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इस संबंध में पूर्ववर्ती सभी अधिसूचनाओं के अधिलंघन में केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड एतद्द्वारा निदेश देता है कि नीचे दी गई अनुसूची के स्तम्भ 2 में विनिर्दिष्ट रेंजों के अपीलीय सहायक आयकर आयुक्त, ऐसे सभी व्यक्तियों और आय को छोड़कर, जिनके आयकर निर्धारण का क्षेत्राधिकार आयकर आयुक्त (अपील) में निहित है, उक्त अनुसूची के स्तम्भ 3 की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट आयकर परिमंडलों, वार्डों और जिलों में आयकर और अधिकार से निर्धारित सभी व्यक्तियों और आय के संबंध में अपने कार्यों का निर्वहन करेंगे :—

अनुसूची

क्रमांक	रेंज	आयकर परिमंडल, वार्ड, जिले
1	2	3
1.	अपीलीय सहायक आयकर आयुक्त, अ–रेंज लखनऊ	1. बाराबंकी 2. उन्नाव 3. केन्द्रीय परिमंडल–i, ii और iii, लखनऊ 4. पुराना परिमंडल i, लखनऊ 5. पुराना परिमंडल ii, लखनऊ 6. सम्पदा शुल्क एवम आयकर परि–मंडल, लखनऊ (पुरानी अपीलें); और 7. उ वार्ड, ऊ– वार्ड लखनऊ परि–मंडल, लखनऊ और आयकर अधि–कारी (वसूली) लखनऊ परिमंडल, लखनऊ।
2.	अपीलीय सहायक आयकर आयुक्त, आ– रेंज, लखनऊ	1. राय बरेली, और 2. अ, आ, इ और ई वार्ड, लखनऊ परिमंडल, लखनऊ।
3.	अपीली सहायक आयकर आयुक्त बरेली रेंज बरेली	1. बरेली परिमंडल, बरेली 2. आयकर कार्यालय, हल्द्वानी 3. इ–वार्ड, परिमंडल–ii, मुरादाबाद और प्रधान कार्यालय बरेली में। 4. केन्द्रीय परिमंडल, बरेली। 5. नैनीताल 6. पीलीभीत 7. बदायूं और 8. अ और आ वार्ड, शाहजहांपुर।
4.	अपीलीय सहायक आयकर आयुक्त, सीतापुर रेंज सीतापुर।	1. सीतापुर 2. लखीमपुर– खीरी 3. हरदोई 4. वेतन परिमंडल, लखनऊ और 5. लखनऊ परिमंडल के वार्ड i और ii, लखनऊ

1	2	3
5.	अपीलीय सहायक आयकर आयुक्त, मुरादाबाद रेंज, मुरादाबाद ।	1. परिमंडल-i, मुरादाबाद 2. परिमंडल-ii, मुरादाबाद (राय बरेली में प्रधान कार्यालय सहित ए वार्ड, परिमंडल ii, मुरादाबाद को छोड़कर) 3. पिथौरागढ़ 4. रामपुर 5. चन्दौसी
6.	अपीलीय सहायक आयकर आयुक्त, नजीबाबाद रेंज, नजीबाबाद ।	1. नजीबाबाद 2. बिजनौर 3. सम्भल 4. अल्मोड़ा, और 5. काशीपुर

जहां कोई आयकर परिमंडल वार्ड या जिला अथवा कोई भाग इस अधिसूचना द्वारा एक रेंज से किसी अन्य रेंज में अन्तरित कर दिया जाता है, वहां उस आयकर परिमंडल, वार्ड अथवा जिले या उसके किसी भाग में किए गए कर निर्धारणों से उत्पन्न होने वाली अपीलें, अपीलीय सहायक आयुक्त रेंज, जिसके अधिकार क्षेत्र से उस आयकर परिमंडल, वार्ड अथवा जिला या उसका कोई भाग अन्तरित किया गया है, इस अधिसूचना के लागू होने की तारीख से रेंज के उस अपीलीय सहायक आयुक्त को अन्तरित की जाएगी और उसके द्वारा निपटाली जाएगी, जिसके अधिकार क्षेत्र में उक्त परिमंडल, वार्ड या जिला या उसका कोई भाग अन्तरित किया गया है ।

यह अधिसूचना 1-9-84 से लागू होगी ।

[संख्या 5985(फा. सं. 261/15/84- आ. क. न्या.]

CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES

New Delhi, the 14th September, 1984

INCOME TAX

S.O. 12 .—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 122 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) and of all other powers enabling it in that behalf and in supersession of all previous notifications in this regard the Central Board of Direct Taxes hereby directs that Appellate Assistant Commissioner of Income-tax of the Ranges specified in Column 2 of the Schedule below shall perform their functions in respect of all persons and income assessed in income-tax and Super-tax in the Income-tax Circles, Wards and Districts specified in the correspondence entry in Column 3 thereof excluding all persons and incomes assessed to Income-tax over which the jurisdiction vest in Commissioner of Income-tax (Appeals):

SCHEDULE

S. No.	Ranges	Income-tax Circle, Wards, Districts
1	2	3
1.	Appellate Assistant Commissioner of Income-tax, A-Range, Lucknow.	1. Barabanki 2. Unnao 3. Central Circle I, II & III, LKO. 4. Old Circle I, Lucknow. 5. Old CircleII,Lucknow. 6. Estate Duty-cum-Income-tax Circle, Lucknow (Old appeals); & 7. E-Ward, F-Ward, Lucknow Circle Lucknow and ITO (Recovery) Lucknow Circle, Lucknow.
2.	Appellate Assistant Commissioner of Income-tax, B-Range Lucknow.	1. Rae-Bareli; & 2. A.B.C & D Wards, Lucknow Circle, Lucknow.
3.	Appellate Assistant Commissioner of Income-tax, Bareilly Range, Bareilly	1. Bareilly Circle, Bareilly. 2. I.T.O. Office, Haldwani. 3. C-Ward, Circle II, Moradabad with Headquarters at Bareilly 4. Central Circle, Bareilly 5. Nainital 6. Pilibhit 7. Budaun & 8. A & B Wards, Shahjanpur.
4.	Appellate Assistant Commissioner of Income-tax, Sitapur Range, Sitapur.	1. Sitapur 2. Lakhimpur-Kheri 3. Hardoi 4. Salary Circles, Lucknow & 5. Ward I & II of Lucknow Circle, Lucknow.
5.	Appellate Assistant Commissioner of Income-tax, Moradabad Range, Moradabad	1. Circle I, Moradabad 2. Circle II, Moradabad (excluding C-Ward, Circle II, Moradabad with Headquarters at Bareilly) 3. Pithoragarh 4. Rampur 5. Chandausi.
6.	Appellate Assistant Commissioner of Income-tax, Najibabad Range, Najibabad	1. Najibabad 2. Bijnor 3. Sambhal 4. Almora & 5. Kashipur.

Whereas an Income-tax Circle, Ward or District or part thereof stands transferred by this Notificatiion from one range to another range, appeals arising out of the assessments made in that Income-tax Circles, Ward or Districts or part thereof and the Appellate Assistant Commissioner of the Range from whom that Income-tax Circle, Ward or District or part thereof is transferred shall from the date this Notification takes effect be transferred to and dealt with by the Appellate Assistant Commissioner of the Range to whom the said Circle, Ward or District or part thereof is transferred.

This Notification shall take effect from 1-9-1984.

[No. 5985(F.No. 261/15/84-ITJ]

का. आ. 13.—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 121 अ के उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और दिनांक 5-11-81 के आदेश संख्या 4296 तथा दिनांक 7-3-84 के आदेश संख्या 5673 तथा दिनांक 21-7-83 की अधिसूचना संख्या 5321 का संशोधन करते हुए केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड एतद्द्वारा निदेश देता है कि नीचे दी गई अनुसूची के स्तम्भ (1) में विनिर्दिष्ट अधिकार-क्षेत्रों के आयकर आयुक्त (अपील) अनुसूची के स्तम्भ (2) और (3) की तत्संबंधी प्रविष्टियों में विनिर्दिष्ट आयकर वार्डों, परिमंडलों, जिलों और रेंजों में ऐसे व्यक्तियों के संबंध में अपने कार्य करेंगे जिन पर आयकर या अतिकर या ब्याजकर लगाया गया हो और जो आयकर अधिनियम, 1961 के धारा 246 की उपधारा (2) के खण्ड

(क) से (ज) में, कंपनी (लाभ) अतिकर अधिनियम, 1964 (1964 का 7) की धारा 11 की उपधारा (1) में और ब्याज कर अधिनियम 1974 (1974 का 43) की धारा 15 की उपधारा (1) में उल्लिखित किसी भी आदेश से व्यथित हुए हैं और ऐसे व्यक्तियों के वर्गों की बाबत भी कार्य करेंगे जिनके लिए बोर्ड ने आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 246 की उपधारा (2) के खण्ड (1) के उपबंधों के अनुसार निदेश दिया है या भविष्य में निदेश दें।

अनुसूची

अधिकार-क्षेत्र और प्रधान कार्यालय	आयकर वार्ड/परिमंडल और जिला	निरीक्षी सहायक आयकर आयुक्तों की रेंज
1	2	3
आयकर आयुक्त, (अपील) 1, मद्रास	1. सिटी परिमंडल, II, मद्रास, (सभी अनुभाग)	1. नि. स. आ. की रेंज-1, मद्रास
	2. कंपनी परिमंडल 2, मद्रास (सभी अनुभाग)	1. नि. सं. आ., रेंज-1 मद्रास
	3. त्रिरुचिरापल्ली, परिमंडल, त्रिरुचिरापल्ली (भूतपूर्व परिमंडल) 4. सिटी परिमंडल 1, त्रिरुची (सभी अनुभाग) 5. सिटी परिमंडल II, त्रिरुची (सभी अनुभाग) 6. कंपनी परिमंडल, त्रिरुची 7. करूर परिमंडल (सभी अनुभाग). 8. पुदुकोट्टई परिमंडल, (सभी अनुभाग) 9. नि. स. आ. (कं. नि.) रेंज-II, मद्रास	नि. स. आ०, त्रिरुचिरापल्ली रेंज त्रिरुची
आयकर आयुक्त (अपील) कोयम्बतूर	1. सिटी परिमंडल, कोयम्बतूर (सभी अनुभाग) 2. कंपनी परिमंडल-III, कोयम्बतूर 3. कोयम्बतूर परिमंडल, कोयम्तूर (भूतपूर्व मंडल) 4. परिमंडल-1 कोयम्बतूर (भूतपूर्व परिमंडल) 5. वेतन परिमंडल, कोयम्बतूर 6. उटामंड परिमंडल, (सभी अनुभाग)	नि. स. आ., रेंज-1, कोयम्बतूर
	7. सिटी परिमंडल-II, कोयम्बतूर (सभी अनुभाग) 8. कंपनी परिमंडल, I, II और IV कोयम्बतूर 9. पोलाची परिमंडल, (सभी अनुभाग) 10. तिरुप्पूर परिमंडल (सभी अनुभाग) 11. परिमंडल-II, कोयम्बतूर (भूतपूर्व परिमंडल)	नि. स. आ., रेंज-II, कोयम्बतूर
	12. सिटी परिमंडल, III, कोयम्बतूर (सभी अनुभाग) 13. कंपनी परिमंडल V, कोयम्बतूर 14. विशेष सर्वेक्षण परिमंडल, कोयम्बतूर 15. विशेष जांच परिमंडल, कोयम्बतूर 16. इरोड परिमंडल (सभी अनुभाग)	नि. स. आ. रेंज रेंज-III कोयम्बतूर
	17. कोयम्बतूर में सभी केन्द्रीय परिमंडल 18. नि. स. आ. (क. नि.) रेंज I और II, कोयम्बतूर	नि. स. आ. केन्द्रीय रेंज-II [illegible]
	19. परिमंडल, I सेलम, (सभी अनुभाग) 20. परिमंडल II, सेलम (सभी अनुभाग) 21. कंपनी परिमंडल, सेलम 22. सेलम परिमंडल (भूतपूर्व परिमंडल) 23. कृष्णागिरी परिमंडल	नि. सं. आ. सेलम

यत: कोई आयकर परिमंडल, वार्ड अथवा जिला अथवा रेंज अथवा उसका कोई भाग इस अधिसूचना द्वारा एक अधिकार क्षेत्र से किसी अन्य अधिकार क्षेत्र में अन्तरित कर दिया गया है, वहां उस आयकर परिमंडल वार्ड अथवा जिले या रेंज अथवा उसके किसी भाग में किए गए कर-निर्धारणों से उत्पन्न होने वाली और इस अधिसूचना की तारीख से तत्काल पूर्व उस अधिकार क्षेत्र के आयकर आयुक्त (अपील) के समक्ष विचाराधीन पड़ी अपीलें जिसके क्षेत्राधिकार से वह आयकर परिमंडल, वार्ड या जिला या रेंज अथवा उसका कोई भाग अन्तरित किया गया है, इस अधिसूचना के लागू होने की तारीख से उस आयकर आयुक्त (अपील) के अधिकार क्षेत्र को अन्तरित की जाएंगी और उसके द्वारा निपटायी जाएंगी, जिसके अधिकार क्षेत्र में उक्त परिमंडल, वार्ड या जिला अथवा रेंज अथवा उसका कोई भाग अन्तरित कर दिया गया है।

यह अधिसूचना 1.9.84 से लागू होगी।

[सं. 5986 (फा. सं. 261/16/84-आ. क. न्या.)]

S.O.13.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 121A of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) and in modification of order No. 4296 dated 5-11-81 and order No. 5673 dated 7-3-84 and Notification No. 5321 dated 21-7-83, the Central Board of Direct Taxes hereby directs that the Commissioner of Income-tax (Appeals) of the charges specified in column (1) of the Schedule below, shall perform their functions in respect of such persons assessed to Income-tax or Surtax or Interest tax in the Income-tax Wards, Circles, Districts and Ranges specified in the corresponding entries in column (2) and column (3) thereof as are aggrieved by any of the orders mentioned in clauses (a) to (h) of sub-section (2) of section 246 of the Income-tax Act, 1961, in sub-section (1) of section 11 of the Companies (Profits) Surtax Act, 1964 (7 of 1964) and in sub-section (1) of the section 15 of the Interest Tax Act, 1974 (45 of 1974) and also in respect of such persons and in clauses of persons as the Board has directed or may direct in future in accordance with the provisions of clauses (i) of sub-section (2) of Section 246 of the Income-tax Act, 1961.

SCHEDULE

Charges with H.Qrs.	I.T. Wards/Circles & District	Range of IACs of Income-tax
1	2	3
City (Appeals) VI Madras.	1. City. Cir. VII, Mds. (All Sections)	1. IAC Range IV, Mds.
	2. Company Cir. VII, Mds. (All Sections)	2. IAC. Range I, Mds.
	3. Tiruchirapalli Circle, Tiruchirapalli. (Erstwhile circle)	IAC, Tiruchirapalli, Range, Tiruchy.
	4. City. Cir. I Tiruchy (All Sections)	
	5. City. Cir. II, Tiruchy (All Sections)	
	6. Company Circle, Tiruchy	
	7. Karur Circle, (All Sections	
	8. Pudukottai Circle, (All Sections)	
	9. IAC (Asst) Range-II Madras.	
CIT (Appeals) Coimbatore	1. City Cir. I, Coimbatore (All Sections)	IAC, Range-I, Coimbatore.
	2. Company Cir. III, Coimbatore.	
	3. Coimbatore Circle, Coimbatore (Erstwhile Cir.)	
	4. Circle I, Coimbatore (Erstwhile Circle)	
	5. Salary Circle, Coimbatore.	
	6. Ootacamund Circle, (All Sections).	
	7. City Cir. II, Coimbatore (All Sections)	IAC, Range-II, Coimbatore.
	8. Company Cir. I, II & IV, Coimbatore.	
	9. Pollachi Circle (All Sections)	
	10. Tiruppur Circle (All Sections)	
	11. Circe II, Coimbatore (Erstwhile Circle)	
	12. City Cir. III, Coimbatore (All Sections)	IAC, Range-III, Coimbatore
	13. Company Circle V, Coimbatore	
	14. Spl. Survey Circle, Coimbatore	
	15. Spl. Inv. Circle, Coimbatore	
	16. Erode Circle, (All Sections)	
	17. All Central Circles at Coimbatore.	IAC, Central Range-II, Madras
	18. IAC (Asst) Range I & II Coimbatore.	
	19. Circle I, Salem (All Sections)	IAC, Salem.
	20. Circle II, Salem (All Sections)	
	21. Company Circle, Salem	
	22. Salem Circle (Erstwhile Circle)	
	23. Krishnagiri Circle	

Whereas the Income-tax Circle, Ward or District or Range or part thereof stands transferred by this Notification from one charge to anotther charge appeals arising out of the assessments made in that Income-tax Circle, Ward or District or Range or part thereof and pending immediately before the date of this Notification before the Commissioner of Income-tax (Appeals) of the charge from whom that Income-tax Circle, Ward or District or range or part thereof is transferred shall from the date of this Notification takes effect, be transferred to and dealt with by the Commissioner of Income-tax (Appeals) of the charge to whom the said Circle, Ward or District or Range or part thereof is transferred.

This notification shall take effect from 1-9-84.

[No. 5986 (F.No. 261/16/84-ITJ)]

का.आ. 14.— आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 121 अ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा पूर्ववर्ती सभी आदेशों का अतिलंघन करते हुए केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड एतद्द्वारा निदेश देता है कि नीचे दी गई अनुसूची के स्तम्भ (1) में विनिर्दिष्ट अधिकार-क्षेत्रों के आयकर आयुक्त (अपील) अनुसूची के स्तम्भ संख्या (2) और (3) की तत्संबंधी प्रविष्टियों में विनिर्दिष्ट आयकर वार्डों, परिमण्डलों, जिलों और रेंजों में ऐसे व्यक्तियों के संबंध में अपने कार्य करेंगे, जिन पर आयकर या अतिकर या ब्याजकर लगाया गया हो और जो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 246 की उपधारा (2) के खण्ड (क) से (ञ) में, कंपनी (लाभ) अतिकर अधिनियम 1964 (1964 का 7) की धारा 11 की उपधारा (1) में और ब्याज कर अधिनियम, 1974 (1974 का 45) की धारा 15 की उपधारा (1) में उल्लिखित किसी भी आदेश से व्यथित हुए हैं और ऐसे व्यक्तियों या व्यक्तियों के वर्गों की बाबत भी कार्य करेंगे, जिनके लिए बोर्ड ने आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 246 की उपधारा (2) के खण्ड (1) के उपबंधों के अनुसार निदेश दिया है या भविष्य में निदेश दे।

अनुसूची

अधिकार-क्षेत्र और प्रधान कार्यालय	आयकर वार्ड, परिमण्डल और जिले	नि. स. आ. की रेंज
1	2	3
आयकर आयुक्त (अ) कालीकट	1. आ.क. परिमण्डल, त्रिचुर	नि. स. आ., त्रिचूर रेंज
	2. अ.क. परिमण्डल, पालघाट	—यथोपरि—
	3. आ.क. परिमण्डल-1, कालीकट	नि. स. आ., कालीकट रेंज
	4. आ. क. परिमण्डल-II	—यथोपरि—
	5. अ. क. परिमण्डल, कन्नोनौर	—यथोपरि—
	6. अ.क. परिमण्डल, कासरगाड़	नि.स. आ. (केन्द्रीय) एर्णाकुलम
	7. केन्द्रीय परिमण्डल, कालीकट	नि. स. आ. (केन्द्रीय) एर्णाकुलम
	8. निरीक्षी सहायक आयकर आयुक्त कर-निर्धारण रेंज	त्रिचुर
आयकर आयुक्त (अ) एर्णाकुलम	1. आ.क. परिमण्डल, अलार्य	नि. स. आ. त्रिचूर रेंज नि. सं० आ० (केन्द्रीय) एर्णाकुलम
	2. केन्द्रीय परिमण्डल, एर्णाकुलम	
	3. विशेष परिमण्डल, एर्णाकुलम	नि. स. आ., एर्णाकुलम रेंज
	4. अ.क. परिमण्डल, एर्णाकुलम	—यथापरि—
	5. कंपनी परिमण्डल, एर्णाकुलम	—यथोपरि—

	6. आ. क. परिमण्डल एर्णाकुलम	—यथोपरि—
	7. सर्वेक्षण परिमण्डल, एर्णाकुलम	नि. सं० आ. (अधिग्रहण), एर्णाकुलम
	8. वेतन परिमण्डल, एर्णाकुलम	नि. सं० आ. एर्णाकुलम रेंज
	9. नि. सं० आयकर आयुक्त कर-निर्धारण रेंज	एर्णाकुलम
आयकर आयुक्त (अ) त्रिवेन्द्रम	1. आ. क. परिमण्डल, त्रिवेन्द्रम,	त्रिवेन्द्रम रेंज नि. स. आ.
	2. वेतन परिमण्डल, त्रिवेन्द्रम	-यथोपरि-
	3. आयकर परिमण्डल, एलेप्पी	-यथोपरि-
	4. आ. क. परिमण्डल, कोट्टायाम	-यथोपरि-
	5. आ. क. परिमण्डल, तिरुवल्ला	-यथोपरि-
	6. आ. क. परिमण्डल क्विलोन,	-यथोपरि-
	7. केन्द्रीय परिमण्डल, त्रिवेन्द्रम	नि. स. आ. (केन्द्रीय) एर्णाकुलम

जहां कोई आयकर वार्ड, परिमण्डल अथवा जिला अथवा उसका कोई भाग, इस अधिसूचना द्वारा एक अधिकार-क्षेत्र में अन्तरित कर दिया गया है, वहां उस आयकर वार्ड, परिमण्डल या जिला या उसके किसी भाग में किए गए कर-निर्धारणों से उत्पन्न होने वाली और इस अधिसूचना की तारीख से तत्काल पूर्व उस अधिकार क्षेत्र के अपीलीय सहायक आयकर आयुक्त के समक्ष विचाराधीन पड़ी अपीलें, जिसके अधिकार-क्षेत्र से आयकर परिमण्डल, वार्ड या जिला या उसका कोई भाग अन्तरित किया गया है इस अधिसूचना के लागू होने की तारीख से उस आयकर आयुक्त अधिकार क्षेत्र को अन्तरित की जाएंगी और उसके द्वारा निपटाई जाएंगी जिसके अधिकार-क्षेत्र में उक्त परिमण्डल, वार्ड या उसका कोई भाग अन्तरित किया गया है।

यह अधिसूचना 1-9-84 से लागू होगी।

[सं. 5987 (फा. सं. 261/10/84-आ. क. न्या०)]

S.O. 14—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 121A of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) and in supersession of all the earlier orders, the Central Board of Direct Taxes hereby directs that the Commissioner of Income tax (Appeals) of the changes specified in column No. 1 of the Schedule below shall perform their functions in respect of such persons assessed to Incometax or Surtax or Interest tax on the Income-tax Wards, Circles, Districts and Ranges specified in the corresponding entries in column No. 2 and column 3 thereof as are aggrieved by any of the orders mentioned in clauses (a) to (h) of sub-sections (2) of section 246 of the Income-tax Act' 1961, in sub-section (i) of section II of Companies (Profits) Surtax Act, 1961 (7 of 1961) and in sub-section (1) of Section 15 of the Interest-tax Act, 1974 (45 of 1974) and also in respect of such persons or classes of persons as the Board may direct in future in accordance with the provisions of clause (1) of sub-section (2) of section 246 of the Income-tax Act, 1961.

SCHEDULE

Charges with H.Qrs.	Income-tax Wards, Circles, and Districts.	Ranges of IACs
1	2	3
Commissioner of Income-tax (A), Calicut.	1. IT Circle, Trichur	IAC, Trichur Range
	2. IT Circle, Palghat	-do-
	3. IT Circle-I, Calicut	IAC, Calicut Range
	4. IT Circle-II, Calicut	-do-
	5. IT Circle, Cannanore	-do-
	6. IT Circle, Kasargod	-do-
	7. Central Circle, Calicut	IAC (Central) EKm
	8. IAC of IT, Asst. Range.	Trichur
Commissioner of Income-tax (A) Ernakulam	1. IT Circle, Alway	IAC Trichur Range
	2. Central Circle, Ekm.	IAC (Central) Ekm.
	3. Special Circle, Ekm.	IAC, Ernakulam Range
	4. IT Circle, Ekm.	-do-
	5. Companies Cir. Ekm.	-do-
	6. IT Circle Ekm	-do-
	7. Survey Circle, Ekm.	IAC (Acqn) Ekm.
	8. Salary Circle, Ekm.	IAC, Ernakulam
	9. IAC of IT, Asst. Range	Ernakulam
Commissioner of Income-tax (A) Trivandrum	1. IT Circle, Trivandrum	IAC, Trivandrum Range
	2. Salary Circle, TVM	-do-
	3. IT Circle, Alleppey	-do-
	4. IT Circle, Kottayam	-do-
	5. IT Circle, Thiruvalla	-do-
	6. IT Circle, Quilon	-do-
	7. Central Circle, TVM	IAC (Central) Ekm.

Whereas the Income-tax Circle, Ward, District or part thereof stands transferred by those Notification from one charge to another charge, appeals arising out of the assessments made in that Income-tax Circle, Wards or District or part thereof and pending immediately before the date of this Notification before the Commissioner of Income-tax of the Charge from whom the Income-tax Circles, Ward or District or part thereof is transferred shall from date of this notifiaction takes effect be transferred to and dealt with by the Commissioner of Income-tax of the Charge to whom the said Circles, Wards or District or part thereof is transferred.

This Notification shall take effect from 1-9-84.

[No. 5987 (F. No. 261/10/84-ITJ)]

नई दिल्ली, 20 सितम्बर, 1984

का. आ. 15.—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 122 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इस संबंध में इसे समर्थ बनाने वाली अन्य सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए और अपीलीय सहायक आयुक्त, राजकोट रेंज-अ और आ., राजकोट के बारे में इस संबंध में पूर्ववर्ती सभी अधिसूचनाओं का अधिलंघन करते हुए, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, नई दिल्ली एतद्द्वारा निर्देश देता है कि नीचे दी गई अनुसूची के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट रेंज का अपीलीय या सहायक आयकर आयुक्त उक्त अनुसूची के स्तम्भ (3) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट आयकर परिमण्डलों में ऐसे सभी व्यक्तियों और आय के संबंध में अपने कार्य करेगा जिन पर आयकर अधिकारी द्वारा आयकर या अतिकर, लगाया गया हो :—

अनुसूची

क्रमांक	रेंज	आयकर परिमण्डल और आयकर अधिकारी
1	2	3
1.	अपीलीय सहायक आयुक्त, राजकोट रेंज, प्रधान कार्यालय, राजकोट	1. परिमण्डल-1, राजकोट 2. परिमण्डल-II- राजकोट 3. केन्द्रीय परिमण्डल, राजकोट 4. विशेष सर्वेक्षण परिमण्डल, राजकोट 5. सहायक नियंत्रक सम्पदा शुल्क राजकोट, परिमण्डल 6. मोरवी परिमण्डल, मोरवी

2. इस अधिसूचना की तारीख से तत्काल पूर्व विचाराधीन पड़ी किसी कर-निर्धारिती की सभी अपीलें इस अधिसूचना के लागू होने की तारीख से उस रेंज के अपीलीय सहायक आयुक्त को अन्तरित की जाएंगी तथा उसके द्वारा निपटायी जाएंगी, इस अधिसूचना के अनुसार जिसके क्षेत्राधिकार में वह कर-निर्धारिती आता है।

3. यह अधिसूचना 1-10-1984 से लागू होगी।

[सं. 5992 (फा. सं. 261/18/84-आ. क. न्या०)]

New Delhi, the 20th September, 1984

S.O. 15.—In exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of Section 122 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) and of all other powers enabling it in that behalf and in supersession of all the previous notifications in this regard, in respect of Appellate Assistant Commissioners, Rajkot Range-A & B, Rajkot, the Central Board of Direct Taxes, New Delhi hereby directs that the Appellate Assistant Commissioner of Income-tax of the Range specified in column (2) of the Schedule below, shall perform their functions in respect of all persons and incomes assessed to Income-tax or Sur-tax in the Income-tax Circles by the Income-tax Officer specified in the corresponding entry in column (3) thereof:—

SCHEDULE

S. No.	Range	Income-tax Circles & Income-tax Officers
1	2	3
1.	Appellate Assistant Commissioner, Rajkot Range, H.Q. Rajkot	1. Circle-I, Rajkot. 2. Circle-II, Rajkot. 3. Central Circle, Rajkot. 4. Special Survey Circle, Rajkot 5. A.C.E.D., Rajkot Circle. 6. Morvi, Circle, Morvi.

2. All appeals in respect of any assessee pending immediately before the date of this Notification shall, from the date of this Notification takes effect, be transferred to and dealt with by the Appellate Assistant Commissioner of the Range who has jurisdiction over that assessee as per this Notification.

3. This Notification shall take effect from 1-10-84.

[No. 5992 (F. No. 261/18/84-ITJ)]

नई दिल्ली, 29 अक्तूबर, 1984

शुद्धि-पत्र

का॰आ॰ 16.—बोर्ड की दिनांक 4 अगस्त, 1984 की अधिसूचना सं. 5922 (फा. सं. 281/13/84-आ.क.न्या.) की ग्यारहवीं पंक्ति में प्रयुक्त "जो कंपनी (लाभ) अतिकर अधिनियम, 1964 (1964 का 7) की उपधारा-11 के खण्ड (क) से (ज) में," शब्दों के स्थान पर "जो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 246 की उप-धारा (2) के खण्ड (क) से (ज) में कंपनी (लाभ) अतिकर अधिनियम, 1964 (1964 का 7) की धारा 11 की उप-धारा (1) में" पढ़ा जाए।

[सं. 6024(फा.सं. 261/13/84-आ.क.न्या.)]

कल्याण चन्द, अवर सचिव
केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड

New Delhi, the 29th October, 1984

CORRIGENDUM

S.O. 16.—In the Board's Notification No. 5922 (F. No. 261/13/84-ITJ) dated 4th August, 1984 in line 13 after the expression "orders mentioned in clauses (a) to (h) of sub-section" and before the expression "11 of Companies (Profits) Sur-tax Act, 1964 (7 of 1964)" the following may be inserted.

"(2) of Section 246 of the Income-tax Act, 1961 in sub-section (1) of Section".

[No. 6024 (F. No. 261/13/84-ITJ)]

KALYAN CHAND, Under Secy.
Central Board of Direct Taxes

(आर्थिक कार्य विभाग)

(बैंकिंग प्रभाग)

नई दिल्ली, 30 नवम्बर, 1984

का. आ. 17.—प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976, (1976 का 21) की धारा 11 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा श्री सी. बी. अर्जुन राव को अलवर-भरतपुर ग्रामीण बैंक भरतपुर का अध्यक्ष नियुक्त करती है तथा 5-10-84 से प्रारम्भ होकर 31-10-1987 को समाप्त होने वाली अवधि को उस अवधि के रूप में निर्धारित करती है जिसके दौरान श्री सी. बी. अर्जुन राव अध्यक्ष के रूप में कार्य करेंगे।

[संख्या एफ. 2-89/81- आर. आर. बी.]

DEPARTMENT OF ECONOMIC AFFAIRS

(Banking Division)

New Delhi, the 30th November, 1984

S.O. 17.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 11 of the Regional Rural Banks Act, 1976 (21 of 1976) the Central Government hereby appoints Shri C. B. Arjuna Rao as the Chairman of the Alwar-Bharatpur Gramin Bank, Bharatpur and specifies the period commencing on the 5-10-1984 and ending with the 31-10-1987 as the period for which the said Shri Rao shall hold office as such Chairman.

[No. F.2-89|81-RRB]

का. आ. 18—प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 (1976 का 21) की धारा 11 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा श्री बी. एन. सिंह को बलिया क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, बलिया का अध्यक्ष नियुक्त करती है तथा 23-10-84 से प्रारम्भ होकर 31-10-87 को समाप्त होने वाली अवधि को उस अवधि के रूप में निर्धारित करती है जिसके दौरान श्री बी. एन. सिंह अध्यक्ष के रूप में कार्य करेंगे।

[संख्या एफ. 2-40/82- आर. आर. बी.]

एस. एस. हसूरकर, निदेशक

S.O. 18.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 11 of the Regional Rural Banks Act, 1976 (21 of 1976), the Central Government hereby appoints Shri B. N. Singh as the Chairman of the Ballia Kshetriya Gramin Bank, Ballia and specifies the period commencing

on the 23-10-1984 and ending with the 31-10-1987 as the period for which the said Shri B. N. Singh shall hold office as such Chairman.

[No. F. 2-40|82-RRB]

S. S. HASUIKAR, Director

नई दिल्ली, 27 दिसम्बर, 1984

का. आ. 19.—केन्द्रीय सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934,(1934 का 2) की धारा 17 (4खख) (ख) के उपबंधों के अधीन भारतीय रिजर्व बैंक से उधार लेने के प्रयोजन से, भारतीय औद्योगिक ऋण और निवेश निगम द्वारा 16.70 करोड़ रुपए के मूल्य के जारी किए जाने वाले बांडों के संबंध में मूलधन की वापसी अदायगी और और 10% (दस प्रतिशत) की दर से ब्याज की अदायगी की एतद्द्वारा गारंटी देती है बशर्ते कि यह गारंटी बांडों के जारी किए जाने की तारीख से 24 महीने की अवधि के लिए प्रभावी रहे।

[एफ. स. 3(12)-आई.एफ.-1/84]

प्रेम प्रकाश शर्मा, उप सचिव

New Delhi, the 27th December, 1984

S.O. 19.—The Central Government hereby guarantees the repayment of the principal and payment of interest at the rate of 10 per cent (ten per cent) per annum in respect of bonds of the value of Rs. 16.70 crores to be issued by the Industrial Credit & Investment Corporation of India, Limited, for the purpose of borrowing from Reserve Bank of India in terms of Section 17(4BB)(b) of the Reserve Bank of India Act, 1934 (2 of 1934) provided that the guarantee will remain in force for a period of 24 months from the date of issue of the bonds.

[F. No. 3(12)-IF-I/84]

P. P. SHARMA, Dy. Secy.

नई दिल्ली, 19 दिसम्बर, 1984

का. आ. 20.—भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 (1955 का 23) की धारा 21 'क' की उपधारा (1) के साथ पठित धारा 21 की उपधारा (1) के खंड (ग) के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्श से निम्नलिखित व्यक्तियों को 19 दिसम्बर, 1984 से भारतीय स्टेट बैंक के गोहाटी स्थानीय मंडल में सदस्य नामित करती है :—

गोहाटी स्थानीय मंडल

1. श्री माहम सिंह,
   अध्यक्ष,
   मेघालय राज्य विधि आयोग,
   उमसोहसुन,
   शिलांग-793001 (मेघालय)
2. श्री आर.सी. चितेन जमीर,
   सदस्य,
   अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति आयोग,
   लोकनायक भवन,
   नई दिल्ली-110003

[सं. एफ. 8/6/84-बी.ओ.-1]

New Delhi, the 19th December, 1984

S.O. 20.—In pursuance of clause (c) of sub-section (1) of section 21 read with sub-section (1) of section 21A of the State Bank of India Act, 1955 (23 of 1955), the Central Government in consultation with the Reserve Bank of India, hereby nominates the following persons to be members of the Gauhati Local Board of the State Bank of India with effect from December 19, 1984, namely :—

GAUHATI LOCAL BOARD

1. Shri Maham Singh,
   Chairman,
   Meghalaya State Law Commissioner,
   Umsohsun,
   Shillong-793001. (Meghalaya)
2. Shri R. C. Chiten Jamir,
   Member,
   Commission for Scheduled Castes and Scheduled Tribes,
   Loknayak Bhawan, New Delhi-110003.

[No. F. 8/6/84-BO. I]

का. आ. 21.—भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 (1955 का 23) की धारा 21 क की उपधारा (1) के साथ पठित धारा 21 की उपधारा (1) के खंड (ग) के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्श से निम्नलिखित व्यक्तियों को भारत सरकार के वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग (बैंकिंग प्रभाग) की अधिसूचना संख्या एफ. 8/3/77-बी.ओ.-1(2) दिनांक 31 जनवरी, 1978 के अंतर्गत नामित सदस्यों के स्थान पर 29 दिसम्बर 1984 से भारतीय स्टेट बैंक के भुवनेश्वर स्थानीय मंडल में सदस्य नामित करती है।

भुवनेश्वर स्थानीय मंडल

1. डा. किस्सेन कानूनगो
   सलाहकार (कृषि)
   योजना आयोग, योजना भवन
   संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001
2. श्री राबिन कुमार मित्रा,
   25, उद्यान मार्ग,
   भुवनेश्वर-751009, (उड़ीसा)
3. श्री बिरजा प्रसाद मल्लिक,
   राजेन्द्र नगर,
   पो.ओ.-मधु पातना,
   कटक-10 (उड़ीसा)

[संख्या एफ. 8/11/84-बी.ओ.-1]

च. वा. मीरचन्दानी, निदेशक

S.O. 21.—In pursuance of clause (c) of sub-section (1) of section 21, read with sub-section (1) of section 21A of the State Bank of India Act, 1955 (23 of 1955), the Central Government, in consultation with the Reserve Bank of India, hereby nominates the following persons to be members of the Bhubaneswar Local Board of the State Bank of India with effect from December 29, 1984 in place of the members nominated under the notification of the Government of India in the Ministry of Finance, Department of Economic Affairs (Banking Division) No. F. 8/3/77-BO. I (2), dated 31st January, 1978, namely :—

BHUBANESWAR LOCAL BOARD

1. Dr. Kissen Kanungo,
   Adviser (Agriculture),
   Planning Commission,
   Yojna Bhavan,
   Sansad Marg,
   New Delhi-110001.
2. Shri Rabin Kumar Mitra,
   25, Udyan Marg,
   Bhubaneswar-751009,
   (Orissa).
3. Shri Biraja Prasad Mallik,
   Rajendra Nagar,
   P.O. Madhupatna,
   Cuttack-10 (Orissa).

[No. 8/11/84-BO. I]

C. W. MIRCHANDANI, Director

(व्यय विभाग)

नई दिल्ली, 14 दिसम्बर, 1984

का. आ. 22—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 77 के खण्ड (3) के अनुसरण में वित्तीय शक्तियों का प्रत्यायोजन नियम, 1978 का आगे और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम वित्तीय शक्तियों का प्रत्यायोजन (दूसरा संशोधन) नियम, 1984 है।

2. ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. वित्तीय शक्तियों का प्रत्यायोजन नियम, 1978 की अनुसूची 5 में, उपाबंध में, क्रम संख्यांक 21(ख) के सामने,

(i) स्तम्भ 3 में "10,000" अंकों के स्थान पर "20,000" अंक रखे जाएंगे ;

(ii) स्तम्भ 4 में,—

(क) पैरा (3) में, "1,000" अंक के स्थान पर "2,000" अंक रखे जाएंगे ;

(ख) पैरा 4 में, उप पैरा (क), (ख) और (ग) में "10,000" "5,000" और "3,000" अंकों के स्थान पर क्रमशः "20,000", "10,000" और "6,000" अंक रखे जाएंगे।

टिप्पण :— वित्तीय शक्तियों का प्रत्यायोजन नियम, 1978 अधिसूचना सं. का. आ. 2131, तारीख 22 जुलाई, 1978 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात निम्नलिखित द्वारा संशोधन किया गया :—

(1) अधिसूचना सं. का. आ. 1887 तारीख 9-6-1979
(2) अधिसूचना सं. का. आ. 2942, तारीख 1-9-1979
(3) अधिसूचना सं. का. आ. 2611, तारीख 4-10-1980
(4) अधिसूचना सं. का. आ. 2164, तारीख, 15-8-1981
(5) अधिसूचना सं. का. आ. 2304, तारीख 5-9-1981
(6) अधिसूचना सं. का. आ. 3073, तारीख 4-9-1982
(7) अधिसूचना सं. का. आ. 4171, तारीख 11-12-1982
(8) अधिसूचना सं. का. आ. 1314, तारीख 26-2-1983
(9) अधिसूचना सं. का. आ. 2502, तारीख 4-8-1984

[संख्या एफ. 1(21)-संस्था. II (क)/84]

एस. पी. भाटिया, अवर सचिव

(Department of Expenditure)

New Delhi, the 14th December, 1984

S.O. 22.—In pursuance of clause (3) of article 77 of the constitution of India, the President hereby makes the following rules further to amend the Delegation of Financial Powers Rules, 1978, namely :—

1. (1) These rules may be called the Delegation of Financial Powers (Second Amendment) Rules, 1984.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazettee.

2. In Schedule V to the Delegation of Finincial Powers Rules, 1978, in the Annexure, against serial number 21(B),—

(i) in column 3, for the figures "10,000", the figures "20,000" shall be substituted ;

(ii) in column 4,—

(a) in paragraph (3), for the figures "1,000", the figures "2,000" shall be substituted ;

(b) in paragraph (4), in sub-paragraphs (a), (b) and (c), for the figures "10,000", "5,000" and "3,000", the figures "20.000", "10.000" and "6,000" shall, respectively, be substituted.

NOTE: The Delegation of Financial Powers Rules, 1978 published vide Notification No.S.O. 2131, dated July 22, 1978 have subsequently been amended by :—

(i)	Notification	No. SO. 1887	dated	9.6.1979.
(ii)	„	No. SO. 2942,	dated	1.9.1979.
(iii)	„	No. SO. 2611,	dated	4.10.1980.
(iv)	„	No. SO. 2164,	dated	15.8.1981.
(v)	„	No. SO. 2304,	dated	5.9.1981.
(vi)	„	No. SO. 3073.	dated	4.9.1982.
(vii)	„	No. SO. 4171,	dated	11.12.1982
(viii)	„	No. SO. 1314,	dated	26.2.1983
(ix)	„	No. SO. 2502,	dated	4.8.1984

[No. F. 1(21)-E. II(A)/84]

S. P. BHATIA, Under Secy.

वाणिज्य मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 20 दिसम्बर, 1984

का. आ. 23.—केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि भारत के निर्यात व्यापार के विकास के लिए ऐसा करना आवश्यक तथा समीचीन है कि निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 (1963 का 22) की धारा 6 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के वाणिज्य मंत्रालय के आदेश सं. का. आ. 2284 तारीख 19 जून, 1982 में नीचे विनिर्दिष्ट रीति से और संशोधन किया जाए;

और केन्द्रीय सरकार ने उक्त प्रयोजन के लिए नीचे विनिर्दिष्ट प्रस्थापनाएं बनाई है तथा उन्हें निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) नियम, 1964 के नियम 11 के उपनियम (2) द्वारा अपेक्षित के अनुसार निर्यात निरीक्षण परिषद् को भेज दिया है;

अतः, अब केन्द्रीय सरकार उक्त उपनियम के अनुसरण में, उक्त प्रस्थापनाओं को उन लोगों की जानकारी के लिए प्रकाशित करती है जिनके उनसे प्रभावित होने की संभावना है।

2. सूचना दी जाती है कि यदि उक्त प्रस्थापनाओं के बारे में कोई व्यक्ति कोई आक्षेप करना या सुझाव देना चाहता है तो वह उसे इस आदेश के प्रकाशन को तारीख से पैंतालीस दिन के भीतर, निर्यात निरीक्षण परिषद, 11 वीं मंजिल, प्रगति टावर, 26, राजेन्द्र प्लेस, नई दिल्ली-110008 को भेज सकता है।

प्रस्थापना

भारत सरकार के वाणिज्य मंत्रालय के आदेश सं. का. आ. 2284, तारीख, 19 जून, 1982 में निम्नरूप से संशोधन किया जाएगा, अर्थात् :—

1. उक्त आदेश के उपाबंध के खंड 1 में—

(क) उपखंड (4) (क) में मद (ix) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा :—

"(ix) लम्बाई में 3 सें. मी. से अधिक की जड़ें, छाल और डब्बे" होंगे; और

(ख) उपखंड (4) (ख) में मद (iv) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा; अर्थात् :—

"(iv) लम्बाई में 1 सें. मी. से 3 सें. मी. तक की जड़ें छाल और धब्बे"

2. उक्त आदेश के उपाबंध के खंड-3 में,—

उपखंड 1 में, मद (क) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"(क) रोल : एक परेषण में रोलों के 80 प्रतिशत में कपड़े का एक ही टुकड़ा होगा तथा प्रत्येक रोल की विनिर्दिष्ट लम्बाई के ± 10 प्रतिशत माप के भीतर होगी। रोल के शेष 20 प्रतिशत की लम्बाई प्रत्येक रोल की विनिर्दिष्ट लम्बाई के ± 20 प्रतिशत के भीतर होगी तथा उसमें कपड़े के दो से अधिक टुकड़े नहीं होंगे जो तब तक एक साथ जुड़े हुए या सिले हुए नहीं होंगे जब तक कि क्रेता तथा विक्रेता के बीच ऐसा करार न हो। छोटा टुकड़ा 50 मीटर से कम नहीं होना चाहिए। रोल में उपरी टुकड़े की लम्बाई तथा कपड़े के पृथक टुकड़े की विद्यमानता को दर्शाते हुए एक टैग भी उस स्थान पर (दो टुकड़ों के बीच) लगा होगा जो बाहर से स्पष्ट दिखाई दें।"

[मि. सं. 16 (11)/79-ई आई एण्ड ईपी]

MINISTRY OF COMMERCE

New Delhi, the 20th December, 1984

ORDER

S.O. 23.—Whereas the Central Government is of opinion that in exercise of the powers conferred by section 6 of the Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963 (22 of 1963), it is necessary and expedient to amend the order of the Government of India in the Ministry of Commerce No. S.O. 2284 dated 19th June, 1982 in the manner specified below, for the development of the export trade of India,

And whereas the Central Government has formulated the proposals specified below for the said purpose and had forwarded the same to the Export Inspection Council as required by sub-rule (2) of rule 11 of the Export (Quality Control and Inspection) Rules, 1964;

Now, therefore, in pursuance of the said sub-rule, the Central Government hereby publishes the said proposals for the information of the public likely to be affected thereby.

2. Notice is hereby given that any person desiring to forward any objection or suggestion with respect to the said proposals may forward the same within fortyfive days of the date of publication of this Order to the Export Inspection Council of India, 11th floor, Pragati Tower, 26 Rajendra Place, New Delhi-110008.

PROPOSALS

The order of the Government of India in the Ministry of Commerce No. S.O. 2284 dated the 19th June, 1982 shall be amended as follows, namely :—

1. In clause 1 of Annexure to the said Order——

(a) in sub-clause (4) (a), for item (ix), the following shall be substituted namely :—

"(ix) Roots, barks and specks exceeding 3 centimetres in length; and

(b) in sub-clause (4) (b), for item (iv), the following shall be substituted, namely :—

"(iv) Roots, barks and specks from 1 centimetre to 3 centimetres in length." :

2. In clause 3 of Annexure to the said order,—

in sub-clause 1, for item (a), the following shall be substituted namely :

"(a) Rolls : 80 percent of the rolls in a consignment shall contain one continuous piece of cloth and measure within ± 10 percent of the specified length per roll The length of the remaining 20 per cent of the rolls must be within ± 20 percent of the stipulated length per roll and may contain not more than two pieces of cloth (not joined or stiched together unless otherwise agreed to between the buyer and the seller). The shorter piece of cloth must not be less than 50 metres. A tag must also be inserted at this place (separation of the two pieces) clearly visible from outside indicating the presence of a separate piece of doth and the length of the top piece in the roll."

[F. No. 6(11)/79-EI&EP]

आदेश

का. आ. .24—केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि भारत के निर्यात व्यापार के विकास के लिए ऐसा करना आवश्यक तथा समीचीन है कि निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 (1963 का 22) की धारा 6 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के वाणिज्य मंत्रालय के आदेश स. का. आ. 3269 तारीख 10 अगस्त, 1983 में नीचे विनिर्दिष्ट रीति से और संशोधन किया जाए;

और केन्द्रीय सरकार ने उक्त प्रयोजन के लिए नीचे विनिर्दिष्ट प्रस्ताव बनाए हैं तथा उन्हें निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) नियम, 1964 के नियम II के उपनियम (2) की अपेक्षानुसार निर्यात निरीक्षण परिषद् को भेज दिया है;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार उक्त उपनियम के अनुसरण में, उक्त प्रस्तावों को उन लोगों की जानकारी के लिए प्रकाशित करती है जिनके उनसे प्रभावित होने की संभावना है।

2. सूचना दी जाती है कि यदि उक्त प्रस्तावों के बारे में यदि कोई व्यक्ति कोई आक्षेप या सुझाव देना चाहता है तो वह उसे इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से पैंतालीस दिन के भीतर, निर्यात निरीक्षण परिषद्, प्रगति टावर, (11 वीं मंजिल), 26, राजेन्द्र प्लेस, नई दिल्ली-110008 को भेज सकता है।

प्रस्ताव

भारत सरकार, वाणिज्य मंत्रालय का आदेश सं. का. आ. 3269 तारीख 10 अगस्त, 1983 में निम्नलिखित रूप से संशोधन किया जाएगा, अर्थात् :—

उक्त आदेश के उपाबंध के खंड-2 के उपखंड 2.1 में सारणी के क्रम संख्या 11 के सामने स्तंभ 2 के नीचे प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा अर्थात् :—

"कपड़े के दो टुकड़े वाले संगठित गांठों के रोलों का 20 प्रतिशत से अधिक नहीं होंगे (क्रेता से पूछे बिना उसे जोड़ा या सिला नहीं जाएगा)"

[मि. सं. 6(26)/79-ई आई एण्ड ई पी]

S.O. 24.—Whereas the Central Government is of opinion that in exercise of the powers conferred by section 6 of the Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963 (22 of 1963), it is necessary and expedient to amend the order of the Government of India in the Ministry of Commerce No. S.O. 3269 dated 10th August, 1983 in the manner specified below, for the development of the export trade of India;

And whereas the Central Government has formulated the proposals specified below for the said purpose and had forwarded the same to the Export Inspection Council as required by Sub-rule (2) of rule 11 of the Export (Quality Control and Inspection) Rules, 1964;

Now, therefore, in pursuance of the said sub-rule, the Central Government hereby publishes the said proposals for the information of the public likely to be affected thereby.

2. Notice is hereby given that any person desiring to forward any objection or suggestion with respect to the said proposals may forward the same within fortyfive days of the date of the publication of this order to the Export Inspection Council, Pragati Tower (11th floor), 26, Rajendra Place, New Delhi-110008.

PROPOSAL

The order of the Government of India in the Ministry of Commerce No. S.O. 3269, dated the 10th August, 1983 shall be amended as follows, namely :—

In sub-clause 2.1 of clause 2 of the Annexure to the said Order, for the entry under column 2 against serial No. 11 of Table, the following entry shall be substituted namely :—

"Not more than 20 per cent of the rolls may be joined rolls made of 2 pieces of cloth (not joined or stitched together unless otherwise asked by the buyers)."

[F. No. 6(26)/79-EI&EP]

आदेश

का. आ. 25.—केन्द्रीय सरकार की, निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 (1963 का 22) की धारा 6 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह राय है कि भारत के निर्यात व्यापार के विकास के लिए ऐसा करना आवश्यक और समीचीन है कि शुष्क मछली को निर्यात से पूर्व क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण के अधीन रखा जाए;

और केन्द्रीय सरकार ने उक्त प्रयोजन के लिए नीचे विनिर्दिष्ट प्रस्ताव बनाए हैं और उन्हें निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) नियम, 1963 के नियम 11 के उप नियम (2) की अपेक्षानुसार निर्यात निरीक्षण परिषद् को भेज दिया है;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त उप नियम के अनुसरण में, भारत सरकार के वाणिज्य मंत्रालय की शुष्क मछली से संबंधित अधिसूचना सं. का. आ. 2137 तारीख 5 जून, 1970 को उन बातों के सिवाय अधिक्रान्त करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, उक्त प्रस्तावों को उन लोगों की जानकारी के लिए प्रकाशित करती है जिनके उनसे प्रभावित होने की संभावना है।

2. सूचना दी जाती है कि ऐसा कोई व्यक्ति, जो उक्त प्रस्तावों के बारे में कोई आक्षेप या सुझाव देना चाहे, उसे इस आदेश के राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से 45 दिन के भीतर भारतीय निर्यात निरीक्षण परिषद्, प्रगति टावर, 11वीं मंजिल, राजेन्द्र प्लेस, नई दिल्ली-110008 को भेज सकेगा।

प्रस्ताव

(1) यह अधिसूचित करना की शुष्क मछली निर्यात से पूर्व क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण के अधीन होगी।

(2) इस आदेश से संलग्न उपाबंध-1 में दिए गए विनिर्देशों की शुष्क मछली के लिए मानक विनिर्देशों के रूप में मान्यता देना।

(3) इस आदेश से संलग्न उपाबंध-2 में दिए गए शुष्क मछली निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) नियम, 1984 के प्रारूप के अनुसार क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण के प्रकार को ऐसे निरीक्षण के प्रकार के रूप में विनिर्दिष्ट करना जो उनके निर्यात से पूर्व ऐसी शुष्क मछली को लागू होगा;

(4) अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में ऐसी शुष्क मछली के निर्यात को तब तक प्रतिषिद्ध करना जब तक कि उसके साथ निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 की धारा 7 के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा स्थापित किसी अभिकरण द्वारा जारी किया गया इस आशय का प्रमाण पत्र न हो कि ऐसी शुष्क मछली मानक विनिर्देशों के अनुरूप है और निर्यात योग्य है।

3. इस आदेश की कोई भी बात भावी क्रेताओं के लिए अभि समुद्र या वायु मार्ग द्वारा शुष्क मछली के नमूनों के निर्यात को लागू नहीं होगी, परन्तु यह तब जब तक कि ऐसे प्रत्येक नमूने का भार दो किलोग्राम से अधिक न हो।

4. इस आदेश के प्रयोजन के लिए शुष्क मछली से निम्नलिखित व्यापार किस्मों की शुष्क मछली अभिप्रेत है, अर्थात् :

क्रम सं.	किस्म	वैज्ञानिक नाम (जाति)
1	2	3
1.	रियर	साइबियम
2.	एग्गाडला	यथोक्त
3.	बलाया	थाइनस

1	2	3
4.	मराया	कारांगा
5.	काट्टा	चोरी नेमस
6.	कोरुवा	सियाना स्पूडो-सियाना
7.	लवाया	सेरानस
8.	स्ट्रैंटुम/एनचोविस	स्टोलिफोरस/एनचोविल
9.	थालाइनेथोली	स्टोलफोरसट्री
10.	कुने (जावला)	पीनिअस (छोटा)
11.	शल्क रहित झींगे	पीनिअस मैटापिनिअस पैरापिना-ओपसिस
12.	शैल रहित झींगे (करडी)	पिनिअस, मैटापिनिअस
13.	शार्क	कारचारिनस स्फिरना प्रिसटिस
14.	नड्वा	ट्राइगन, माइलियो बैटीड राइन कोबेटस रिनाबेटस
15.	एंगुलुवा (कुलीकोरीन)	ऐरिअस
16.	एंगुलुवा	ऐरिअस
17.	हुल्ला	सार्डीनेला सर्म
18.	मूडया	सार्डीनेल्ला गिब्बोसा
19.	मोरोल्लो	हिमिरहैम्फस
20.	बेनगनवा	पिल्लोना
21.	पैराया छोटे	कारानक्स
22.	कुमब्राथला	राष्ट्रेलिगर कानागुर्ता
23.	थोनदया शुष्क	टुमुमिरिया
24.	सीब्बाकीलस	सिथरीनस एपरिओन लुटियानस
25.	जीला स्फिरेना	गेटोरिना और प्रिस्टोपोमा
26.	ब्लाइफैल्डम	चिरोसेन्ट्रस
27.	थालापाथ	सिमीफयोफोरस
28.	सगरावैरी कारचारीनस (खाल और हड्डी के बिना शार्क स्ट्रिप)	कारचारीनस विशेष
29.	मुथिल्ला	इनाकाटे विशेष
30.	पुलुन्नों (लेपिसा)	लक्टेसिरिअस विशेष
31.	नमक युक्त और शुष्क थानेदया	टुस्सुमेरिया विशेष
32.	बोलान	डीकेपटैरस विशेष
33.	कोली (नमक रहित)	ऐक्सोकाट्रैस
34.	कोली (नमक युक्त)	यथोक्त
35.	सालाया (मालाबार का तैलिय सरडाइन)	सारडिनेल्ला लौंगीसैप्स
36.	सलाया	सरडाइनेल्ला सरडानेला गिब्बोसा, सडाइनेल्ला फिम्ब्रिगेट सरडाइनेल्ला अलबेल्ला कोली विशेष
37.	शुष्क मुम्बई डक	हारपोडेन नेहरियस
38.	लमिनेट मुम्बई डक	हारपोडेन नेहरियस
39.	एंगुलुवा (छोटा (डुबर)	ऐरिअस
40.	सिल्वर बेल्ली (मुल्लेन)	लियोग्नेथस विशेष
41.	सोल मछली (मैथल)	साइनोग्लोसस विशेष
42.	रिबन मछली	ट्रिचिरस विशेष

उपाबंध — 1

शुष्क मछली के लिए विनिर्देश

सामान्य. शुष्क मछली स्वास्थ्यप्रद होगी। किसी गर्त-संसाधित मछली या ऐसी मछली, जिससे पानी निकलता हो (पचपच, अल्प-शुष्क अर्ध शुष्क (या जो सूखे) (रोगजीवाणु वाली) या फफूंदी से (ग्रस्त फफूंदियां ग्रस्त) है या कीटों द्वारा खाई हुई या कीट ग्रस्त मछली या परिष्कृत मछली अनुज्ञात नहीं की जाएगी।

क्रम सं.	किस्म	वैज्ञानिक नाम (जाति)	संक्षेप में संसाधन की पद्धति
1.	2	3	4
1.	मियर	साइवियम	केवल कोलम के रूप में नमक से संसाधित मालाबार तट को सियर की मछली की दशा में वह सिर सहित या रहित अथवा खंड खंड रूप में हो सकेगी। टुकड़ों में कटी हो सकेगी, प्रत्येक टुकड़े का माप 37.5 सें. मी., से कम नहीं होगा ।

क्वालिटी का स्तर				बाह्य पदार्थ	अन्य टिप्पणी
आकार	रूप	गंध	शुष्क अवस्था		
5	6	7	8	9	10
सिर रहित 37.5 सें.मी. और उससे अधिक	रंग भूरा होगा या अच्छी तरह से शुष्क अच्छी सियर मछली की विशिष्टता	बदबूदार या सड़ी गली मछली वाली गंध नहीं, होगी	आर्द्रता 40% से अधिक नहीं	कोई नहीं	मछली का मांस दृढ़ होगा और धज्जियों में नहीं होगा।

1	2	3	4
	2. गंगाइम्ना	माइबियम	यथोक्त
	3. वलाया	थाइरुस	केवल सिर रहित कोलम के रूप में नमक से संसाधित
	4. पराया	कारान्क्स	केवल सिर रहित कोलम के रूप में नमक से संसाधित
	5. यात्रा	थोरीनेमज	यथोक्त
	6. कोड्वा	सियाना स्यूडो सियाना	यथोक्त
	7. लबाया	सेरानस	यथोक्त
	8. स्प्रेट्स	एन्कोथी स्टोलिफेरस एनथोविला	सिर सहित नमक युक्त या नमक रहित
	9. वालाइनेथोली	स्टोलफोरसटी	सिर सहित या रहित नमक युक्त या नमक रहित शुष्क
	10. कुने (जावला)	पिनिअस (छोटा)	शुष्क और नमक से संसाधित न हो।

5	6	7	8	9	10
37.5 से.मी. से कम	यथोक्त	यथोक्त	आर्द्रता 35% से अधिक नहीं	कोई नहीं	—
सिर रहित 20 से.मी. से अधिक	रंग में गाढ़ा	बिल्कुल ताजी संसाधित गंध में कोई भी सड़ी गली गन्ध नहीं होगी।	आर्द्रता 35% से अधिक नहीं	कोई नहीं	—
25 से.मी. और उससे अधिक	भूरा रंग	बिल्कुल ताजी संसाधित, गंध में कोई भी सड़ी गली गंध नहीं होगी	आर्द्रता 35% से अधिक नहीं	कोई नहीं	—
सिर सहित या रहित 30 सें.मी. से अधिक	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त	—
सिर सहित या रहित 60 सें.मी. से अधिक	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त	कोई नहीं	—
सिर सहित या रहित 25	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त	कोई नहीं	—
स.मी. से अधिक सिर सहित 4 सें.मी. से अधिक	सफेद या मन्द रंग या कालापन लिए हुए रंग	स्वास्थ्यप्रद शुष्क मछली की गंध, तीक्ष्ण गंध नहीं	बिना नमक वाली किस्म के लिए आर्द्रता 18% से अधिक और नमक युक्त किस्म के लिए 25%	स्प्रेट्स या अन्य किसी मछली के टुकड़े या अन्य किस्मों की छोटी मछलियों का मिश्रण 6% से अधिक नहीं होगा।	रेत या कुल अंश भार में 7 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा
सिर रहित 4 सें.मी. से अधिक	सफेद या मंद रंग या कालापन लिए हुए रंग और पूर्णतः शल्कों से आवृत्त	स्वास्थ्यप्रद शुष्क मछली की गंध, तीक्ष्ण गंध, नहीं	बिना नमक वाली किस्म के लिए आर्द्रता 18% से अधिक नहीं और नमक युक्त किस्म के लिए 25%	स्प्रेट्स या अन्य किसी मछली के टूटे टुकड़े या अन्य किस्म की किस्मों की छोटी मछलियों का मिश्रण 6% से अधिक नहीं होगा।	रेत या कुल अंश भार में 7 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा।
	सफेद या मंद रंग या कालापन लिए हुए रंग	स्वास्थ्यप्रद शुष्क झींगे मछली की गंध तीक्ष्ण गंध नहीं।	आर्द्रता 25% से अधिक नहीं	कोई नहीं	—

1	2	3	4
11	शल्क रहित झींगें	पिनिग्रस मैटापिनिग्रस पैरापिन ओपसिस	उबली हुई/बिना उबली हुई शुष्क और बिना शल्क की।
12.	शल्क रहित झींगे (करंडी)	पीनिग्रस मैटापिनिग्रस पैरापिनाग्रो-पसिस	उबला हुआ/बिना उबला हुआ शल्क रहित शुष्क
13	शार्क	कारचारिनस स्फिरना प्रिसटिस रीनियोबटस	बड़े टुकड़ों या कोलमों के रूप में नमक से संसाधित
14	मड़ुवा	ट्राइगन, माइलियोबेटीडे, राइनकोबेटस रिनोबेटस	बड़े टुकड़ों के रूप में या कोलमों नमक युक्त संसाधित
15.	एंगुलुवा	गेरिग्रस	लम्बाई में कटे हुए, आंतें निकाली हुई और खंड-खंड मछली या कोलम सिर सहित या सिर रहित नमक युक्त और शुष्क
16.	एंगुलुवा (तूतीकोरीन)	गेसिग्रस	यथोक्त
17	हुरला	सार्डीनेल्ला सर्म	गोलाकार रूप में नमक से संसाधित
18.	सूड़या	सार्डीनेल्ला गिब्बोसा	गोलाकार रूप में नमक से संसाधित

5	6	7	8	9	10
सामुद्रिक झींगें (अन्य जाति के झींगें भार में 10% से अधिक नहीं होगा।	काले विशिष्टता धब्बों से मुक्त रंग।	ताजी, निम्न नहीं।	(i) जब प्रशीतित कक्षों में पोत लदान किया जाए तो आर्द्रता 30% से अधिक नहीं, (ii) जब अन्यथा पोत पर लादा जाएगा तो 25%	**टूटे हुए टुकड़े भार में 15 प्रतिशत से अधिक नहीं होंगे टूटे हुए टुकड़ों को छोड़कर खराब टुकड़े, आंखें, शल्के और पूंछे भार में 2% से अधिक नहीं होंगे)	भस्म अम्ल अघुलनशील भस्म प्रतिशत से अधिक नहीं।
--	विशिष्टता काले धब्बों से मुक्त रंग	ताजी, निम्न नहीं।	आर्द्रता 30% से अधिक नहीं	खराब टुकड़े भार में 2 प्रतिशत से अधिक नहीं होंगे।	अम्ल अघुलनशील भस्म 0.5 प्रतिशत से अधिक नहीं।
कौडल पर एक साथ धारित होने वाले टुकड़ों के रूप में या बड़े टुकड़ों के रूप में हो सकते हैं।	मांस की तरफ सफेद या सफेद सा	विशिष्टताएं, शार्क की गंध थोड़ा सा निम्न	आर्द्रता 35% से अधिक नहीं	कोई नहीं	--
कौडल पर एक साथ धारित होने वाले टुकड़ों के रूप में या बड़े टुकड़ों के रूप में हो सकते हैं।	यथोक्त	यथोक्त	--	कोई नहीं	---
30 सें.मी. से अधिक	सफेद या हल्का भूरा	संसाधित मछली की ताजी गंध	आर्द्रता 35% से अधिक नहीं	कोई नहीं	
20 सें.मी. से अधिक	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त	कोई नहीं	कोलमों का अधिमान्यता।
7 सें.मी. से अधिक	भूरा या सफेद	ताजी संसाधित मछली की गंध कोई अन्य अमोनियाई अरुचिकर गंध नहीं होगी।	आर्द्रता 30% से अधिक नहीं	कोई नहीं	मांस दृढ़ होगा और धज्जियों में नहीं होगा।
यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त	कोई नहीं	यथोक्त

* शल्क स्प्रैट्स एनकोवी में कुल रेत अंश 14.5% तक उस दशा में अनुज्ञात होगा यदि 7% से अधिक अतिरिक्त रेत अंश उन्हीं जातियों की अतिरिक्त सामग्री मिलाकर पूरा किया जाए परन्तु यह तब जब कि क्रेता इस विशेष सहायता के लिए सहमत हो।

** यदि टूटे हुए टुकड़े 15 प्रतिशत से अधिक है तो परेषण को सारा टूटा हुआ माना जाएगा

1	2	3	4
19.	मोरोल्लो	हिमिर हैम्फस	गोलाकार रूप में नमक युक्त और शुष्क
20.	बेनगनवा	पिल्लोना	गोलाकार रूप में नमक से संसाधित और अच्छी तरह से शुष्क
21.	पैरावा छोटा	कारानक्स	यथोक्त
22.	कुमबालवा	राष्ट्रेलिगर कानागुर्ता	आंतों और गलफड़ों को निकाल दिया जाएगा। नमक से संसाधित और शुष्क
23.	थानेवया शुष्क	थुमुर्मिरिया	गोलाकार रूप में शुष्क तथा नमक रहित
24.	चीथाकोलम	लीथरीनस एपरिग्रोन लूहियानस गेटिरिना और प्रिस्टीपोमा	कोलम के रूप में नमक से संसाधित और शुष्क सिर सहित या रहित हो सकेगी।
25.	जीला	रिफरेना	खंड खंड या कोलम
26.	बलाईकेन्डम	चिरोसेन्ट्रम	मछली से आंतें निकाली हुई। टुकड़ों में कटी हुई। नमक से संसाधित तथा शुष्क।
27.	थालापाथ	मिसफियो फोरस	कटी हुई रूप में या साबुत रूप मे मछली कोलम या स्ट्रिप या बड़े टुकड़ें के रूप में (सिर सहित या सिर रहित) हो सकती है (साबुत रूप में मछली या टुकड़ों में यदि मछली बहुत बड़े आकार की है), संसाधित

5	6	7	8	9	10
15 से 30 सें. मी. थूथनी से पूंछ तक	भूरा या सफेद	ताजी संसाधित मछली की गंध कोई अन्य अमोनियाई या अरुचिकर गंध नहीं होगी।	आर्द्रता 30 प्रतिशत से अधिक नहीं	कोई नहीं	मास दृढ़ होगा और धज्जियों में नहीं होगा।
6 सें मी. से अधिक	सफेद से पीला	यथोक्त	यथोक्त	कोई नहीं	यथोक्त
25 सें. मी. से कम	सफेद से हल्का भूरा	यथोक्त	यथोक्त	कोई नहीं	यथोक्त
10 सें. मी. से अधिक	सफेद से हल्का पीला या हल्का भूरा	ताजी	यथोक्त	कोई नहीं	नमक की पपड़ी लगाने के सिवाय अधिक से अधिक 4 प्रतिशत खुला नमक किन्तु टेयर जोड़ने की व्यवस्था सहित।
7 सें. मी. से अधिक	मछली का प्राकृतिक रंग किन्तु फीका, चमकीला नहीं	हल्की तीक्ष्ण गंध किन्तु ताजी शुष्क गंध अन्यथा कोई सड़ी गली गंध नहीं होगी।	आर्द्रता 20 प्रतिशत से अधिक नहीं	टूटे हुए टुकड़े या किसी अन्य मछली के बड़े टुकड़े या अन्य किस्मों की छोटी मछली का मिश्रण 5 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा।	मछली से अलग की हुई रेत टेयर बनाएगी।
25 सें. मी. से अधिक	हल्का पीला से गाढ़ा भूरा	ताजी संसाधित गंध में कोई दुर्गंध नहीं होगी।	आर्द्रता 35 प्रतिशत से अधिक नहीं	कोई नहीं	—
22.5 सें. मी. से अधिक	रंग में गाढ़ा	ताजी संसाधित गंध में कोई सड़ी गली गंध नहीं होगीं।	आर्द्रता कोई 35 प्रतिशत से अधिक नहीं	कोई नहीं	कोलम लम्बाई में कटे हुए। खंड खंड और आंतें निकली हुई मछली को अधिमानता दी जाए।
10 सें. मी. से अधिक	सफेद सा से मंद भूरा	ताजी	आर्द्रता 35 प्रतिशत से अधिक नहीं	कोई नहीं	—
यथास्थिति, साबुत मछली के रूप में या टुकड़ों के रूप में 30 सें. मी. से अधिक	सफेद या भूरा	ताजी	यथोक्त	कोई नहीं	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
28.	सरगाचेर्री (खाल और हड्डी के बिना शार्क स्ट्रिप)	कारचारीनस विशेष	हड्डी या खाल या पंख के बिना शार्क मछली के कटे छटे मांस के टुकड़े और नमक से संसाधित तथा शुष्क।	टुकड़े 10 से. मी. से अधिक	सफेद से भूरा या मांस का रंग	विशिष्टता या शार्क के मांस की गंध (हल्का तीक्ष्ण)	आर्द्रता 35 प्रतिशत से अधिक नहीं	कोई नहीं	
29.	सुथिहला	स्कोलाकाटे विशेष	नमक से संसाधित और खण्ड-खंड में शुष्क या सिर सहित या रहित कालम के रूप में।	15 से. मी. से अधिक	सफेद से विवर्ण भूरा	विकृत और सड़ी गली मछली की गंध नहीं होगी।	यथोक्त	कोई नहीं	
30.	पुल्लुर्रो (लेपिना)	लैक्टेरियस विशेष	नमक से संसाधित और आंतों सहित या रहित गोलाकार रूप में शुष्क। खण्ड-खण्ड रूप में भी संसाधित की जा सकेगी।		रंग में हल्का काला	विकृत या सड़ी गली मछली की गंध नहीं नहीं होगी।	आर्द्रता भार में 30 प्रतिशत से अधिक नहीं	कोई नहीं	
31.	नमकयुक्त और शुष्क थीनद्रया	द्रुस्सुमेरिया विशेष	गोलाकार रूप में नमक से संसाधित और शुष्क।	7 से. मी. से अधिक	यथोक्त	यथोक्त	आर्द्रता 30 प्रतिशत से अधिक नहीं	कोई नहीं	
32.	बोलान	ड्रीकैण्टेस्पस विशेष	गोलाकार रूप में नमक से संसाधित और शुष्क।	7 से. मी. से अधिक	सफेद से हल्का पीला	विकृत या सड़ी-गली मछली की गंध नहीं होगी।	आर्द्रता 35 प्रतिशत से से अधिक नहीं	कोई नहीं	पैकिंग के समय 4 प्रतिशत तक नमक मिलाने की अनुज्ञा होगी किन्तु यह टेयर में जोड़ा जाएगा।
33.	कोली (नमक रहित)	एक्सोकाट्स विशेष	साबुत रूप में शुष्क। नमक नहीं लगाया जाएगा।	8 से. मी. से अधिक	हल्का नीला से काला	यथोक्त	आर्द्रता 25 प्रतिशत से अधिक नहीं	कोई नहीं	
34.	कोली (नमक युक्त)	यथोक्त	गोलाकार रूप में नमक से संसाधित और शुष्क।	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त	आर्द्रता 35 प्रतिशत से अधिक नहीं	कोई नहीं	अम्ल अघुलनशील भस्म भार में 5 प्रतिशत हो सकती है।
35.	सफाया (मालाबार का तैलीय सरडाइन)	सरडाइनल्ला लांगीसैप्स	आंत निकासन के बाद नमक से संसाधित और शुष्क।	7 से. मी. से अधिक	हरिताभ से भूरा	विकृत या सड़ी-गली मछली की गंध नहीं होगी।	आर्द्रता 30 प्रतिशत से अधिक नहीं	कोई नहीं	पैकिंग के लिए प्रयुक्त रवा या चूर्ण के रूप में नमक भार में 4 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा और यह टेयर में जोड़ा जाएगा।
36.	सलाया	सरडाइनल्ला गिब्बोसा सरडाइनल्ला फिम्ब्रिएटा, सरडाइनल्ला अलबेल्ला, कोली विशेष	गोलाकार रूप में नमक से संसाधित और शुष्क आंतें नहीं निकाली जाएंगी।	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त	कोई नहीं	यथोक्त
37.	शुष्क मुम्बई डक	हारपोडॉन नेहिरियस	स्वास्थ्यकर दशा में धूप से सुखाई हुई या कृत्रिम शोषक से सुखाई हुई।	----	गुलाबी धब्बा से मुक्त विशिष्ट रंग	विकृत गंध से मुक्त विशिष्ट गंध	आर्द्रता भार में अधिकतम 25 प्रतिशत		(आर्द्रता मुक्त आधार पर) अम्ल में अघुलनशील भस्म अधिक से अधिक 5 प्रतिशत।

1	2	3	4
38.	लमिनेटेड मुम्बई डक	हार्पाडोन नेहिरियस	सिर, पंखों और आंतों को हटाने के पश्चात् शुष्क मछली को उपयुक्त रूप में दबाकर तथा समान आकार के टुकड़े प्राप्त करने के लिए दांए और बाएं भागों को काट-छांट कर तैयार की गई।
39.	एंगुलुवा छोटा (डुवर)	ऐरियस	लम्बाई में काटी हुई आंतें निकाली हुई और खंड खंड मछली या सिर सहित या सिर रहित नमक युक्त शुष्क कोलम
40.	सिल्वर बल्ली (मुलेन)	लियोग्नेथस विशेष	सिर सहित नमक युक्त या नमक रहित शुष्क
41.	सोल मछली	साइनोग्लोसस विशेष	यथोक्त
42.	रिबन मछली	ट्रिचियूरस विशेष	साबुत मछली नमक से समाधित और शुष्क

5	6	7	8	9	10
बड़ी 15 सें. मी. और उससे अधिक छोटी 15 सें. मी. से कम	यथोक्त	यथोक्त	आर्द्रता भार में 20 प्रतिशत से अधिक नहीं		(आर्द्रतामुक्त आधार पर) अम्ल अघुलनशील भस्म अधिक से अधिक 2.5 प्रतिशत।
15 सें०मी० से अधिक	सफेद सा से फीका भूरा	समाधित मछली की ताजी गंध	आर्द्रता 35 प्रतिशत से अधिक नहीं	कोई नहीं	—
—	रंग चमकदार सफेद से सफेद होगा शुष्क सिल्वर बैल्ली की विशिष्टता	स्वास्थ्यप्रद शुष्क मछली की गंध तीक्ष्ण गंध नहीं।	आर्द्रता नमक युक्त किस्म के लिए 35 प्रतिशत और नमक रहित किस्म के लिए 25 प्रतिशत से अधिक नहीं।	टूटी हुई और अन्य किस्मों की मछलियां 5 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।	अम्ल अघुलनशील भस्म 2 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।
—	विशिष्टता शुष्क सोल मछली का भूरे से गहरा बैंगनी रंग	यथोक्त	यथोक्त	कोई नहीं।	अम्ल अघुलनशील भस्म भार में 1.5 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।
30 सें०मी० से अधिक	विशिष्टता ताजी शुष्क रिबनमछली का सफेद रंग	यथोक्त	आर्द्रता 35 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।	कोई नहीं	अम्ल अघुलनशील भस्म भार में 2 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।

उपाबंध 2

शुष्क मछली का निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) नियम, 1970 को अधिक्रान्त करते हुए, निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 (1963 का 22) की धारा 17 के अधीन बनाए जाने के लिए प्रस्तावित नियमों का प्रारूप :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम शुष्क मछली निर्यात (निरीक्षण) नियम, 1984 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 60 दिन के पश्चात् प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएं.—इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(1) "अधिनियम" से निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 (1963 का 22) अभिप्रेत है।

(2) "अभिकरण" से अधिनियम की धारा 7 के अधीन मुम्बई, कलकत्ता, कोचीन, दिल्ली और मद्रास में स्थापित अभिकरणों में से कोई एक अभिकरण अभिप्रेत है।

(3) "परिषद" से निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम 1963 की धारा 3 के अधीन स्थापित निर्यात निरीक्षण परिषद अभिप्रेत है।

(4) "शुष्क मछली" से इन नियमों की अनुसूची में विनिर्दिष्ट कोई भी व्यापार किस्म की शुष्क मछली अभिप्रेत है।

3. निरीक्षण का आधार :—निर्यात के लिए आशयित शुष्क मछली का निरीक्षण यह देखने के उद्देश्य से किया जाएगा कि शुष्क मछली अधिनियम की धारा 6 के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त विनिर्देशों के अनुरूप है।

4. निरीक्षण की प्रक्रिया (1) शुष्क मछली का निर्यात करने का इच्छुक निर्यातकर्ता, निर्यात किए जाने के लिए आशयित परेषण की विशिष्टता देते हुए, अभिकरण के निकटतम कार्यालय को आवेदन देगा ताकि वह ऐसे परेषण की परीक्षा इस दृष्टि से कर सके या करवा सके कि परेषण नियम 3 में निर्दिष्ट विनिर्देशों के अनुरूप है या नहीं।

(2) उपनियम (1) के अधीन प्रत्येक आवेदन, निर्यातकर्ता के परिसर से परेषण पोत लदान के लिए भेजी जाने की प्रत्याशित तारीख से कम से कम तीन दिन पूर्व किया जाएगा।

(3) उपनियम (2) में निर्दिष्ट आवेदन प्राप्त होने पर अभिकरण परिषद द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों के अनुसार शुष्क मछली के परेषण का निरीक्षण करेगा और अपना यह समाधान करेगा कि परेषण मान्यता प्राप्त विनिर्देशों की अपेक्षाओं का अनुपालन करता है। निर्यातकर्ता अभिकरण को ऐसा निरीक्षण करने के लिए सभी आवश्यक सुविधाएं प्रदान करेगा।

5. प्रमाणन :—यदि परेषण का निरीक्षण करने के पश्चात् अभिकरण का यह समाधान हो जाता है कि वह मान्यताप्राप्त विनिर्देशों के अनुरूप है और उसे इन नियमों के अनुसार पैक और चिह्नित किया गया है तो वह निरीक्षण की तारीख से 3 दिन के भीतर यह घोषणा करते हुए

एक प्रमाण पत्र जारी करेगा कि परेषण निर्यात योग्य है परन्तु यदि अभिकरण का ऐसा समाधान नहीं होता है तो वह उक्त 3 दिन की अवधि के भीतर ऐसा प्रमाण पत्र जारी करने से इंकार कर देगा और ऐसे इंकार की सूचना उसके कारणों सहित निर्यातकर्ता को देगा।

6. निर्यात के लिए पैकिंग और चिन्हित किया जाना.—(1) शुष्क मछली को निर्यात संविदा में विनिर्दिष्ट रूप में पैक किया जाएगा।

(2) उपनियम (1) में निर्दिष्ट किसी करार के न होने पर, उसे उस रीति से पैक किया जाएगा जो परिषद् विहित करे।

(3) प्रत्येक पैकेज पर निम्नलिखित विशिष्टियां अमिट स्याही से चिन्हित की जाएंगी या निम्नलिखित विशिष्टियों सहित लेबल लगाया जाएगा।

(क) सामग्री का नाम और किस्म,

(ख) अन्तर्वस्तु का शुद्ध भार और पैकेजों का कुल भार,

(ग) पोतलदान चिन्ह

(घ) पोत का गन्तव्य स्थान,

7. निरीक्षण का स्थान (1) इन नियमों के प्रयोजन के लिए निरीक्षण निर्यातकर्ता के परिसर में किया जाएगा जिसमें प्रकाश की अच्छी व्यवस्था होगी और जिसे स्वच्छ और स्वास्थ्य प्रद दशाओं में रखा जाएगा। निर्यातकर्ता द्वारा परिसर में तोलने, पैक करने और निरीक्षण की आवश्यक सुविधाएं प्रदान की जाएंगी।

(2) उपनियम (1) में परिसर में निरीक्षण के अतिरिक्त अभिकरण को यह अधिकार होगा कि वह परेषण की क्वालिटी का भण्डार अभिवहन में या पत्तनों पर पुनः निर्धारण कर सकेगा, जैसा वह इन नियमों के प्रयोजन को क्रियान्वित करने के लिए आवश्यक समझे। यदि इस प्रक्रमों में से किसी पर परेषण मान्यताप्राप्त विनिर्देशों के अनुरूप नहीं पाया गया है तो नियम 5 के अनुसार जारी किया गया प्रमाण पत्र वापस ले लिया जाएगा।

8. निरीक्षण फीस :—प्रति परेषण न्यूनतम 50 रुपए के अधीन रहते हुए, परेषण के पोत पर्यन्त नि:शुल्क मूल्य के 0.4 प्रतिशत की दर से फीस अभिकरण को दी जाएगी।

9. अपील.— अभिकरण द्वारा नियम 5 के अधीन प्रमाण पत्र जारी करने से इंकार करने से व्यथित कोई निर्यातकर्ता, उसके द्वारा ऐसे इंकार की सूचना प्राप्त होने के दस दिन के भीतर, केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त, विशेषज्ञों के पनल को, जिसमें कम से कम तीन और अधिक से अधिक सात व्यक्ति होंगे, अपील कर सकेगा।

विशेषज्ञों के पैनल की कुल सदस्यता के कम से कम दो तिहाई सदस्य, गैर सरकारी होंगे। पैनल की गणपूर्ति तीन सदस्यों से होगी। अपील को उसकी प्राप्ति से पन्द्रह दिन के भीतर निपटा दिया जाएगा।

अनुसूची

[नियम 2 (4) देखें]

क्रम सं.	किस्म	वैज्ञानिक नाम (जाति)
1	2	3
1	सियर	माइक्रियस
2	एरगाछला	यथोक्त
3.	बलाया	थाइननस
4	पराया	कारान्सस
5.	कादृरा	चोर्र. नेमज
6.	कोडुवा	सियाना स्पूडो-सियाना
7.	लथाया	सेगनस
8.	स्नैट्स/एनचोविज	स्टोलेफोरस/एनचोविस
9.	वाल्लछनेथोली	स्टोलफोरस ट्री
10.	कुने (जावला)	पनिअस (छोटा)
11.	शल्क रहित झींगे	पनिअस मेटापेनिअस पैरापिना-ओपसिस
12.	शैल रहित झींगे (कारड)	पिनिअस, मैटापिनिअस
13.	शार्क	कारचारिनस स्फिरना प्रिसटिस
14.	सबुरा	ट्राइगन, माइलियो बैटिडे राइन-कौबेटसरिनोबैट्स
15.	एरालुवा	ऐरिअस
16.	एगुलुवा (तून कोरन)	ऐरिअस
17.	हुल्ला	सार्डीनेल्ला सर्म
18.	मूड्या	सार्डीनेल्ला गिब्बोसा
19.	मोरोल्लो	हिमिरहैम्फस
20	बेनगलवा	पिल्लोना
21.	पैराबा छोटे	कारानक्स
22	कुमबालवा	रास्ट्रेलिगर कानागर्वा
23.	थोमंदया शुष्क	ड्युस्मिरिया
24.	चोक्याक लेम	लैथरनस एपरिओन लुटियानस सेटिग्ना और प्रिस्टपोमा
25.	जेला	स्फिरेना
26.	क्लाइकैन्डस	चिरोसेन्ट्रस
27.	थालाराथ	सिसफियोफोरस
28.	सगरपेरा कारचारिनस (खाल और हड्डी के बिना शार्क स्ट्रिप)	कारचारनस विशेष
29.	सूथिल्ला	ट्राइकाटे विशेष
30.	पुसुल्लो (लेपिसा)	लेक्टेरिअस विशेष
31	नमक युक्त और शुष्क थामेदया	ड्युस्मुमेरिया विशेष
32.	बोमान	इलैगटेरस विशेष
33	कोल (नमक रहित)	ऐब्लीफाटोस
34.	कोल (नमक युक्त)	यथोक्त
35.	सालाया (मालाबार का तेल व सारडाइन)	सारडिनेल्ला लौंग सेप्स
36.	सलाया	सरडाइनेल्ला सरडाइनेल्ला, गिब्बोसा, सरडाइनेल्ला फिम्ब्रिएटे सरडाइनेल्ला अलबेल्ला कोली विशेष
37.	शुष्क मुम्बई डक	हारपोडेन नेहरियस
38.	लसिनेट मुम्बई डक	हारपोडेन नेहरियस
39	एगुलुवा छोटा (डुवर)	ऐरिअस
40	सिल्वर बैल्लो (मुल्लेन)	लियोग्नेथस विशेष
41.	सोल मछली (मैथल)	साइनोग्लोसस विशेष
42.	रिबन मछली	ट्रिचिरस विशेष

[फाईल सं. 6/1/84-ई आई एण्ड ई. पी.]

एन. एस. हरिहरण, निदेशक,

पाद टिप्पण

का०आ० 2137 तारीख 5-6-1970

S.O. 25.—Whereas in exercise of the powers conferred by section 6 of the Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963 (22 of 1963) the Central Government is of opinion that it is necessary and expedient so to do for the development of the export trade of India that Dried Fish should be subjected to quality control and inspection prior to export.

And, whereas, the Central Government has formulated the proposals specified below for the said purpose and has forwarded the same to the Export Inspection Council as required by sub-rule (2) of rule 11 of the Export (Quality Control and Inspection) Rules, 1964;

Now, therefore, in pursuance of the said sub-rule, the Central Government in supersession of the notification of the Governmiet of India in the Miistry of Commerce No. S.O. 2137 dated 5th June, 1970, relating to Dried Fish, except as respects things done or mitted to be done, hereby publishes the said proposals for information of the public likely to be affected thereby.

2. Notice is hereby given that any person who desires to make any objection or suggestion with respect to the said proposals may forward the same within 45 days of the date of publication of this order in the Official Gazette, to the Export Inspection Council, Pragati Tower, 11th floor, 26, Rajendra Place, New Delhi-77008.

PROPOSALS

(1) To notify that Dried Fish shall be subject to quality control and inspection prior to export;

(2) To recognise the specifications as set out in Annexure-I appended to this order as the standard specifications for Dried Fish;

(3) To specify the type of quality control and inspection in accordance with the draft Export of Dried Fish (Quality Control and Inspection) Rules, 1984 as set out in Annexure-II appended to this order as the type of inspection which shall be applied to such Dried Fish prior to their export:

(4) To prohibit the export of such Dried Fish in the international trade unless the same are accompanied by a certificate of inspection issued by an Agency established by the Central Government under section 7 of the Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963 to the effect that such Dried Fish conform to the standard specifications and are exportworthy.

3. Nothing in this order shall apply to the export by land, sea or air of samples of Dried Fish to prospective buyers, provided that each such sample does not weigh more than two kilograms.

4. For the purpose of this order, 'Dried Fish' shall mean any of the following trade varieties of Dried Fish namely :

Sl. No.	Variety	Scientific name (species)
1	2	3
1.	Seer	Cybium
2.	Angila	-do-
3.	Balaya	Thynnus
4.	Parawa	Caranx
5.	Katta	Chorinemuz
6.	Kroduwa	Sciaena Pseudo-Sciaena
7.	Lavaya	Serranus
8.	Spratts/Anchovis	Stolephorus/Anchoville
9.	Valainetholi	Stolephorus tri
10.	Kooney (Jawla)	Penacus (small)
11.	Prawns without shell	Penaeus Metapenaeus Parapenaeopsis
12.	Prawns with shell (Kardi)	Penaeus Metapenaeus Parapenaeopsis
13.	Shark	Carcharinus, Sphyrna, Pristis Galcourda
14.	Maduwa	Trygon, Myliobatidae, Rhynchobatus Rhinabatus
15.	Anguluwa	Arius
16	Anguluwa (Tuticorin)	Arius
17.	Hurulla	Sardinella Sirm
18.	Soodaya	Sardinella gibbosa
19.	Morollo	Hemirhamphus
20.	Venganawa	Pellona
21.	Parawa Small	Caranx
22.	Kumbalawa	Rastrelliger Pranagurta
23.	Thondaya Dried	Dussumeria
24.	Chevva Keelam	Lethrinus Aprion Lutianus Gatorina & Pristipoma
25.	Jecla	Sphyraena
26.	Valaikandam	Chirocentrus
27.	Thalapath	Misfiophorus
28.	Magaracheri Carcharinus (Shark strips without skin and bone)	Carcharinus spp.
29.	Moothilla	Elacate spp.
30.	Pulunno (Lapisa)	Lactarius Spp.
31.	Thondaya salted & dried	Dussumeria Spp.
32.	Bolan	Decapterus Spp.
33.	Koli (Unsalted)	Exocaetus
34.	Koli (salted)	-do-
35.	Salaya (Oil sardine of Malabar)	Sardinella longiceps
36.	Salaya	Sardinella gibbosa, Sardinella fimbriate, Sardinella al-bella Colie Spp.
37.	Dried Bombay Duck	Harpoden nehereus
38.	Laminate Bombay Duck	Harpoden nehereus
39.	Anguluwa small (Dubar)	Arius
40.	Silver Belly (Mullen)	Leiognathus Spp.
41.	Sole Fish (Manthal)	Cynoglosus Spp.
42.	Ribbon Fish	Trichurus Spp.

ANNEXURE—I

SPECIFICATIONS FOR DRIED FISH

General : Dried Fish shall be wholesome. No pit-cured fish or fish oozing with water (pechaped, "semi-dried", "half-dried". "Soft Dried") or having 'red' (bacteria) or mould attack (fungal attack) or maggotridden or insect infested fish or reconditioned fish shall be permitted

Sr. No.	Variety	Scientific name (species) brief	Method of cure in brief
1	2	3	4
1.	Seer	Cybium	Cured with salt as keelam only. May be with or without heads or in split open form in case of seer fish from the Malabar coast May be cut into pieces each piece measuring not less than 37.5 cm.
2.	Angila	-do-	-do-

Size	Appearance	Smell	Driage		
5	6	7	8	9	10
37.5 cm & above without head	Colour shall be brown or characteristic of well dried good seer fish	Shall not be that of rancid or decomposed fish	Moisture not exceeding 40%	Nil	Fish flesh shall be firm and shall not come off in shreds
Below 37.5 cm	-do-	-do-	Moisture not exceeding 35%	Nil	—

1	2	3	4
3.	Balaya	Thynnus	Curred with salt as Keelam without head only.
4.	Parawa	Caranx	-do-
5.	Katta	Chorinemuz	-do-
6.	Koduwa	Sciaena Pseudo-Sciaena	-do-
7.	Lavaya	Serranus	-do-
8.	Spratts/Anchovy	Stolephorus/Anchoviella	Salted or unsalted with head
9.	Valainatholi	Stolephorus Tri	Salted or unsalted dried with or without head
10.	Kooney (Jawla)	Penaeus (samll)	Dried and not salted cured
11.	Prawns without shell	Penaeus Metapenaeus parapenaeopsis	Boiled unboiled, Dried & deshelled

5	6	7	8	9	10
Above 20 cm. without head	Dark in colour	Freshly cured smell shall not have any decomposed odour	Moisture not exceeding 35%	Nil	—
25 cm. & above	Brown coloured	-do-	-do-	Nil	—
Above 30cm. with or with out head	-do-	-do-	-do-	Nil	—
Above 60 cm. with or without head	-do-	-do-	-do-	Nil	—
25 cm & above with or without head	-do-	-do-	-do-	Nil	—
Above 4 cm with head	White or dull coloured blackish coloured	Wholesome dried fish smell & not pungent	Moisture not exceeding 18% for unsalted variety & 25% for salted variety	Broken bits of spratts or any other fish or mixture of other varieties of small fish shall not be more than 6%	*Total sand content shall not exceed 7% by weight.
Above 4 cm. without head	White or dull coloured or blackish coloured and fully covered with scales	-do-	-do-	-do-	Total sand content shall not exceed 7% by wt.
—	White or dull coloured or blackish coloured	Wholesome dried prawn smell and not pungent	Moisture not exceeding 25%	Nil	—
Whole prawn (Prawns of other species shall not exceed 10% by weight)	Characteristic colour free from black discolouration	Fresh & not pungent	Moisture not exceeding (i) 30% when shipped in refrigerated chambers & (ii) 25% if shipped otherwise	**The broken pieces shall not exceed 15% by wt. spoiled pieces eyes, shells & tails excluding the broken pieces shall not exceed 2% by wt.	Acid insoluble ash not to exceed 1%

*Total sand content upto 14.5% shall be permitted in dried spratts Anchovy if the excees sand content above 7% is compensated by adding additional material of the same species, provided that the buyer agree to this special tolerance.

**In case the broken pieces exceed 15% the consignment shall be treated as whole and broken/broken.

1	2	3	4
12.	Prawns with shell (Kardi)	Penaeus Metapenaeus Parapenaeopsis	Boiled/unboiled, dried with shell
13.	Shark	Carcharinus Sphyrns Pristis Galeourda	Salt cured as fillets or as Keelams
14.	Maduwa	Trygon, Myliobatidae, Rhynchobatus Rhinabatus	Salt cured as fillets or as Keelams
15.	Anguluwa	Arius	Cut open longtitudinally entrails removed and fish split open, or Keelams salted and dried with or without head
16.	Anguluwa (Tuticorin)	Arius	-do-
17.	Hurulla	Sardinella sirm	Salt cured in the round form
18.	Soodaya	Sardinella gibbosa	Cred with salt in the round form
19.	Morollo	Hemirhamphus	Salted and dried in the round form
20.	Venganawa	Pellona	Cured with salt in the round form and well dried
21.	Parawa Small	Caranx	Cured with salt in the round form and well dried
22.	Kumbalawa	Rastrelliger kanagurta	Guts & gills shall be removed. Cured with salt & dried.
23.	Thondaya Dried	Dussumeria	Dried in the round form and not salted

5	6	7	8	9	10
—	Characteristic colour free from black discolouration	-do-	Moisture not exceeding 30%	Spoiled pieces shall not exceed 2% by wt.	Acid in soluble ash not to exceed 0.5%
As pieces being held together at the caudal or can be in the form of fillets	White or whitish on the flesh side	Characteristic smell of shark (lightly pungent)	Moisture not exceeding 35%	Nil	—
As pieces being held together at the caudal or can be in the form of fillets	White or Whitish on the flesh side	Characteristic smell of shark (lightly pungent)	Mossture not exceeding 35%	Nil	—
Above 30cm.	Whitish to dull brown	Fresh flavour of a cured fish	Moisture not exceeding 35%	Nil	—
Above 20 cm.	-do-	-do-	-do-	Nil	Keelams preferred
Above 7 cm.	Brown Or white	That of freshly cured fish. No other ammonical or foul odour shall be present	Moisture not exceeding 30%	Nil	Flesh shall be firm and not come of in shreds
Above 7 cm.	-do-	-do-	-do-	Nil	-do-
15 to 30.cm. (Beak to tail)	-do-	-do-	-do-	Nil	-do-
Above 6 cm.	White to yellow	-do-	-do-	Nil	-do-
Below 25 cm.	White to light brown	That of freshly cure fish. No other ammonical or foul odour shall be present.	Moisture not exceeding 30%	Nil	Flesh shall be firm and not come off in shreds.
Above 10 cm.	White to light yellow or light brown	Fresh	Moisture not exceeding 30%	Nil	Maximum 4% loose salt except salt encrustation but with provision to add tare
Abve 7 cm.	Natural colour of the fish but dull and not brilliant	Light pungent smell but freshly dried smell otherwise no decomposed smell shall be present	Moisture not exceeding 20%	Broken bits of spratts or any other fish or mixtue of other varieties of small fish shall not be more than 5%	Sand separated from fish shall go to make the tare

1	2	3	4
24.	Chevva Koelam	Lethrinus Aprion Lutianus Gaterina & Pristipoma	Cured with salt as Koelam and dried. May be with or witohut head.
25.	Jeela	Sphyraena	Split open or Keelams
26.	Valaikandam	Chirocentrus	Fish removed of guts. Cut into pieces. Cured with salt and dried.
27.	Thalapath	Misflophorus	Cured in the cut open form or as keelam or strips fillets (can be with or without head) as a whole fish or in pieces, if the fish is of a very large size.
28.	Magaracheri (shark strips without skin and bone)	Carcharinus sp.	Dressed flesh pieces of shark fish without bone or skin or fin and cured with salt and dried.
29.	Moothilla	Elacate sp.	Salt cured and dried in split open or as keelam with or without head.
30.	Pulunoo (Lapisa)	Lactarius sp.	Salt cured and dried in the round form with or without guts. May be cured also in the split open form.
31.	Thondaya salted & dried	Dussumeria sp.	Cured with salt the round form and dried.
32.	Bolan	Decapterus sp.	-do-
33.	Koli (unsalted)	Exocaetus sp.	Dried in the whole form no salt added.

5	6	7	8	9	10
Above 25 cm.	Light yellow to dark brown	Fresh cured flavour no bad odour shall be present	Moisture not exceeding 35%	Nil	—
Above 22.5 cm	Dark in colour	Freshly cured smell shall not have any decomposed odour	-do-	Nil	Keelams cut open longitudinally. Fish split and entrails removed shall be preferred.
Above 10 cm.	Whitish to dull brown	Fresh	-do-	Nil	—
Above 30 cm. in the whole fish form or as pieces as the case may be.	White or brown	Fresh	Moisture not exceeding 35%	Nil.	
Pieces above 10 cm.	White to ash grey or flesh coloured	Characteristic smell of shark flesh (lig-(lightly pungent)	-do-	Nil.	—
Above 15 cm.	White to ash grey.	Shall not be that of rancid or decomposed fish	Nosture not exceeing 35%	Nil.	—
—	Light dark in colour	Shall not be that of rancid or decomposed fish.	Moisture not exceed ing 35% by wt. max.	Nil.	—
Above 7 cm	-do-	-do-	Mosture not exceeding 30 %	Nil.	—
-do-	White to light dark	-do-	Moisture not exceeding 35%	Nil	Salt used at the time of packing to the extent of 4 % will be allowed but this will add to tare.
Above 8 cm.	Light blue to dark	-do-	Moisture not exceeding 25%	Nil.	—

1	2	3	4
34.	Koli (Salted)	Exocaetus Sp.	Salt cured in the round form and dried
35.	Salaya (oil sardine of Malabar)	Sardinella Longiceps	Cured with salt after removing the viscera and dried.
36.	Salaya	Sardinella gibbosa, Sardinella fimbriata, Sardinella albella, colie sp.	Cured with salt in the round form and dried. Guts not removed.
37.	Dried Bombay Duck	Harponden nehereus	Sundried or dried in artificial drier under hygienic condition.
38.	Laminated Bombay Duck	-do-	Prepared by suitable pressing of dried fish after removing head, fins and entails sides trimmed to get pieces of uniform size.
39.	Anguluwa small (Dubar)	Arius	Cut open longitudinally entrails removed and fish split open or keelams salted dried with or without head.
40.	Silver belly (mullen)	Leiognathus sp.	Salted or unsalted dried with head.
41.	Sole fish (Manthal)	Cynoglosus sp.	-do-
42.	Ribbon Fish	Trichiurus sp.	Whole fish cured with slat and dried.

5	6	7	8	9	10
Above 8 cm.	Light blue to dark	Shall not be that of rancid or decompasid fish	Moisture not exceeding 35%	Nil	Acid insoluble ash can be 5 % by wt.
Above 7 cm.	Greenish to brown	Shall not be that of rancid or decomposed fish	Moisture not exceed ing 30 %	Nil	Salt as crystal or powder used for packing shall not exceed 4% by wt. and will be added to tare.
Above 7 cm.	Greenish brown	-do-	Moisture not exceed ing 30 %	Nil	Salt as crystal or powder used for packing shall not exeed 4 % by wt and will be added to tare.
—	Characteristic colour free from any pink discolouration	Characteristic flavour free from any rancid odour	Moisture 25% by wt. maximum	—	Acid insoluble ash (on moisture free basis) max. 5%
Large 15 cm. & above above small less than 15 cm.	-do-	-do-	Moisture 20% by wt. max.	—	Acid insoluble ash (on moisture free basis 2.5 % max.)
Above 15 cm.	Whitish to dull brown	Fresh flavour of a cured fish	Moisture not exceeding 35%	Nil	—
—	Colour shall be shining white to white Characteristic of dried silver belly	Whole some dried fish smell and not pungent	Moisture shall not exceeding 35% for salted variety & 25% for unsalted vareity	Broken and fishes of other species shall not exceed 5%	Acid insoluble ash shall not exceed 2%
—	Characteristic brown to deep violet colour of dried sole fish	-do-	-do-	Nil	Acid insoluble asl shall not exceec 1.5 % by wt.
Above 30 cm.	Characteristic white colour of fresh dried ribbon	Wholesome dried fish small & not pungent	Moisture shall not exceed 35%	Nil	Acid insloluble asl shall not exceec 2% by wt.

ANNEXURE II

DRAFT RULES PROPOSED TO BE MADE UNDER SECTION 17 OF EXPORT (QUALITY CONTROL AND INSPECTION) ACT, 1963 (22 of 1963) IN SUPERSESSION OF THE EXPORT OF DRIED FISH (QUALITY CONTROL AND INSPECTION) RULES, 1970

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Export of Dried Fish (Inspection) Rules, 1984.

(2) They shall come into force after 60 days from the date of publication in the Official Gazette.

2. Definition—In these rules, unless the context otherwise requires :

(1) "Act" means the Export (Quality Control and inspection) Act, 1963 (22 of 1963);

(2) "Agency" means any one of the Agencies at Bombay Calcutta, Cochin, Delhi and Madras established under section 7 of the Act;

(3) "Council" means Export Inspection Council established under section 3 of the Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963;

(4) 'Dried Fish' means any of the trade varieties of dried fish as specified in t he schedule to these rules.

3. Basis of Inspection.—Inspection of dried fish intended for export shall be carried out with a view to seeing that the Dried Fish conforms to the specifications recognised by the Central Government under section 6 of the Act.

4. Procedure of Inspection.—(1) An exporter intending to export dried fish shall submit an application to the nearest office of the Agency, giving particulars of the consignment intended to be exported, to enable it to examine such consignment or cause the same to be examined to see whether the same conforms to the specifications referred to in rule 3;

(2) Evry application in sub-rule (1) shall be made not less than three days before the anticipated date of descpatch of the consignment from the exporters' premises for shipment.

(3) On receipt of the application referred to in sub-rule (2) the Agency shall inspect the consignment of Dried Fish as per the instructions issued by the Council in this behalf and satisfy itself that the consignment complies with the requirements of the recognised specifications. The exporter shall provide all necessary facilities to the Agency to enable it to carry out such inspection.

5. Certification.—If after inspection of the consignment, the Agency is satisfied that the same conforms to the recognised specifications and has been packed and marked according to these rules, it shall issue a certificate within three days from the date of inspection declaring the consignment as exportworthy. Provided that if the Agency is not so satisfied it shall within the said period of three days refuse to issue such certificate and communicate such refusal to the exporter along with the reasons thereof.

6. Packing and Marking for export.—(1) The dried fish shall be packed as specified in the export contract.

(2) In the absence of any agreement referred to in sub-rule (1) the same shall be packed in a manner as may be prescribed by the Council.

(3) Each package shall be marked with indelible ink or labelled with the following particulars :—

(a) Name and variety of the material;

(b) Net weight of contents and the gross weight of the packages;

(c) Shipping marks;

(d) Port of destination.

7. Place of Inspection.—(1) Inspection for the purpose of these rules shall be carried out at the exporters' premises which shall be well lighted and maintained in sanitary and hygienic conditions. Necessary facilities for weighing, packing and inspection shall be provided at the premises by the exporter.

(2) In addition to the inspection at the premises in sub-rule (i) the Agency shall have the right to reassess the quality of the consignment in the storage, in transit or at the ports, as it may consider necessary to carry out the purpose of these rules. In the event of the consignment being found not conforming to the recognised specifications at any of these stages, the certificate issued as per rule 5 shall be withdrawn.

8. Inspection fee.—A fee at the rate of 0.4% of the f.o.b. value of the consignment subject to a minimum of Rs. 50/- per consignment shall be paid to the Agency.

9. Appeal.—Any exporters a ggrieved by the refusal of the Agency to issue a certificate under rule 5 may within two days of the receipt of such refusal by him prefer an appeal to a Panel of Experts consisting of not less than three but not more than seven persons appointed by the Central Government.

At least two thirds of the total membership of the Panel of Experts shall consist of non-official. The quorum of the panel shall be three. The appeal shall be disposed of within 15 days of its receipt.

SCHEDULE

[See rule 2(4)]

Sl. No.	Variety	Scientific name (species)
1	2	3
1.	Seer	Cybium
2.	Angila	-do-
3.	Balaya	Thynnus
4.	Parawa	Caranx
5.	Katta	Chorinemuz
6.	Koduwa	Sciaena Pseudo-sciaena
7.	Lavaya	Serranus
8.	Sparatts/Anchovis	Stolephorus/Anchoville
9.	Valainetholi	Steolephorus tri
10.	Kooney (Jawla)	Penaeus (small)
11.	Prawns without shell	Penaeus, Metapenaeus, Parapenaeopsis
12.	Prawns with shell (Kardi)	Penaeus, Metapenaeus, Parapenaeopsist
13.	Shark	Carcharinus, Sphyrna, Pristis, Galeourda
14.	Maduwa	Trygon, Myliobatidae, Rhynchobatus, Rhinabatus
15.	Anguluwa	Arius
16.	Anguluwa (Tuticorin)	Arius
17.	Hurulla	Sardinella sirm
18.	Soodaya	Sardinella gibbosa
19.	Morollo	Hemirhamphus
20.	Venganawa	Pellona
21.	Parawa Small	Caranx
22.	Kumbalawa	Rastrelliger Kanagurta
23.	Thondaya Dried	Dussumeria
24.	Chevva Keelam	Lethrinus, Aprion, Lutianus, Gaterina & Pristipoma
25.	Jeela	Sphyraena
26.	Valaikandam	Chirocentrus
27.	Thalapath	Misfiophorus
28.	Magaracheri Carcharinus (shark strips without skin and bone)	Carcharinus sp.

1	2	3
29.	Moothilla	Elacate spp.
30.	Pulunno (Lapisa)	Lactarius spp.
31.	Thondaya salted and dried	Dussumeria spp.
32.	Bolan	Decapterus spp.
33.	Koli (unsalted)	Exocaetus
34.	Koli (salted)	-do-
35.	Salaya (Oil sardine of Malabar)	Sardinella Longiceps
36.	Salaya	Sardinella gibbosa, Sardinella fimbriate, Sardinella albella, colie spp.
37.	Dried Bombay Duck	Harpoden ne-hereus
38.	Lamintted Bombay Duck	-do-
39.	Anguluwa small (Dubar)	Arius
40.	Silver Belly (Mullen)	Leiognathus spp.
41.	Sole Fish (Manthal)	Cynoglosus spp.
42.	Ribbon fish	Trichiurus spp.

[F. No. 6/1/84-EI&EP]
N.S. HARIHARAN, Director

Foot Note
S.O. 2137 dated 5-6-1970

वाणिज्य मंत्रालय

(टैक्सटाइल विभाग)

नई दिल्ली, 22 दिसम्बर, 1984

का.आ. 26.—केन्द्रीय सरकार, सरकारी स्थान (अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) अधिनियम, 1971 (1971 का 40) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नीचे की सारणी के स्तम्भ (1) में उल्लिखित अधिकारी को, जो सरकार के राजपत्रित अधिकारी की पंक्ति के समतुल्य अधिकारी है, उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए संपदा अधिकारी नियुक्त करती है, जो उक्त सारणी के स्तम्भ (2) की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट सरकारी स्थानों की बाबत अपनी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर उक्त अधिनियम द्वारा या उसके अधीन सम्पदा अधिकारी को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करेगा और उसपर अधिरोपित कर्तव्यों का पालन करेगा।

सारणी

अधिकारी का पदनाम	सरकारी स्थानों के प्रवर्ग और अधिकारिता की स्थानीय सीमाएं
(1)	(2)
सचिव, ब्रुशवेयर लिमिटेड कानपुर	ब्रुशवेयर लिमिटेड कानपुर, लिमिटेड के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन स्थान

[फा. सं. 22/14/84-डब्ल्यू टी]
जे. के. बागची, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF COMMERCE

(Department of Textiles)

New Delhi, the 22nd December, 1984

S. O. 26.—In exercise of the powers conferred by section 3 of the Public Premises (Eviction of Unauthorised Occupants) Act 1971 (40 of 1971) the Central Government hereby appoints the officer mentioned in column (1) of the Table below being an officer equivalent to the rank of a Gazetted Officer of Government to be Estate Officer for the purposes of the said Act who shall exercise the powers conferred and perform the duties imposed on Estate Officer by or under the said Act within the local limits of his jurisdiction in regard to the Public Premises specified in the corresponding entry in column (2) of the said Table:—

THE TABLE

Designation of Officer	Category of Public Premises and local limits of the jurisdiction
(1)	(2)
Secretary Brushware Limited Kanpur.	Premises under the administrative control of Brushware Limited Kanpur.

[File No. 22/14/84-WT]
J.K. BAGCHI Jt. Secy.

उद्योग मंत्रालय

(भारी उद्योग विभाग)

नई दिल्ली, 5 दिसम्बर, 1984

आदेश

का.आ. 27:—उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 6 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एवं विकास परिषद (कार्यविधिक) नियम 1952 के नियम 2, 4 और 5 के साथ पढ़ते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा तेल और गैस का पता लगाने और उत्पादन उद्योग हेतु उपकरणों के लिए विकास परिषद गठित करती है और निम्नलिखित को उक्त परिषद का सदस्य नियुक्त करती है—

1. सचिव, भारी उद्योग विभाग	अध्यक्ष
2. महानिदेशक, तकनीकी विकास महानिदेशालय	सदस्य
3. अपर सचिव, (वाणिज्य)	सदस्य
4. अपर सचिव, आर्थिक कार्य विभाग	सदस्य
5. सलाहकार (आई. एण्ड एम.), योजना आयोग	सदस्य
6. सलाहकार (आर्थिक नीति एवं योजना पेट्रोलियम विभाग)	सदस्य
7. सलाहकार (तकनीकी) एवं पदेन संयुक्त सचिव, भारी उद्योग विभाग	सदस्य
8. संयुक्त सचिव, पेट्रोलियम विभाग	सदस्य

9. संयुक्त सचिव, औद्योगिक विकास विभाग — सदस्य
10. अध्यक्ष, तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग — सदस्य
11. अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, आयल इण्डिया लिमिटेड — सदस्य
12. अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, मझगांव डाक लिमिटेड — सदस्य
13. अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड — सदस्य
14. अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, भारत हैवी प्लेट एण्ड वेसल्स लिमिटेड — सदस्य
15. अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, इंजीनियर्स इण्डिया लिमिटेड — सदस्य
16. प्रबन्ध निदेशक, भारत पम्प एण्ड कम्प्रेसर्स लि. — सदस्य
17. परामर्शदाता, तेल उद्योग और विकास-बोर्ड — सदस्य
18. अध्यक्ष, तेल एवं गैस उपकरण प्रभाग, भारतीय इंजीनियरी उद्योग संघ — सदस्य
19. अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, के. जी. खोसला कम्प्रेसर्स लिमिटेड — सदस्य
20. अध्यक्ष, भारत स्टील ट्यूब्स, नई दिल्ली — सदस्य
21. श्री ए. के. सेन, औद्योगिक सलाहकार, तकनीकी विकास महानिदेशालय, नई दिल्ली — सदस्य-सचिव

अन्य सदस्यों को जैसा भी आवश्यक हो, अध्यक्ष की स्वीकृति से सहयोजित किया जा सकता है।

2. विकास परिषद के विचारार्थ विषय निम्नलिखित होंगे :—

(1) उत्पाद-श्रेणी, प्रौद्योगिकी और तेल तथा गैस क्षेत्र के लिए विकास कार्यक्रमों में सहभागिता के रूप में तेल और गैस उपकरण निर्माण उद्योग की स्थिति की समीक्षा करना।

(2) तेल और गैस उपकरण उद्योग की भारी वृद्धि के लिए परिप्रेक्ष्य योजना को बढ़ावा देना जिससे अधिक से अधिक औद्योगिक विकास और आयात प्रतिस्थापन किया जा सके।

(3) इस बात की जांच करना कि मानकीकरण किस सीमा तक प्राप्त कर लिया गया है और भारतीय मानक संस्था और तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग/आयल इण्डिया लिमिटेड के परामर्श से और आगे मानकीकरण के लिए विशिष्ट कार्यक्रमों का विकास करना।

(4) अन्तर्राष्ट्रीय बाजार की रूपरेखा पर विचार करना जिससे तेल और गैस उपकरणों के निर्यात को बढ़ाया जा सके।

(5) अनुसंधान तथा विकास के संबंध में राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं और उद्योग के स्तर पर समन्वित कार्यवाई को बढ़ावा देना।

(6) तेल और गैस उपकरण उद्योग की वृद्धि से संबंधित किसी अन्य संबंधित पहलू पर विचार करना।

3. विकास परिषद का कार्यकाल दो वर्ष का होगा।

4. स्थिति की समीक्षा करने के लिए इस विकास परिषद की छः महीनों में एक बार और यदि आवश्यकता हुई तो बारम्बार ऐसे स्थानों पर बैठक होगी जिनका निश्चय अध्यक्ष द्वारा किया जाएगा। यह परिषद इसके द्वारा किए गए मामलों के बारे में भारत सरकार को समय-समय पर रिपोर्ट देगी।

[फा. सं. I-(9)-2/84- टी. एस. डब्ल्यू.]

ए. सी. ढींगरा, सलाहकार (तकनीकी) एवं पदेन संयुक्त सचिव

MINISTRY OF INDUSTRY

(Department of Heavy Industry)

New Delhi, the 5th December, 1984

ORDER

S. O. 27.—In exercise of the powers conferred by Section 6 of the Industries (Development and Regulation) Act 1951 (65 of 1951) read with Rules 2, 4 and 5 of the Development Councils (Procedural) Rules 1952 the Central Government hereby constitutes the Development Council for Equipment for Oil and Gas Exploration and Production Industry and appoints the following to be the members of the said Council.

1.	Secretary, Deptt. of Heavy Industry.	Chairman
2.	Director General, Directorate General of Technical Development.	Member
3.	Addl. Secretary (Commerce)	Member
4.	Addl. Secretary, Department of Economic Affairs.	Member
5.	Adviser (I & M), Planning Commission.	Member
6.	Adviser (Economic Policy & Planning), Deptt. of Petroleum.	Member
7.	Adviser (Technical) & Ex-Officio Joint Secretary, Department of Heavy Industry.	Member
8.	Joint Secretary, Department of Petroleum.	Member
9.	Joint Secretary, Department of Industrial Development.	Member
10.	Chairman, Oil & Natural Gas Commission.	Member
11.	Chairman & Managing Director Oil India Ltd.	Member

12. Chairman & Managing Director, Mazagon Dock Ltd. — Member
13. Chairman & Management Director, Bharat Heavy Electricals Ltd. — Member
14. Chairman & Managing Director, Bharat Heavy Plate & Vessels Ltd. — Member
15. Chairman & Managing Director, Engineers India Ltd. — Member
16. Managing Director, Bharat Pumps & Compressors Ltd. — Member
17. Consultant, Oil Industry & Development Board. — Member
18. Chairman, Oil & Gas Equipment Division, Association of Indian Engineering Industry. — Member
19. Chairman & Managing Director, K.G. Khosla Compressors Ltd. — Member
20. Chairman, Bharat Steel Tubes, New Delhi. — Member
21. Shri A.K. Sen, Industrial Adviser, Directorate General of Technical Development. New Delhi. — Member-Secretary

Others members can be co-opted as necessary with the approval of Chairman.

2. The terms of reference of the Development Council would be as follows:—

(i) To review the status of the oil & gas equipment manufacturing industry in terms of product range technology and participation in the development programmes for the oil & gas sector.

(ii) To promote the perspective plan for the future growth of the oil & gas equipment industry so as to maximise industrial development and import substitution.

(iii) To examine the extent to which standardisation has been achieved and to evolve specific programmes for furtker standardisation in consultation with ISI and ONGC/OIL.

(iv) To consider the international market scenario so as to increase exports of oil & gas equipment.

(v) To promote coordinated action in regard to R & D at the level of national laboratories and industry.

(vi) To consider any other related aspect having a bearing on the growth of the oil & gas equipment industry.

3. The term of the Development Council will be 2 years.

4. This Development Council will meet to review the position once in six months and more frequently if occasion warrants at such places as may be decided by the Chairman. It will submit periodical reports to the Government of India about the matters handled by if.

[F.No.I(9)-2/84-TSW]

S.C. DHINGRA, Adviser (Technical) & Ex-officio Jt. Secy.

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय

(नागरिक पूर्ति विभाग)

भारतीय मानक संस्था

नई दिल्ली, 10 दिसम्बर, 1984

का. आ. 28.—भारत के राजपत्र भाग 2 खंड 3, उपखण्ड (ii) दिनांक 1981-05-16 में प्रकाशित तत्कालीन नागरिक पूर्ति मंत्रालय (भारतीय मानक संस्था) अधिसूचना संख्या एस ओ 1496 दिनांक 1981-04-23 का आंशिक रूप से संशोधन करते हुए भारतीय मानक संस्था द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि गहरे कुएं के बरमें की मानक चिन्ह का डिजाइन में संशोधन किया गया है।

मानक चिन्ह की यह संशोधित डिजाइन, शाब्दिक विवरण और तत्संबंधी भारतीय मानक के शीर्षक सहित नीचे अनुसूची में दी गई है।

भारतीय मानक संस्था/प्रमाणन चिन्ह अधिनियम 1952 और इसके अधीन बने नियमों और विनियमों के कार्यों के लिए यह मानक चिन्ह 1983-02-16 से लागू होगा।

अनुसूची

क्रम संख्या	मानक चिन्ह का डिजाइन	उत्पाद/उत्पाद की श्रेणी	तत्संबंधी भारतीय मानक की संख्या और शीर्षक	मानक चिन्ह की डिजाइन और शाब्दिक विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	ISI : 9301	गहरे कुओं के बरमे	IS : 9301—1982 गहरे कूएं के बरमों की विशिष्टि (प्रथम पुनरीक्षण)	भारतीय मानक संस्था का मोनोग्राम जिसमें "ISI" शब्द होते हैं स्तम्भ 2 में दिखाई गई शैली और अनुपात में तैयार किया गया है और जैसा डिजाइन में दिखाया है इस मोनोग्राम के ऊपर की ओर भारतीय मानक की पद संख्या दी गई है।

[सं. सीएमडी/13 : 9]

ए. एस. चीमा, अपर महानिदेशक

MINISTRY OF FOOD AND CIVIL SUPPLIES

(Department of Civil Supplies)

INDIAN STANDARDS INSTITUTION

New Delhi, the 10th December, 1984

S.O. 28.—In partial modification of the then Ministry of Civil Supplies (Indian Standards Institution) notification number S.O. 1496 dated 1981-04-23 published in the Gazette of India, Part-II, Section-3, Sub-section (ii) dated 1981-05-16 the Indian Standards Institu-

tion, hereby, notifies that the design of the Standard Mark for deep well hand pumps has been revised. The revised design of the Standard Mark together with the title of the relevant Indian Standard and verbal description of the design is given in the following Schedule.

This Standard Mark for the purpose of the Indian Standards Institution (Certification Marks) Act, 1952 and the Rules and Regulations framed thereunder, shall come into force with effect from 1983-02-16.

SCHEDULE

Sl. No.	Design of the Standard Mark	Product/Class of Product	No. & Title of the Relevant Indian Standard	Verbal Description of the Design of the Standard Mark
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	IS : 9301 IS:9301 ISI	Deep well hand pumps	IS : 9301-1982 Specification for deep well hand pumps (First Revision).	The monogram of the Indian Standards Institution, consisting of letters 'ISI', drawn in the exact style and relative proportions as indicated in Col. (2); the number of the Indian Standard being superscribed on the top side of the monogram as indicated in the design.

[No. CMD/13:9]
A. S. CHEEMA, Addl. Director General

रसायन और उर्वरक मंत्रालय

नई दिल्ली, 17 अक्तूबर, 1984

का. आ. 29—सार्वजनिक परिसर (गैर कानूनी कब्जे की बेदखली) अधिनियम, 1971 (1971 का 40) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा निम्न तालिका के कालम (1) में उल्लिखित अधिकारी जो सरकार के राजपत्रित अधिकारी की श्रेणी के समस्तर का अधिकारी है, जो उक्त अधिनियम के प्रयोजनार्थ सम्पदा अधिकारी नियुक्त करती है जो उक्त तालिका के कालम (2) में निर्दिष्ट सार्वजनिक परिसर के संबंध में उक्त अधिनियम के द्वारा अथवा उसके अधीन सम्पदा अधिकारी को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करेगा और उसे सौंपे गए दायित्वों को पूर्ण करेगा।

तालिका

अधिकारी का पदनाम	सार्वजनिक परिसर की श्रेणी
1	2
कार्मिक अधिकारी, सामान्य प्रशासन इंडियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्युटिकल लि., दिल्ली।	दिल्ली, नई दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता मद्रास, बंगलौर, हैदराबाद, लखनऊ, चंडीगढ़, अहमदाबाद, जयपुर, इंदौर पटना, कोचीन, और करनाल में आई डी पी एल द्वारा अथवा उनकी ओर से अपने कर्मचारियों के आवासीय प्रयोग हेतु पट्टे पर लिये गये अथवा इससे संबंधित सभी परिसर

[फा.सं. एल-38022/17/78-डी वी]
बी.सी. मुर्गेसन, अवर सचिव

MINISTRY OF CHEMICALS & FERTILIZERS

New Delhi, the 17th October, 1984

S. O. 29.—In exercise of the powers conferred by section 3 of the public premises (Eviction of un-authorised occupants) ACT, 1971 (40 of 1971), the Central Government hereby appoints the officer mentioned in column (1) of the Table below, being an officer equivalent, to the rank of a gazetted officer of Government, to be the Estate Officer, for the purposes of the said Act who shall exercise the powers conferred, and perform the duties imposed, on Estate Officer by or under the said Act in respect of the Public premises specified in column (2) of the said Table.

TABLE

Designation of the Officer	Categories of public premises
1	2
Personnel Officer, General Administration, Indian Drugs and Pharmaceuticals Limited, Delhi.	All premises belonging to or taken on lease at Delhi/New Delhi, Bombay, Calcutta Madras, Bangalore, Hyderabad, Lucknow, Chandigarh, Ahmedabad, Jaipur, Indore, Patna, Cochin and Karnal by or on behalf of the Indian Drugs and Pharmaceuticals Limited for the residential use of its employees.

[F. No. L-38022/17/78-DV]
B. C. MURUGESAN, Under Secy.

ऊर्जा मंत्रालय

(पैट्रोलियम विभाग)

नई दिल्ली, 22 दिसंबर, 1984

का. आ. 30.—यत: पैट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय, पैट्रोलियम विभाग की अधिसूचना का. आ. सं. 3663 तारीख 30-1084-द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था।

और यत: सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

1267 GI|84—5

और आगे यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है।

अब, अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख से निहित होगा।

अनुसूची

विजयपुर (म.प्र.) से सवाई माधोपुर (राज.) तक पाईप लाईन बिछाने के लिए

राज्य राजस्थान जिला सवाई माधोपुर तहसील सवाई माधोपुर

गांव	खसरा नं.	हेक्टर	आर	सेंटीआर
बिलोपा	466	0	07	80
	467/1	0	12	00
	508	0	16	20
	532/1	0	06	20
	532/1078	0	00	80
	532/1077	0	24	00

[सं. O-14016/44/84-जीपी]

MINISTRY OF ENERGY

(Department of Petroleum)

New Delhi, the 22nd December, 1984

S.O. 30.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Energy, Department of Petroleum S.O. 3663 dated 30th Oct. 1984 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the land specified in the schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline,

And, whereas, the Competent Authority has under Sub-Section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And, further, whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And, further, in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests from this date of the publication of this declaration in the Oil & Natural Gas Commission free from encumbrances.

SCHEDULE

Pipeline from Bijapur (M.P.) to Sawai Madhopur (Raj.)

State : Rajasthan District : Sawai Madhopur

Tehsil : Sawai Madhopur

Village	Survey No.	Hectare	Are	Centiare
Bilopa	466	0	07.	80
	467/1	0	12	00
	508	0	16	20
	532/1	0	06	20
	532/1078	0	00	80
	532/1077	0	24	00

[No. O-14016/44/84-GP]

का. आ. 31.—यतः पैट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय, पैट्रोलियम विभाग की अधिसूचना का. आ. सं. 3661 तारीख 30-10-84 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था।

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और आगे यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है।

अब, अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा, (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख से निहित होगा।

अनुसूची

विजयपुर (म.प्र.) से सवाई माधोपुर (राज.) तक पाईप लाईन बिछाने के लिए

राज्य : राजस्थान जिला : सवाई माधोपुर तहसील सवाई माधोपुर

गांव	खसरा नं.	हेक्टेर	आर	सेंटीआर
डेकवा	4	0	00	76
	11	0	29	02
	13	0	11	64
	14	0	14	13
	15	0	14	25
	16	0	16	50
	27	0	04	20
	29	0	04	98
	30	0	16	27
	31	0	14	93
	32	0	17	14

54	0	04	64
33	0	33	60
34	0	02	40
62	0	08	97
68	0	34	50
69	0	15	22
70	0	38	81
71	0	00	24
99	0	52	80
100	0	02	00

[सं. O-14016/45/84-जीपी]

S.O. 31.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Energy, Department of Petroleum S.O. 3664 dated 30-10-84 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the land specified in the schedule appended to the notification for the purpose of laying pipeline;

And, whereas, the Competent Authority has under Sub-Section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And, further, whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And, further, in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests from this date of the publication of this declaration in the Oil & Natural Gas Commission free from encumbrances.

SCHEDULE

Pipeline from Bijaipur (M.P.) to Sawai Madhopur (Raj.)

State : Rajasthan District : Sawai Madhopur

Tehsil : Sawai Madhopur

Village	Survey No.	Hectare	Are	Centiare
Dhekawa	4	0	00	76
	11	0	29	02
	13	0	11	64
	14	0	14	13
	15	0	14	25
	16	0	16	50
	27	0	04	20
	29	0	04	98
	30	0	16	27
	31	0	14	93
	32	0	17	14
	33	0	33	60
	34	0	02	04
	62	0	08	97
	68	0	34	50
	69	0	15	22
	70	0	38	81
	71	0	00	24
	99	0	52	80
	100	0	02	00

[No. O-14016/45/84-GP]

का. आ. 32.—यत: पैट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय, पैट्रोलियम विभाग की अधिसूचना का. आ. सं. 2398 तारीख 12-7-84 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाईप लाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था।

और यत: सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और आगे यत: केन्द्रीय सरकार ने उक्त भूमियों पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है।

अब, अत: उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाईपलाईन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा।

अनुसूची

कोयली से बरेली से जगदीशपुर तक पाइप लाइन बिछाने के लिए।

राज्य : गुजरात जिला : बड़ोदरा तालुका : डभोई

गांव	सर्वे नं.	हेक्टेयर	ए आर ई	सेंटीयर
बायदपुर	7	0	01	12
	8	0	35	96
	10	0	24	16
	18	0	13	72
	19/1	0	02	08
	19	0	11	56
	17	0	05	76
	21	0	10	20
	22	0	20	48
	29	0	18	56
	28	0	10	18
	18पी	0	16	00
	48	0	02	08
	49	0	00	48
	17	0	10	24
	46	0	22	88
	50	0	27	08
	51	0	18	24
	52	0	22	24
	53	0	03	04
	54	0	04	64
	323	0	27	48

[सं. O-12016/69/84-ओ एन जी डी-4/ऊर्जा प(1)]

S.O. 32.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Energy, Department of Petroleum S.O. 2398 dated 12-7-84 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline;

And, whereas, the Competent Authority has under Sub-Section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And, further, whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And, further, in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests from this date of the publication of this declaration in the Oil & Natural Gas Commission free from encumbrances.

SCHEDULE

Pipeline from Hajira-Bareilly-Jagdishpur

State : Gujarat District : Vadodara Taluka : Dabhoi

Village	Survey No.	Hectare	Are	Centiare
Vayadpura	7	0	01	12
	8	0	35	96
	10	0	24	16
	18	0	13	72
	19/1	0	02	08
	19	0	11	56
	17	0	05	76
	21	0	10	20
	22	0	20	48
	29	0	18	56
	28	0	10	28
	48/P	0	16	00
	48	0	02	08
	49		00	48
	47	0	10	24
	46	0	22	88
	50	0	27	08
	51	0	18	24
	52	0	22	24
	53	0	03	04
	54	0	04	64
	323	0	27	48

[No. O-12016/69/84-ONG-D-4/GP]

का. आ. 33.—यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाईन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय, पैट्रोलियम विभाग की अधिसूचना का. आ. सं. 3671 तारीख 30-10-84 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग के अधिकार को पाईप लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था।

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और आगे यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है।

अब, अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाईन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख से निहित होगा।

अनसूची

विजयपुर (म.प्र.) से सवाई माधोपुर (राज.) तक पाईपलाईन बिछाने के लिए

राज्य : राजस्थान जिला : बूंदी तहसील : केशोराय पाटन

सब-तहसील : इन्द्रगढ़ पाटन

गांव	खसरा नं	हेक्टर		सेंटीआर
अभयपुरा	12	0	06	60
	13	0	32	90
	15	0	01	50
	17	0	07	30
	17/232	0	02	40
	18	0	07	00
	19	0	04	10
	20	0	09	40
	27/218	0	10	70
	27/219	0	12	40
	29	0	02	90
	32	0	16	50
	33	0	21	50
	50	0	04	20
	177	0	06	30
	178	0	57	70
	181	0	00	90
	182	0	28	90
	186	0	24	10
	187	0	18	00
	188	0	16	80
	196	0	04	40
	198	0	13	20
	199	0	28	90
	200	0	14	90
	201	0	93	20
	202	0	15	00
	205	0	12	00
	29/217	0	13	80

[सं. O-14016/101/84-जी पी]

S.O. 33.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Energy, Department of Petroleum S.O. 3671 dated 30-10-84 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the land specified in the schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline;

And, whereas, the Competent Authority has under Sub-Section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And, further, whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the Schedule appended to this Notification hereby acquired for laying the pipeline;

And, further, in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests from this date of the publication of this declaration in the Oil & Natural Gas Commission free from encumbrances.

SCHEDULE

Pipeline from Bijaipur (M.P.) to Sawai Madhopur (Raj.)

State : Rajasthan District : Bundi Tehsil : Keshorai Patna Sub. Teh. Indar Garh

Village	Survey No.	Hectare	Are	Centiare
Abhay Pura	12	0	06	60
	13	0	32	90
	15	0	01	50
	17	0	07	30
	17/232	0	02	40
	18	0	07	00
	19	0	04	10
	20	0	09	40
	27/218	0	10	70
	27/219	0	12	40
	29	0	02	90
	32	0	16	50
	33	0	21	60
	50	0	04	20
	177	0	06	30
	178	0	57	70
	181	0	00	90
	182	0	28	90
	186	0	24	10
	187	0	18	00
	188	0	16	80
	196	0	04	40
	198	0	13	20
	199	0	28	90
	200	0	14	90
	201	0	93	20
	202	0	15	00
	205	0	12	00
	29/217	0	13	80

[No. O-14016/101/84-GP]

का. आ. 34.—यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय, पेट्रोलियम विभाग की अधिसूचना का. आ. सं. 3672 तारीख 30-10-84 के द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था ;

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है ;

और आगे यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है ;

अब अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाईन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है ,

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग में सभी बाधाओं से मुक्त रूप से घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख से निहित होगा।

अनुसूची

विजयपुर (म.प्र.) से सवाई माधोपुर (राज.) तक पाइपलाइन बिछाने के लिए

राज्य : राजस्थान जिला : बूंदी तहसील : केशोराय पाटन सब-तहसील : इंद्रगढ़

गांव	खसरा नं.	हेक्टर	आर	सेंटआर
डोवरला	1	1	48	00
	6	0	13	50
	8	0	04	00
	60	0	69	90
	63	0	53	30
	64	0	16	50
	84	0	06	50
	85	0	28	60
	83	0	13	70
	60/214	0	62	30
	60/216	0	02	20
	80	0	01	50
	68	0	04	50
	79	0	03	30

[सं. O-14016/102/84-जी पी]

S.O. 34.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Energy, Department of Petroleum S.O. 3672 dated 30-10-84 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the land specified in the schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline;

And, whereas, the Competent Authority has under Sub-section (1) of Section 6 of t the said Act, submitted report to the Government;

And, further, whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the Schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the Schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And, further, in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in the Central Government vests from this date of the publication of this declaration in the Oil & Natural Gas Commission free from encumbrances.

SCHEDULE

Pipeline from Bijaipur (M.P.) to Sawai Madhopur (Raj.)
State : Rajasthan Dsitrict : Bundi Tehsil : Keshorai Patan
Sub. Teh. : Indar Garh

Village	Survey No.	Hectare	Are	Centiare
Dobarli	1	1	48	00
	6	0	13	50
	8	0	04	00
	60	0	69	90
	63	0	53	30
	64	0	16	50
	84	0	06	50
	85	0	28	60
	83	0	13	70
	60/214	0	62	30
	60/216	0	02	20
	80	0	01	50
	68	0	04	50
	79	0	03	30

[No. O-14016/102/84-GP]

का. आ. 35—यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय, पेट्रोलियम विभाग की अधिसूचना का. आ. सं. 3673 तारीख 30-10-84 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाईप लाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था।

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और आगे यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है।

अब, अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख से निहित होगा।

अनुसूची

विजयपुर (म.प्र.) से सवाई माधोपुर (राज.) तक पाइप लाइन बिछाने के लिए

राज्य : राजस्थान जिला : बूंदी तहसील : केशोराय पाटन सब-तहसील : इंद्रगढ़

गांव	खसरा नं.	हेक्टर	आर	सेंटीआर
1	2	3	4	5
किशनपुरा	12	0	28	40
	17/115	0	06	20
	14	0	02	20
	15	0	09	70
	16	0	54	50
	17/1	0	04	50
	17/2	0	13	10
	83	0	48	30
	84	0	14	10
	86	0	24	50
	92	0	23	20
	91/119	0	01	20
	102	0	40	60
	103	0	16	70
	91/129	0	34	70
	91	0	11	40

[सं. O-14016/103/84-जी पी]

S.O. 35.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Energy, Department of Petroleum S.O. 3673 dated 30-10-84 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the land specified in the schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline;

And, whereas, the Competent Authority has under Sub section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And, further, whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the Schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the Schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline:

And, further, in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests from this date of the publication of this declration in the Oil & Natural Gas Commission free from encumbrances.

SCHEDULE

Pipeline from Bijaipur (M.P.) to Sawai Madho pur (Raj.)
State : Rajasthan District : Bundi Tehsil : Keshorai Patan
Sub. Teh. : Indar Garh

Village	Survey No.	Hectare	Are	Centiare
Kishanpura	12	0	28	40
	17/115	0	06	20
	14	0	02	20
	15	0	09	70
	16	0	54	50
	17/1	0	04	50
	17/2	0	13	10
	83	0	48	30
	84	0	14	10
	86	0	24	50
	92	0	23	20
	91/119	0	01	20
	102	0	40	60
	103	0	16	70
	91/129	0	34	70
	91	0	11	40

[No. O-14016/103/84-GP]

का. आ. 36.—यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय, पेट्रोलियम विभाग की अधिसूचना का. आ. सं. 3674 तारीख 30-10-84 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था।

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और आगे यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है।

अब, अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख से निहित होगा।

अनुसूची

बिजयपुर (म.प्र.) से सवाई माधोपुर (राज.) तक पाइप लाइन बिछाने के लिए
राज्य : राजस्थान जिला : बूंदी तहसील : केशोराय पाटन सब-तहसील : इंद्रगढ़

गांव	खसरा नं.	हैक्टर	आर	सेंटीआर
नान्ता	3	1	90	00
	85	0	12	90
	86	1	82	40
	86/262	0	02	10
	112	0	06	60
	114	0	39	30
	114/263	0	19	80
	116	0	00	10
	140	0	02	40
	117/289	0	18	20
	117	0	03	40
	118	0	17	00
	205	0	23	70
	207	0	43	50

[सं. O-14016/106/84-जी.पी.]

S.O. 36.—Whreas by notification of the Government of India in the Ministry of Energy, Department of Petroleum S.O. 3674 dated 30-10-84 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the land specified in the schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline;

And, whereas, the Competent Authority has under Sub-section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification.

Now, therefore, in exercise of the pover conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the Schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And, further, in exercise of power conferred by sub-section (4) of that setion, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests from this date of the publication of this declaration in the Oil & Natural Gas Commission free from encumbrances.

SCHEDULE

Pipeline from Bijaipur (M.P.) to Sawai Madhopur (R)
State : Rajasthan District : Bundi Teshil : Keshorai Patan
Sub Teh. : Indar Garh

Village	Survey No.	Hectare	Are	Centiare
Nanta	3	1	9	00
	85	0	12	90
	86	1	85	40
	86/262	0	02	10
	112	0	06	60
	114	0	39	30
	114/263	0	19	80
	116	0	00	10
	140	0	02	40
	117/289	0	18	20
	117	0	03	40
	118	0	17	00
	205	0	23	70
	207	0	43	50

[No. O-14016/106/84-GP]

का. आ. 37.—यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाईन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के ऊर्जा मन्त्रालय, पेट्रोलियम विभाग की अधिसूचना का. आ. सं. 3690 तारीख 30-10-84 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था।

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और आगे यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है।

अब, अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख से निहित होगा।

अनुसूची

बिजयपुर (म. प्र.) से सवाई माधोपुर (राज.) तक पाईप लाईन बिछाने के लिए

राज्य—राजस्थान जिला—टोंक तहसील—उनियारा

गांव	खसरा नं.	हेक्टर	आर	सेंटीआर
रिजोंदा	35	0	42	30
	36	0	09	20
	33	0	19	30
	40	0	38	50
	11	0	14	50
	38	0	04	00
	58	0	08	90
	42	0	00	50
	43	0	10	60
	44	0	73	00
	48	0	00	20
	47	0	53	40
	95	0	21	00
	96	0	32	40
	95/464	0	07	20
	97	0	03	30
	98	0	02	60
	111	0	45	90
	107	0	33	80
	104/465	0	03	90
	104	0	17	70
	103	0	21	40
	105	0	12	90

[सं. O-14016/147/84 जी० पी०]

S.O. 37.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Energy, Department of Petroleum S.O. 3690 dated 30-10-84 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the Schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline ;

And, whereas, the Competent Authority has under Sub-section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And, further, whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the Schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the Shedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline ;

And, further, in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests from this date of the publication of this declaration in the Oil & Natural Gas Commission free from encumbrances.

SCHEDULE

Pipeline from Bijaipur (M.P.) to Sawai Madhopur (Raj.)

State : Rajasthan District : Tonk Teshil : Uniyara

Village	Survey No.	Hectare	Are	Centiare
Rejonda	35	0	42	30
	36	0	09	20
	33	0	19	30
	40	0	31	50
	41	0	14	50
	38	0	04	00
	58	0	08	90
	42	0	00	50
	43	0	10	60
	44	0	73	00
	48	0	00	20
	47	0	53	40
	95	0	21	00
	96	0	32	40
	95/464	0	07	20
	97	0	03	30
	98	0	02	60
	111	0	45	90
	107	0	13	80
	104/465	0	03	90
	104	0	17	70
	103	0	21	40
	105	0	12	90

[No. 0-14016/147/84-GP]

का. आ. 38 :—यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के ऊर्जा मन्त्रालय, पेट्रोलियम विभाग की अधिसूचना का. आ. सं. 3691 तारीख 30-10-84 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था।

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और आगे यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है।

अब, अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार निदेश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख से निहित होगा।

अनुसूची

विजयपुर (म. प्र.) से सवाई माधोपुर (राज.) तक पाईप लाईन बिछाने के लिए

राज्य-राजस्थान जिला—टौंक तहसील—उनियारा

गांव	खसरा नं.	हेक्टर	आर	सेंट आर
बिशनपुरी	1	0	11	70
	37	0	11	10
	38	0	23	40
	39	0	25	00
	40	0	25	20
	68	0	43	20
	66	0	61	00
	67	0	15	60
	108	0	39	00
	107	0	07	10
	106	0	07	60
	105	0	31	50
	104	0	34	20
	75	0	15	90
	76	0	29	70
	80	0	01	80
	95	0	35	00
	96	0	17	10
	91	0	13	50
	90	0	09	00
	89	0	32	60
	85	0	28	50
	87	0	00	80
	86	0	15	90

[सं. O-14016/148/84-ज. प.]

SCHEDULE

Pipeline from Bijaipur (M.P.) to Sawai Madhopur (Raj.)

State : Rajasthan District : Tonk Tehsil : Uniyara

Village	Survey No.	Hectare	Are	Centiare
Bishanpur	1	0	11	70
	37	0	11	10
	38	0	23	40
	39	0	25	00
	40	0	25	20
	68	0	43	20
	66	0	61	00
	67	0	15	60
	108	0	39	00
	107	0	07	10
	106	0	07	60
	105	0	31	50
	104	0	34	20
	75	0	15	90
	76	0	29	70
	80	0	01	80
	95	0	35	00
	96	0	17	10
	91	0	13	50
	90	0	09	30
	89	0	32	60
	85	0	28	50
	87	0	00	80
	86	0	15	89

[N. O-14016/148/84-GP]

S.O. 38.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Energy, Department of Petroleum S.O. 3691 dated 30-10-84 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the land specified in the schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline.

And, whereas, the Competent Authority has under Sub-Section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And, further, whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And, further, in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests from this date of the publication of this declaration in the Oil & Natural Gas Commission free from encumbrances.

का. आ. 39.—यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाईन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के ऊर्जा मन्त्रालय, पेट्रोलियम विभाग की अधिसूचना का. आ. सं. 3692 तारीख 30-10-84 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था।

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और आगे यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है।

अब, अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइप लाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख से निहित होगा।

अनुसूची

बिजयपुर (म.. प्र.) से सवाई माधोपुर (राज.) तक पाईप लाईन बिछाने के लिए

राज्य–राजस्थान जिला–टोंक तहसील–उनियारा

गांव	खसरा नं.	हेक्टर	आर	सेंटआर
रघुनाथपुरा	46	0	29	40
	44	0	04	80
	43	0	32	50
	42	0	09	10
	47/2	0	02	10
	41	0	16	20
	40	0	44	90
	40/50	0	00	50
	37	0	01	00
	85	0	06	20
	34	0	22	40
	33	0	05	20
	25	0	07	20
	32	0	01	80
	26	0	08	60
	31	0	06	00
	30	0	01	50
	27	0	10	80
	49	0	60	30
	49/1/4	0	16	80
	49/1/1	0	84	00

[सं. O-14016/149/84-जी प]

S.O. 39.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Energy, Department of Petroleum S.O. 3692 dated 30-10-84 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the land specified in the Schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline;

And, whereas, the Competent Authority has under Sub-Section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And, further, whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the Shedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And, further, in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests from this date of the publication of this declaration in the Oil & Natural Gas Commission free from encumbrances.

SCHEDULE

Pipeline from Bijaipur (M.P.) to Sawai Madhopur (Raj.)

State : Rajasthan District : Tonk Tehsil : Uniyara

Village	Survey No.	Hectare	Are	Centiare
1	2	3	4	5
Raghunathpura	46	0	29	40
	44	0	04	80
	43	0	32	50
	42	0	09	10
	47/2	0	02	10
	41	0	16	20
	40	0	44	90
	40/50	0	00	50
	37	0	01	00
	35	0	06	20
	34	0	22	40
	33	0	05	20
	25	0	07	20
	32	0	01	80
	26	0	08	60
	31	0	06	00
	30	0	01	50
	27	0	10	80
	49	0	60	30
	49/1/4	0	16	80
	49/1/1	0	84	00

[No. O-14016/149/84-GP]

का. आ 40.—पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाईन भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन अधिनियम 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय पेट्रोलियम विभाग की अधिसूचना का. आ. सं. 3700 तारीख 30-10-84 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था।

और यत: सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और आगे यत: केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है।

अब, अत: उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्-द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के लिए प्रयोजन एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख से निहित होगा।

अनुसूची

बिजयपुर (म. प्र.) से सवाई माधोपुर (राज.) तक पाईप लाईन बिछाने के लिए

राज्य—राजस्थान, जिला—टोंक, तहसील—उनियारा

गांव	खसरा नं.	हेक्टर	आर	सेंटीआर
पचाली	141	0	07	00
	140	0	04	50
	137	0	52	50
	138	0	69	40
	125	0	06	80
	152	0	20	00
	154	0	57	00

1	2	3	4
153	0	01	60
172	0	42	70
180	0	18	60
174	0	05	00
181	0	36	30
182	0	05	10
183	0	13	80
184	0	06	00
190	0	42	60
185	0	17	90
185/312/2/1	0	11	10
185/312/2	0	05	50
187	0	29	20
186	0	64	90
304	0	82	60
303	0	15	20

[सं. O-14016/157/84-जी पी]

S.O. 40.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Energy, Department of Petroleum S.O. 3700 dated 30-10-84 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the land specified in the schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline;

And, whereas, the Competent Authority has under Sub-Section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And, further, whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And, further, in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests from this date of the publication of this declaration in the Oil and Natural Gas Commission free from encumbrances.

SCHEDULE

Pipeline from Bijaipur (M.P.) to Sawai Madhopur (Raj.)

State : Rajasthan District : Tonk Tehsil : Uniyara

Village	Survey No.	Hectare	Are	Centiare
1	2	3	4	5
Pachali	141	0	07	00
	140	0	04	50
	137	0	52	50
	138	0	69	40
	125	0	06	80
	152	0	20	00
	154	0	57	00
	153	0	01	60
	172	0	42	70
	180	0	18	60
	174	0	05	00
	181	0	36	30
	182	0	05	70
	183	0	13	80
	184	0	06	00
	190	0	42	60
	185	0	17	90
	185/312/2/1	0	11	10
	185/312/2	0	05	50
	187	0	29	20
	186	0	62	90
	304	0	82	60
	303	0	15	20

[No. 0-14016/157/84-GP]

का. आ. 41:—यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाईन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय, पेट्रोलियम विभाग की अधिसूचना का. आ. सं. 3702 तारीख 30-10-84 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था।

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और आगे यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है।

अब, अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख से निहित होगा।

अनुसूची

बिजयपुर (म. प्र.) से सवाई माधोपुर (राज.) तक पाईप लाईन बिछाने के लिए

राज्य—राजस्थान . . . .जिला—टोंक . . . .तहसील—उनियारा

गांव	खसरा नं.	हैक्टर	आर	सेंटीआर
इब्राहिम गंज	20	0	21	60
	21	0	09	20
	16	0	07	20
	17	0	02	20
	18	0	01	70
	23	0	00	80
	24	0	01	70
	25	0	02	40
	26	0	36	80
	45	0	08	40
	27	0	07	60
	29	0	00	50

[सं. O-14016/159/84-जी पी]

S.O. 41.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Energy, Department of Petroleum S.O. 3702 dated 30-10-84 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the land specified in the schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline;

And, whereas, the Competent Authority has under Sub-Section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And, further, whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the Schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And, further, in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests from this date of the publication of this declaration in the Oil & Natural Gas Commission free from encumbrances.

SCHEDULE

Pipeline from Bijaipur (M.P.) to Sawai Madhopur (Raj.)

State : Rajasthan District : Tonk Tehsil : Uniyara

Village	Survey No.	Hectare	Are	Centiare
Ibrahimganj	20	0	21	60
	21	0	09	20
	16	0	07	20
	17	0	02	20
	18	0	01	70
	23	0	00	80
	24	0	01	70
	25	0	02	40
	26	0	36	80
	45	0	08	40
	27	0	07	60
	29	0	00	50

[No. O-14016/159/84-G.P.]

का. आ. 42:—यत: पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन, अधिनियम 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय, पेट्रोलियम विभाग की अधिसूचना का. आ. सं. 3708 तारीख 30-10-84 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था।

और यत: सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और आगे यत: केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है।

अब, अत: उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख से निहित होगा।

अनुसूची

बिजयपुर (म. प्र.) से सवाई माधोपुर (राज.) तक पाइप लाइन बिछाने के लिए

राज्य—राजस्थान जिला—टोंक तहसील—उनियारा

गांव	खसरा नं.	हेक्टर	एयर	सेंटीआर
नयागंज	50/1/2	0	22	80
	50/3	0	05	10
	50/4	0	13	50
	50/2	0	06	90
	49	0	01	80
	48	0	00	20
	40	0	07	90
	47	0	01	90
	46	0	10	60
	44	0	04	40
	45	0	19	10
	60	0	13	70
	61	0	03	80
	63	0	03	00
	62	0	12	90
	99	0	07	20
	100	0	02	00
	12/12	0	00	70
	105/1	0	30	90
	103	0	73	20
	105	0	67	30
	105/3	0	01	50
	41	0	02	00
	107	0	02	00

[सं. ओ०-14016/166/84-जी पी]

S.O. 42.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Energy, Department of Petroleum S.O. 3708 dated 30-10-84 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the land specified in the schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline;

And, whereas, the Competent Authority has under Sub-Section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And, further, whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And, further, in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests from this date of the publication of this declaration in the Oil & Natural Gas Commission free from encumbrances.

SCHEDULE

Pipeline from Bijaipur (M.P.) to Sawai Madhopur (Raj.)
State : Rajasthan District : Tonk Tehsil : Uniyara

Village	Survey No.	Hectare	Are	Centiare
Nawahganj	50/1/2	0	22	80
	50/3	0	05	40
	50/4	0	13	50
	50/2	0	06	90
	49	0	01	80
	48	0	00	20
	40	0	07	90
	47	0	02	90
	46	0	10	60
	44	0	04	40
	45	0	19	10
	60	0	13	70
	61	0	03	80
	63	0	03	00
	62	0	12	90
	99	0	07	20
	100	0	02	00
	12/12	0	00	70
	105/1	0	30	90
	103	0	73	20
	105	0	67	30
	105/3	0	01	50
	41	0	02	00
	107	0	02	00

[No. O–14016/166/84-GP]

का. आ. 43 :—यत: पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाईन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय, पेट्रोलियम विभाग की अधिसूचना का. आ. सं. 3709 तारीख 30-10-84 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था।

और यत: सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और आगे यत: केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है।

अब, अत: उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन इस तारीख से निहित होगा।

अनुसूची

विजयपुर (म० प्र०) से सवाई माधोपुर (रा०) तक पाईप लाईन बिछाने के लिए

राज्य—राजस्थान जिला—टोंक तहसील—उनियारा

गांव	खसरा नं.	हेक्टर	आर	सेंटीआर
पचाला	94	0	34	50
	95	0	29	10
	92	0	01	20
	98/1	0	63	00
	98/2	0	31	50
	99	0	15	60
	99/1317	0	14	40
	110	0	03	10
	1060/2	0	08	40
	1060/1	0	08	40
	1062	0	05	10
	1067/4	0	39	10
	1067/1/1/1	0	26	60
	1067/3	0	17	40
	1067/11	0	18	90
	1066	0	12	00
	1144/1/2	0	10	10
	1144/3/2	0	42	60
	1144/10	0	12	00
	1145	0	12	90
	1149	0	17	70
	1147	0	01	90
	1148	0	01	00
	1150	0	05	10
	1153	0	27	70
	1152	0	04	50
	1186	0	11	40
	1188	0	23	30
	1187	0	05	70
	1214	0	03	70
	1229	0	04	00
	1227	0	13	60
	1228	0	09	70
	1225	0	24	10
	1226	0	06	30
	1230	0	04	40
	1224/3	0	13	40
	1224/1	0	22	20
	1277	0	02	70
	1290/1	0	17	40
	1210	0	03	00
	1278/1	0	09	60
	1284	0	01	80
	1275/11	0	01	20
	1275/13	0	29	70
	1275/1	0	53	70
	1275/6	0	03	90
	1265	0	00	10

[सं. O–14016/167/84–जी पी]

S.O. 43.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Energy, Department of Petroleum S.O. 3709 dated 30-10-84 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the land specified in the schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline;

And, whereas, the Competent Authority has under Sub-Section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And, further, whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And, further, in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests from this date of the publication of this declaration in the Oil & Natural Gas Commission free from encumbrances.

SCHEDULE

Pipeline from Bijaipur (M.P.) to Sawai Madhopur (Raj.)

State : Rajasthan District : Tonk Tehsil : Uniyara

Village	Survey No.	Hectare	Are	Centiare
Pachala	94	0	34	50
	95	0	29	10
	92	0	01	20
	98/1	0	63	00
	98/2	0	31	50
	99	0	15	60
	99/1317	0	14	40
	110	0	03	10
	1060/2	0	08	40
	1060/1	0	08	40
	1062	0	05	10
	1067/4	0	38	10
	1067/1/1/1	0	26	60
	1067/3	0	17	40
	1067/11	0	18	90
	1066	0	12	00
	1144/1/2	0	10	10
	1144/3/2	0	42	60
	1144/10	0	12	00
	1145	0	12	90
	1149	0	17	70
	1147	0	01	90
	1148	0	01	00
	1150	0	05	10
	1153	0	27	70
	1152	0	04	50
	1186	0	11	40
	1188	0	23	30
	1187	0	05	70
	1214	0	03	70
	1229	0	04	00
	1227	0	13	60
	1228	0	09	70
	1225	0	24	10
	1226	0	06	30
	1230	0	04	40
	1224/3	0	13	40
	1224/1	0	22	20
	1277	0	02	70
	1290/1	0	17	40
	1210	0	03	00
	1278/1	0	09	60
	1284	0	01	80
	1275/11	0	01	20
	1275/13	0	29	70
	1275/1	0	53	70
	1275/6	0	03	90
	1265	0	00	10

[No. O-14016/167/84-GP]

का. आ. : 44 —यत: पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाईन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय, पेट्रोलियम विभाग की अधिसूचना का. आ. सं० 3728 तारीख 30-10-84 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था।

और यत: सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और आगे यत: केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है।

अब, अत: उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख से निहित होगा।

अनुसूची

विजयपुर (म०प्र०) से सवाईमाधोपुर (राज०) तक पाईप लाईन बिछाने के लिए

राज्य—राजस्थान . . जिला—बून्दी सहगल-केशोराय पाटन राव तहसील—इन्द्रगढ़

गांव	खसरा नं.	हेक्टर	आर	सेंटीआर
गुढ़ा	3	0	99	00
	4	0	02	10
	5	2	17	80
	25	1	25	70
	25/210	0	15	50
	25/209	0	13	80
	25/211	0	15	60
	25/208	0	12	00
	25/205	0	18	60
	25/206	0	28	20
	39	0	31	90
	40	0	01	50
	41	0	26	10
	42	0	75	30
	38	0	00	80
	46	0	04	20
	157	0	09	00
	154	0	13	80
	153	0	15	60
	153/218	0	01	90
	158	0	55	80
	160	0	80	10
	159	0	01	50
	178	0	38	80

[सं. O-14016/219/84-जी पी]

S.O. 44.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Energy, Department of Petroleum S.O. 3728 dated 30-10-84 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the land specified in the schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline;

And, whereas, the Competent Authority has under Sub-Section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report the Government;

And, further, whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And, further, in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests from this date of the publication of this declaration in the Oil & Natural Gas Commission free from encumbrances.

SCHEDULE

Pipeline from Bijaipur (M.P.) to Sawai Madhopur (Raj.)

State : Rajasthan District : Bundi Tehsil : Keshorai Pata

Sub. Teh. : Indar Garh

Village	Survey No.	Hectare	Are	Centiare
Gudha	3	0	99	00
	4	0	02	10
	5	2	17	80
	25	1	25	70
	25/210	0	15	50
	25/209	0	13	80
	25/211	0	15	60
	25/208	0	12	C0
	25/205	0	18	60
	25/206	0	28	20
	39	0	31	90
	40	0	01	50
	41	0	26	10
	42	0	75	30
	38	0	00	80
	46	0	04	20
	157	0	09	00
	154	0	13	80
	153	0	15	60
	153/218	0	01	90
	158	0	55	80
	160	0	80	10
	159	0	01	50
	178	0	38	80

[No. O-14016/219/84—GP]

नई दिल्ली, 27 दिसम्बर, 1984

का. आ. 45.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि मध्य प्रदेश राज्य में हजीरा से बरेली से जगदीशपुर तक पैट्रोलियम के परिवहन के लिए पाइप लाइन तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए।

और यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्पाबद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है।

अतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्द्वारा घोषित किया है।

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति, उस भूमि के नीचे पाइप लाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग एच बी.जे. पाइप लाइन 83 गुनाल नगर आगर रोड, उज्जैन (म.प्र.) 456001 को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतः यह भी कथन करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत रूप से हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत।

एच.बी.जे. गैस पाइप लाइन प्रोजेक्ट

ग्राम कोयल खेड़ी तहसील : घट्टिया जिला : उज्जैन राज्य : मध्य प्रदेश

अनुसूची

अनु. क्र.	खसरा नं.	उपयोग अधिकार अर्जन का क्षेत्र (हैक्टर में)
1	2	3
1.	95/1/4	0.168
2.	95/1/5	--
3.	95/1/3	0.314
4.	95/1/2	0.178
5.	94/1/3	0.303
6.	90/1	0.586
7.	86	0.377
8.	87/1 मी०	0.052
9.	84/2	0.586
10.	84/1 मी०	0.637
11.	85/4	0.387
12.	44	0.209
13.	54	0.188
14.	79	0.021
15.	72/24	0.293
16.	72/9	0.052
17	72/23	0.157
18.	72/8	0.209
19	76/0 मी०	0.157
19.	76/मी०	0.105
20	75/1	
21.	72/13	0.052
22.	72/10	0.052
23.	72/14	0.010

1	2	3
24.	72/11	0.052
25.	72/7	0.146
26.	73	0.470
27.	43	0.044
28.	45	0.115
29.	77	0.084
30.	78	0.314
31.	81	0.044
32.	92	0.052
33.	94/2	0.031
योग कुल क्षत्रफल		7.512

[सं. 0-14016/495/84-जी पी]

New Delhi, the 27th December, 1984

S.O. 45.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of petroleum from Hajira-Bareilly to Jagdishpur in Madhya Pradesh State pipeline should be laid by the Oil & Natural Gas Comission.

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto :

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the Land) Act, 1962 (50 of 1962) the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein:

Provided that any person intersted in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipeline under the land to the competent Authority Oil & Natural Gas Comission, HBJ gas pipe line, 83, Subash Nagar, Sanver Road, Ujjain (M.P.)

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be hear in person or by legal practitioner.

HBJ Gas Pipe Line Project

Village Koyal Khedi Tehsil : Ghatiya Dist : Ujjain

SCHEDULE

S. No.	Survey No.	Area to be acquired for R.O.U. In Hecture
1.	95/1/4	0.168
2.	95/1/5	—
3.	95/1/3	0.314
4.	95/1/2	0.178
5.	94/1/3	0.303
6.	90/1	0.586
7.	86	0 377
8.	87/1 M	0.052
9.	84/2	0.586
10.	84/1/2 M	0.637
11.	85/4	0.387
12.	44	0.209
13.	54	0.188
14.	79	0.021
15.	72/24	0.293
16.	72/9	0.052
17.	72/23	0.157
18.	72/8	0.209
19.	76 M	0.157
19/1.	76 M	
20.	75/1	0.105
21.	72/13	0.052
22.	72/10	0.052
23.	72/14	0.010
24.	72/11	0.052
25.	72/7	0.146
26.	73	0.470
27.	43	0.044
28.	45	0.115
29.	77	0.084
30.	78	0.314
31.	81	0.044
32.	92	0.052
33.	94/2	0.031
	Total Area	7.512

[No. O-14016/495/84-GP]

का. आ. 46.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि मध्य प्रदेश राज्य में हजीरा से बरेली से जगदीशपुर तक पट्रोलियम के परिवहन के लिए पाइप लाइन तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए।

और यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिए एतदपाबद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है।

अतः अब पट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्द्वारा घोषित किया है।

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति, उस भूमि के नीचे पाइप लाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग, एच.बी.जे. पाइप लाइन 83 सुभाष नगर सांवर रोड, उज्जैन (म.प्र.) 456001 को इस अधिसूचना की तारीख तक 31 दिनों के भीतर कर सकेगा।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतः यह भी कथन करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत रूप से हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत।

एच.बी.जे. गैस पाईप लाईन, प्रोजेक्ट

ग्राम : मुधाई तहसील : तराना जिला : उज्जैन राज्य : (मध्य प्रदेश)

अनुसूची

क्रम क.	खसरा नं.	उपयोग अधिकार अर्जन का क्षेत्र (हैक्टर्स में)
1.	87	0.202
2.	86	0.405
3.	96	0.506
4.	84	0.072
5.	91	0.168
6.	90/4	0.235

1	2	3
7.	90/1	0.175
8.	90/3	0.235
9.	90/2	0.240
10.	89	0.128
11.	85	0.008
12.	94	0.008
	योग कुल क्षेत्रफल	2.382

[सं. O-14016/496/84-जी.पी.]

S.O. 46.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interst that for the transport of petroleum from Hajira-Barilly to Jagdishpur in Madhya Pradesh State pipeline should be laid by the Oil & Natural Gas Commission.

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto :

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the Land) Act, 1962 (50 of 1962) the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein;

Provided that any person intersted in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipeline under the land to the competent Authority Oil & Natural Gas Commission, HBJ gas pipe line, 83, Subash Nagar, Sanver Road, Ujjain (M.P.)

And every person making such an objection shall also state specificalyy whether he wishes to be heard in person or by legal practitioner.

HBJ Gas Pipe Line Project

Village : Suchai Tehsil : Tarana Dist : Ujjain

SCHEDULE

S. No.	Survey No.	Area to be acquired for R.O.U. in Hecture
1.	87	0.202
2.	86	0.405
3.	96	0.506
4.	84	0 072
5.	91	0.168
6.	90/4	0 235
7.	90/1	0.175
8.	90/3	0.235
9.	90/2	0 240
10.	89	0 128
11.	85	0.008
12.	94	0 008
	Total Area	2.382

[No. O-14016/496/84-G.P.]

का.आ. 47 :— यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि मध्य प्रदेश राज्य में हजीरा से बरेली जगदीशपुर तक पैट्रोलियम के परिवहन के लिए पाइप लाइन तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए।

और यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाईनों को बिछाने के प्रयोजन के लिए एतदपाबद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है।

अतः अब पैट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद द्वारा घोषित किया है।

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति, उस भूमि के नीचे पाइप लाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग एच.बी.जे. पाइप लाइन 83 सुभाष नगर सांवेर रोड, उज्जैन (म.प्र.) 456001 को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतः यह भी कथन करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत रूप से हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत।

एच.बी.जे. गैस पाईप लाइन प्रोजेक्ट

ग्राम . नवाखेड़ा उर्फ सुतारखेड़ा तहसील . घट्टिया जिला-उज्जैन (राज्य . मध्य प्रदेश)

अनुसूची

अनुक्रम	खसरा नं.	उपयोग अधिकार अर्जन का क्षेत्र (हैक्टर्स में)
1.	132/1	0.732
2.	24	0.377
3.	126	0.345
4.	115	0.010
5.	124	0.314
6.	112	0.439
7.	111	0.627
8.	104	0.105
9.	99	0.021
10.	103	0.449
11.	100	0.658
12.	47	0.449
13.	46	0.314
14.	42मी.	0.428
15.	41	0.052
16.	22	0.031
17.	2	0.105
18.	20	0.606
19.	125	0.042
20.	117	0.052
	योग कुल क्षेत्रफल	6.156

[सं. O-14016/497/84-जी प]

S.O. 47.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of petroleum from Harira-Barilly to Jagdishpur in Madhya Pradesh State pipeline should be laid by the Oil & Natural Gas Commission.

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto :

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the Land) Act, 1962 (50 of 1962) the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user threin;

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipeline under the land to the competent Authority Oil & Natural Gas Commission, HBJ gas pipe line. 83, Subash Nagar, Sanver Road, Ujjain (M.P.)

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by legal practitioner.

HBJ Gas Pipe Line Project

Village Navakheda Urf Sutarkheda Tehsil Bhatiya

District Ujjain

SCHEDULE

S. NO	Survey No.	Area to be acquired for R.O.U. in Hecture
1.	132/1	0.732
2.	24	0.377
3.	126	0.345
4.	115	0.010
5.	124	0.314
6.	112	0.439
7.	111	0.627
8.	104	0.105
9.	99	0.021
10.	103	0.449
11.	100	0.658
12.	47	0.449
13.	46	0.314
14.	42 M	0.428
15.	41	0.052
16.	22	0.031
17.	2	0.105
18.	20	0.606
19.	125	0.042
20.	117	0.052
	Total Area	6.156

[No. O-14016/497/84-G.P.]

का.आ. 48.— यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि मध्य प्रदेश राज्य में हजीरा से बरेली से जगदीशपुर तक पैट्रोलियम के परिवहन के लिए पाइप लाइन तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए।

और यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिए एतदुपाबद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है।

अतः अब पैट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्द्वारा घोषित किया है।

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति, उस भूमि के नीचे पाइप लाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग, एच.बी.जे. पाइप लाइन 83 सुभाष नगर सांवेर रोड, उज्जैन (म.प्र.) 456001 को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतः यह भी कथन करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत रूप से हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत।

एच.बी.जे. गैस पाईप लाइन का प्रोजेक्ट

ग्राम . भगवनपुरा तहसील . नराना जिला . उज्जैन राज्य (मध्य प्रदेश)

अनुसूची

अनु. क्रम	खसरा नं	उपयोग अधिकार अर्जन का (क्षेत्र हैक्टर्स में)
1.	117/2	0.016
2.	120	0.192
3.	172/2	0.056
4.	274	0.240
5.	281	0.211
6.	275	0.190
7.	272	0.202
8.	280	0.088
9.	279	0.360
10.	278	0.022
11.	277/1	0.240
12.	282	0.230
13.	285	0.530
14.	287	0.224
15.	276/1 1	0.040
16.	288/3	0.104
17.	172/1	0.091
18.	292/1	0.041
19.	291	0.022
20.	292/2	0.144
21.	293	0.052
22.	294	0.020
23.	296	0.517
24.	297	0.214
25.	299	0.405
26.	300	0.445
	योग कुल क्षेत्रफल	4.896

[सं. O-14016/498/84-ज. प.]

S.O. 48.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interst that for the transport of petroleum from Hajira-Barilly to Jagdishpur in Madhya Pradesh State pipeline should be laid by the Oil & Natural Gas Commission.

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto :

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the Land) Act, 1962 (50 of 1962) the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein;

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipeline under the land to the competent

Authority Oil & Natural Gas Commission, HBJ gas pipe line, 83, Subash Nagar, Sanver Road, Ujjain (M.P.)

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by legal practitioner.

HBJ Gas Pipe Line Project

Village : Bhagwatpura Tehsil : Tarana Dist. : Ujjain

SCHEDULE

S. NO	Survey No.	Area to be acquired for R.O.U in Hecture.
1.	117/2	0.016
2.	120	0.192
3.	172/2	0.056
4.	274	0.240
5.	281	0.211
6.	275	0.190
7.	272	0.202
8.	280	0.088
9.	279	0.360
10.	278	0.022
11.	277/1	0.240
12.	282	0.230
13.	285	0.530
14.	287	0.224
15.	276/1/1	0.0'0
16.	288/3	0.104
17.	172/1	0.091
18.	292/1	0.0[illegible]1
19.	291	0.022
20.	292/2	0.144
21.	293	0.052
22.	294	0.020
23.	296	0.517
24.	297	0.214
25.	299	0.405
26.	300	0.445
	Total Area	4.896

[No. O-14016/498/84-G.P.]

का. आ. 49.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि मध्यप्रदेश राज्य में हजीरा से बरेली से जगदीशपुर तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिए पाइप लाइन तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए।

और यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्पाबद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है

अतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन (भूमि में उपयोग अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद् द्वारा घोषित किया है।

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति, उस भूमि के नीचे पाइप लाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग को एच. बी. जे. पाइप लाइन 83 सुभाष नगर सांवेर रोड, उज्जैन (म. प्र.) 456001 को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतः यह भी कथन करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत रूप से हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत।

एच. बी. जे. गैस पाइप लाइन प्रोजेक्ट

ग्राम खोरिया तहसील घट्टिया जिला-उज्जैन राज्य (मध्य-प्रदेश)

अनुसूची

अनु.क्र.	खसरा नं.	उपयोग अधिकार अर्जन का क्षेत्र (हैक्टर्स में)
1.	47	0.470
2.	46	0.031
3.	120	0.021
4.	114	0.073
5.	54/2	0.512
6.	36	0.271
7	57	0.073
8	35	0.282
9.	56	0.031
10	61	0.167
11.	113	0.167
12.	62	0.157
13.	63	0.073
14.	66	0.087
15.	67	0.157
16.	68	0.105
17.	69	0.314
18.	108	0.021
19.	107	0.491
20.	115	0.157
21.	118	0.105
22.	116	0.105
23.	122	0.073
24.	117	0.021
25.	31	0.721
26.	111	0.086
27.	121	0.010
28.	60	0.031
	योग कुल क्षेत्रफल:—	4.812

[सं. O-14016/499/84-जी. पी]

S.O. 49.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in thepublic interest that for the transport of petroleum from Hajira-Barilly to Jagdishpur in Madhya Pradesh State pipeline should be laid by the Oil & Natural Gas Commission.

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto :

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipeline (Acquisition of Right of User in the Land) Act, 1962 (50 of 1962) the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein;

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipeline under the land to the competent Authority Oil & Natural Gas Commission, HBJ gas pipe line, 83, Subash Nagar, Sanver Road, Ujjain (M.P.)

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by legal practitioner.

HBJ Gas Pipe Line Project

Village : Khopariya Tehsil : Ghatiya Dist. : Ujjain

SCHEDULE

S. No.	Survey No.	Area to be acquired for .RO.U. in Hecture
1.	47	0.470
2.	46	0.031
3.	120	0 021
4.	114	0.073
5.	54/2	0.512
6.	36	0.271
7.	57	0.073
8.	35	0.282
9.	56	0.031
10.	61	0.167
11.	113	0.167
12.	62	0 157
13.	63	0.073
14.	66	0.087
15.	67	0.157
16.	68	0.105
17.	69	0.314
18.	108	0 021
19.	107	0.491
20.	115	0.157
21.	118	0.105
22.	116	1.105
23.	122	0.073
24.	117	0.021
25.	31	0.721
26.	111	0.086
27.	121	0.010
28.	60	0.031
	Total Area	4.812

[No. O-14016/444/84-G.P.]

का. आ. 50.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि मध्यप्रदेश राज्य में हजीरा से बरेली से जगदीशपुर तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिए पाइप लाइन तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए।

और यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्पाबद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है।

अतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्द्वारा घोषित किया है।

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति, उस भूमि के नीचे पाइप लाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकार, तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग, एच. बी. जे. पाइप लाइन 83 सुभाष नगर सांवेर रोड, उज्जैन (म. प्र.) 456001 को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतः यह भी कथन करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत रूप से हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत।

एच. बी. जे. गैस पाइप लाइन प्रोजेक्ट

ग्राम गुड़ा तहसील घटिट्या जिला-उज्जैन राज्य (मध्य-प्रदेश)

अनुसूची

अनुक्र.	खसरा नं.	उपयोग अधिकार अर्जन का क्षेत्र (हैक्टर्स में)
1.	211	0.219
2.	260	0.031
3.	265/1	0.094
4.	278	0.439
5.	281	0.094
6.	269/2	0.010
7.	272	0.596
8.	273	0.941
9.	274	0.031
10.	277	0.052
11.	279	0.324
12.	280 मि.	0.073
13.	280 म.	0.293
14.	282	0.261
15.	283	0.345
16.	286	0.293
17.	284	0.230
18.	249/3	0.115
	कुल योग क्षेत्रफल :	4.441

[सं० O-14016/590/84/जी पी]

S.O. 50.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of petroleum from Hajira-Barilly to Jagdishpur in Madhya Pradesh State pipeline should be laid by the Oil & Natural Gas Commission.

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto :

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the Land) Act, 1962 (50 of 1962) the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein;

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipeline under the land to the competent Authority Oil & Natural Gas Commission, HBJ gas pipe line, 83, Subash Nagar, Sanver Road, Ujjain (M.P.)

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by legal practitioner.

HBJ Gas Pipe Line Project

Village : Guda Tehsil : Ghatiya Distt. : Ujjain

SCHEDULE

S. No.	Survey No.	Area to be acquired fo· R.O.U. in Hecture
1	2	3
1.	211	0.219
2.	260	0.031

1	2	3
3.	265/1	0.094
4.	278	0.439
5.	281	0.094
6.	269/2	0.010
7.	272	0.596
8.	273	0.941
9.	274	0.031
10.	277	0.052
11.	279	0.324
12.	280 M	0.073
13.	280 M	0.293
14.	282	0.261
15.	283	0.345
16.	286	0.293
17.	284	0.230
18.	248/3	0.115
	Total Area	4.441

[No. O-14016/500/84-G.P.]

का. आ. 51.—यत: केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि मध्य प्रदेश राज्य में हजीरा से बरेली से जगदीशपुर तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिए पाइप लाइन तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए।

और यत: यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाईनों को बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्पाबद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है।

अत: अब पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्द्वारा घोषित किया है।

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति, उस भूमि के नीचे पाइप लाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग, एच. बी. जे. पाइप लाइन 83 सुभाष नगर सांवेर रोड, उज्जैन (म. प्र.) 456001 को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टत: यह भी कथन करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत रूप से हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत।

एच. बी. जे. गैस पाइप लाइन प्रोजेक्ट

ग्राम सामानेरा तहसील तराना जिला-उज्जैन राज्य (मध्य-प्रदेश)

अनुसूची

अनु.क्र.	खसरा नं.	उपयोग अधिकार अर्जन का क्षेत्र (हैक्टर्स में)
1	2	3
1.	351	0.030
2.	352	0.030
3.	353	0.030
4.	354	0.080
5.	355	0.200
6.	378	0.100
7.	365/1	0.150
8.	365/3	0.030
9.	369	0.020
10.	370	0.040
11.	376	0.100
12.	377/1	0.045
13.	377/2	0.100
14.	379	0.050
15.	381	0.100
16.	382	0.450
17.	383/1	0.050
18.	391	0.040
19.	371	0.005
20.	418	0.080
21.	435/4	0.030
22.	562	0.010
23.	587	0.020
24.	593	—
25.	594/3	0.003
26.	615	0.060
27.	392	0.050
28.	432	0.100
29.	393	0.120
30.	422	0.440
31.	423/1	0.140
32.	425/2	0.140
33.	426	0.250
34.	429	0.040
35.	430	0.080
36.	431	0.200
37.	418 पै०	0.050
38.	594/1	0.100
39.	612	0.120
40.	613	0.150
41.	617	0.080
42.	616/1	0.180
43.	721	0.320
44.	722	0.150
45.	794	0.100
46.	425/1	0.100
47.	584	0.340
	कुल योग क्षेत्रफल:-	5.103

[सं. O-14016/501/84-जी. प.]

S.O. 51.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of petroleum from Hajira-Barilly to Jagdishpur in Madhya Pradesh State pipeline should be laid by the Oil & Natural Gas Commission.

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the Land) Act, 1962 (50 of 1962) the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein;

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipeline under the land to the competent Authority Oil & Natural Gas Commission, HBJ gas pipe line, 83, Subash Nagar, Sanver Road, Ujjain (M.P.)

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by legal practitioner.

HBJ Gas Pipe Line Project

Village : Samanera Tehsil : Tarana Dist. : Ujjain

SCHEDULE

S. No.	Survey No.	Area to be acquired for R.O.U. in Hecture
1.	351	0.030
2.	352	0.030
3.	353	0.030
4.	354	0.080
5.	355	0.200
6.	378	0.100
7.	365/1	0.150
8.	365/3	0.030
9.	369	0.020
10.	370	0.040
11.	376	0.100
12.	377/1	0.045
13.	377/2	0.100
14.	379	0.050
15.	381	0.100
16.	382	0.450
17.	383/1	0.050
18.	391	0.040
19.	371	0.005
20.	418	0.080
21.	435/4	0.030
22.	562	0.010
23.	587	0.020
24.	595	- -
25.	594/3	0.003
26.	615	0.060
27.	392	0.050
28.	432	0.100
29.	393	0.120
30.	422	0.440
31.	423/1	0.140
32.	425/2	0.140
33.	426	0.250
34.	429	0.040
35.	430	0.080
36.	431	0.200
37.	448 P.	0.050
38.	594/1	0.100
39.	612	0.120
40.	613	0.150
41.	617	0.080
42.	616/1	0.180
43.	721	0.320
44.	722	0.150
45.	794	0.100
46.	425/1	0.100
47.	584	0.340
	Total Area	5.103

[No. O-14016/501/84-GP]

का. आ. 52.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि मध्यप्रदेश राज्य में हजीरा से बरेली से जगदीशपुर तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिए पाइप लाइन तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए।

और यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाईनों को बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्पाबद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है।

अतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाईप लाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्द्वारा घोषित किया है।

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति, उस भूमि के नीचे पाइप लाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग एच. बी. जे. पाइप लाइन 83 सुभाष नगर सांवेर रोड, उज्जैन (म. प्र.) 456001 को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतः यह भी कथन करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत रूप से हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत।

एच. बी. जे. गैस पाईप लाईन प्रोजेक्ट

ग्राम डावड़ा राजपूत तहसील तराना जिला-उज्जैन राज्य (मध्य-प्रदेश)

अनुसूची

अनु.क्र.	खसरा नं.	उपयोग अधिकार अर्जन का क्षेत्र (हैक्टर्स में)
1.	1	0.090
2.	2	0.025
3.	3/1	0.285
4.	3/3	0.012
	योग कुल क्षेत्रफल:-	0.412

[सं. O-14016/502/84-जी. पी.]

S.O. 52.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of petroleum from Hjira-Barilly to Jagdishpur in Madhya Pradesh State pipeline should be laid by the Oil & Natural Gas Commission.

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto :

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipeline (Acquisition of Right of User in the Land) Act, 1962 (50 of 1962) the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein;

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipeline under the land to the competent Authority Oil & Natural Gas Commission, HBJ gas pipe line, 83, Subash Nagar, Sanver Road, Ujjain (M.P.)

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by legal practitioner.

HBJ Gas Pipe Line Project

Village : Dahda Rajput Tehsil : Tarana Distt. : Ujjain

SCHEDULE

S. No.	Survey No.	Area to be acquired for R.O.U. in Hecture
1.	1	0.090
2.	2	0.025
3.	3/1	0.285
4.	3/3	0.012
	Total Area	0·412

[No. O-14016/502/84-GP]

का. आ. 53.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि मध्य प्रदेश राज्य में हजीरा से बरेली से जगदीशपुर तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिए पाइप लाइन तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए।

और यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्पाबद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है।

अतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्द्वारा घोषित किया है।

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति उस भूमि के नीचे पाइप लाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकार, तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग एच. बी. जे. पाइप लाइन 83 सुभाष नगर सांवेर रोड, उज्जैन (म. प्र.) 456001 को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतः यह भी कथन करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत रूप से हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत।

एच. बी. जे. गैस पाईप लाईन प्रोजेक्ट

ग्राम रूपाखेड़ा, तहसील तराना जिला-उज्जैन, राज्य (मध्य प्रदेश)

अनुसूची

क्रम.	खसरा नं.	उपयोग अधिकार अर्जन का क्षेत्र (हैक्टर्स में)
1	2	3
1	55	0.150
2.	56	—
3.	57	0.090
4.	58	—
5.	59	—
6.	60	0.230
7.	62	0.220
8.	63	0.150
9.	76	0.160
10.	77	0.140
11.	78	0.200
12.	358	0.030
13.	91	0.170
14.	95	0.050
15.	96/2	0.130
16.	275	0.090
17.	61	0.010
18.	79	0.020
19.	357	0.025
20.	374/1	0.010
21.	349/2	0.130
22.	348	0.010
23.	277/2	0.020
24.	330	0.150
25.	359	0.200
26.	278	0.250
27.	280	0.260
28.	329	0.070
29.	281	0.060
30.	282	—
31.	283	0.300
32.	284	0.040
33.	285	0.080
34.	298	0.320
35.	293	0.380
36.	294	0.460
37.	297/2	0.030
38.	297/1	0.220
39.	331	0.150
40.	333	—
41.	347	0.120
42.	360	0.220
43.	370	0.210
44.	372	0.250
45.	373	0.110
46.	53/393	0.040
47.	290/392	0.070
	कुल योग क्षेत्रफल:—	6.025

[सं. O-14016/503/84-जी पी]

S.O. 53.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of petroleum from Hajira-Barilly to Jagdishpur in Madhya Pradesh State pipeline should be laid by the Oil & Natural Gas Commission.

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the described in the schedule annexed hereto :

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the Land) Act, 1962 (50 of 1962) the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein;

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipeline under the land to the competent Authority Oil & Natural Gas Commission, HBJ gas pipe line, 83, Subash Nagar, Sanver Road, Ujjain (M.P.)

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by legal practitioner.

HBJ Gas Pipe Line Project

Village : Rupakhedi *Tehsil* : Tarana Distt. : Ujjain

SCHEDULE

S. No.	Survey No.	Area to be acquired for R.O.U. in Hecture
1.	55	0.150
2.	56	
3.	57	0.090
4.	58	—
5.	59	—
6.	60	0.230
7.	62	0.220
8.	63	0.150
9.	76	0.160
10.	77	0.140
11.	78	0.200
12.	358	0.030
13.	94	0.170
14.	95	0.050
15.	96/2	0.130
16.	275	0.090
17.	61	0.010
18.	79	0.020
19.	357	0.025
20.	374/1	0.010
21.	349/2	0.130
22.	348	0.010
23.	277/2	0.020
24.	330	0.150
25.	359	0.200
26.	278	0.250
27.	280	0.260
28.	329	0.070
29.	281	0.060
30.	282	—
31.	283	0.300
32.	284	0.040
33.	285	0.080
34.	298	0.320
35.	293	0.380
36.	294	0.460
37.	297/2	0.030
38.	297/1	0.220
39.	331	0.150
40.	333	—
41.	347	0.120
42.	360	0.220
43.	370	0.210
44.	372	0.250
45.	373	0.110
46.	53/393	0.040
47.	290/392	0.070
	Total Area	6.025

[No. O-14016/503/84-GP]

का. आ. 54.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि मध्य प्रदेश राज्य में हजीरा से बरेली से जगदीशपुर तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिए पाइप लाइन तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए

और यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाईनों को बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्पाबद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है ।

अतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्द्वारा घोषित किया है ।

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति, उस भूमि के नीचे पाइप लाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग, एच. बी. जे. पाइप लाइन 83 सुभाष नगर सावेर रोड, उज्जैन (म. प्र.) 456004 को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा ।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतः यह भी कथन करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत रूप से हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत ।

एच. बी. जे. गैस पाईप लाईन प्रोजेक्ट

ग्राम जिवाजी तहसील तराना जिला-उज्जैन राज्य (मध्य-प्रदेश)

अनुसूची

अनु.क्र.	खसरा नं.	उपयोग अधिकार अर्जन का क्षेत्र (हैक्टर्स में)
1	2	3
1.	232	0.036
2.	279	0.318
3.	272	0.005
4.	278	0.154
5.	475	0.125
6	458	0.049
7.	286	0.390
8.	290	0.300
9.	287	0.041
10	276	0.010
11.	200/1/1	0.024
12.	307	0.364
13.	357/1-2	0.615
14.	309	0.540
15.	359	0.490
16.	352	0.210
17.	371	0.014
18.	368	0.090
19.	367	0.340
20.	369	0.020
21.	377	0.047
22.	376	0.182
23.	379	0.405
24.	375	0.081
25	380	0.225
26.	478/1/1ग.	0.360
27.	476	0.330
28.	455	0.441
29.	456	0.162
30.	459/1	0.342

1	2	3
31.	461/1/1	0.605
32.	461/1/2	—
	462/1	—
33.	433	0.010
34.	358	0.025
35.	454	0.025
कुल योग क्षेत्रफल:–		7.378

[सं. O-14016/504/84-जी.पी.]

S.O. 54.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of petroleum from Hajira-Barilly to Jagdishpur in Madhay Pradesh State pipeline should be laid by the Oil & Natural Gas Commission.

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the Schedule Annexed hereto ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the Land) Act, 1962 (50 of 1962) the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein;

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipeline under the land to the competent Authority Oil & Natural Gas Commission, HBJ gas pipe line, 83, Subash Nagar, Sanver Road, Ujjain (M.P.)

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by legal practitioner.

HBJ Gas Pipe Line Project

Village : Chikli Tehsil : Tarana Distt. : Ujjain

SCHEDULE

S. No.	Survey No.	Area to be acquired for R.O.U in Hecture
1.	232	0.036
2.	279	0.318
3.	272	0.005
4.	278	0.154
5.	475	0.125
6.	458	0.049
7.	286	0.390
8.	290	0.300
9.	287	0.041
10.	276	0.010
11.	200/1/1	0.024
12.	307	0.364
13.	357/1-2	0.615
14.	309	0.540
15.	359	0.490
16.	352	0.210
17.	371	0.014
18.	368	0.090
19.	367	0.340
20.	369	0.020
21.	377	0.047
22.	376	0.182
23.	379	0.405
24.	375	0.081
25.	380	0.225
26.	478/1/1 P.	0.360
27.	476	0.330
28.	455	0.444
29.	456	0.162
30.	459/1	0.342
31.	461/1/1	0.605
32.	461/1/2	—
	462/1	—
33.	433	0.010
34.	358	0.025
35.	454	0.025
	Total Area	7.378

[No. O-14016/504/84-G.P.]

का. आ. 55.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि मध्यप्रदेश राज्य में हजीरा से बरेली से जगदीशपुर तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिए पाइप लाइन तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए ।

और यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाईनों को बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्पाबद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है ।

अतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्द्वारा घोषित किया है ।

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति, उस भूमि के नीचे पाइप लाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग, एच. बी. जे. पाइप लाइन 83 सुभाष नगर, सवेर रोड, उज्जैन (म. प्र.) 456001 को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा ।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतः यह भी कथन करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत रूप से हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत ।

एच. बी. जे. गैस पाईप लाईन प्रोजेक्ट

ग्राम. भोड़ल्या तहसील: तराना जिला. उज्जैन राज्य (मध्य-प्रदेश).

अनुसूची

अनु.क्र.	खसरा नं.	उपयोग अधिकार अर्जन का क्षेत्र (हैक्टर्स में)
1	2	3
1.	281	0.015
2.	282	0.081
3.	283/2	0.220
4.	283/3	0.202
5.	285/1	0.+210
6.	285/2	0.260
7.	287	0.030
8.	421	0.231
9.	422/1	0.237
	422/2	—
10.	423	0.032
11.	458	0.210
12.	459	0.288
13.	457	0.055
कुल योग क्षेत्रफल:–		2.071

[सं. O-14016/505/84-जी.पी.]

एम०एस श्री निवासन, उप सचिव

S.O. 55.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of petroleum from Hajira-Barilly to Jagdishpur in Madhya Pradesh State pipeline should be laid by the Oil & Natural Gas Commission.

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto :

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the Land) Act, 1962 (50 of 1962) the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of users therein;

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipeline under the land to the competent Authority Oil & Natural Gas Commission, HBJ gas pipe line, 83, Subash Nagar, Sanver Road, Ujjain (M.P.)

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by legal practitioner.

HBJ Gas Pipe Line Project

Village : Bhodalya Tehsil : Tarana Distt. : Ujjain

SCHEDULE

S. No.	Survey No.	Area to be acquired for R.O.U. in Hecture
1.	281	0.015
2.	282	0.081
3.	283/2	0.220
4.	283/3	0.202
5.	285/1	0.210
6.	285/2	0.260
7.	287	0.030
8.	421	0.231
9.	422/1	0.237
	422/2	—
10.	423	0.032
11.	458	0.210
12.	459	0.288
13.	457	0.055
	Total Area	2.071

[No. O-14016/505/84-G.P.]
M. S. SRINIWASAN Dy. Secy.

शिक्षा और संस्कृति मंत्रालय

(संस्कृति विभाग)

नई दिल्ली, 15 दिसम्बर, 1984

का. आ. 56 :—सार्वजनिक सूचनार्थ यह अधिसूचित किया जाता है कि उपखण्ड (1) की धारा (एच) तथा भारतीय संग्रहालय अधिनियम 1910 (1910 का 10) के खण्ड-2 के उप-खण्ड (3) के उपबंध के अनुसरण में एशियाटिक सोसायटी, कलकत्ता द्वारा डॉ. चन्दन राय चौधरी को 17 नवम्बर, 1984 से तीन वर्षों की अवधि के लिए भारतीय संग्रहालय, कलकत्ता में न्यासी के रूप में नामित किया गया है।

[सं. फा. 11-9/84-सी.एच.-5]
टी. एन. वाजपेयी, अवर सचिव

MINISTRY OF EDUCATION AND CULTURE

(Department of Culture)

New Delhi, the 15th December, 1984

S.O.56.—It is hereby notified for the formation of the public that in pursuance of clause (h) of sub-section (1) and proviso to sub-section (3) of section 2 of the Indian Museum Act, 1910 (19 of 1910) Dr. Chandan Roy Chaudhuri, has been nominated by the Council of the Asiatic Society, Calcutta as a Trustee of the Indian Museum; Calcutta for a period of three years with effect from the 17th November, 1984.

[No. F. 11-9/84-CH. 5]
T. N. BAJPAI, Under Secy.

नौवहन और परिवहन मंत्रालय

(नौवहन पक्ष)

नई दिल्ली, 19 दिसम्बर, 1984

का. आ. 57.—केन्द्रीय सरकार वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 1958 (1958 का 44) की धारा 356 क की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, घोषित करती है कि उक्त अधिनियम के भाग XI क के उपबंध, धारा 356 ड (356 एम) के उपबंधों के सिवाय, तुरन्त लागू होंगे।

[सं. एस. डब्ल्यू/5-एम एस आर(11)/84-एम.ए.]
सुदर्शन सिंघल, अवर सचिव

MINISTRY OF SHIPPING AND TRANSPORT

(Shipping Wing)

New Delhi, the 19th December, 1984

S.O. 57.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the section 356A of the Merchant Shipping Act, 1958 (44 of 1958), the Central Government hereby declares that the provisions of Part XI A, except the provisions of section 356 M, of the said Act, shall come into force with immediate effect.

[No. SW/5-MSR(11)/84-MA]
S. SYNGHAL, Under Secy.

संचार मंत्रालय

(डाक तार बोर्ड)

नई दिल्ली, 20 दिसम्बर, 1984

का. आ. 58.—स्थायी आदेश संख्या 627, दिनांक 8 मार्च, 1960 द्वारा लागू किए गए भारतीय तार नियम, 1951 के नियम 434 के खण्ड 3 के पैरा (क) के अनुसार डाक-तार महानिदेशक ने नदिगामा टेलीफोन केन्द्र में दिनांक 16-1-85 से प्रमाणित दर प्रणाली लागू करने का निश्चय किया है।

[संख्या 5-8/84-पी एच बी]
अजरामसिंह, सहायक महानिदेशक (पी. एच. बी.)

MINISTRY OF COMMUNICATIONS

(P&T Board)

New Delhi, the 20th December, 1984

S.O. 58.—In pursuance of para (a) of Section III of Rule 434 of Indian Telegraph Rules, 1951, as introduced by

S. O. No. 627 dated 8th March, 1960, the Director General, Posts and Telegraphs, hereby specified 16-1-1985 as the date on which the Measured Rate System will be introduced in NANDIGAMA Telephone Exchange Andhra Pradesh Circle.

[No. 5-8|84-PHB]

B. R. SINGH, Asstt. Director General (PHB)

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय

(श्रम विभाग)

नई दिल्ली, 20 दिसम्बर, 1984

का. आ. 59.—मैसर्स दी मैसूर पेपर मिल्स लिमिटेड, भद्रावती-577302, पंजीकृत दफ्तर, 16/4, अली अस्कर रोड, प. ब. नं.-112, बंगलौर-22, (क नं./41) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है ।

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही लाईफ कवर स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय हैं;

अतः, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इसके उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबंधों के प्रवर्तन से छूट देती है ।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त कर्नाटक को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर निर्दिष्ट करे।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण, प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3क) के खण्ड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करे।

3. लाईफ कवर स्कीम के प्रशासन में, जिसके अंतर्गत लेखाओं का रखा जाना विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अंतरण, निरिक्षण प्रभारों संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा ।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित लाईफ कवर स्कीम के नियमों की एक प्रति, और जब कभी इनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद ,स्थापन ।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है, तो नियोजक, लाईफ कवर स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा ।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाए जाते हैं, तो नियोजक लाईफ कवर स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए लाईफ कवर स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं ।

7. लाईफ कवर स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नाम निर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अंतर के बराबर रकम का संदाय करेगा।

8. लाईफ कवर स्कीम के उपबंधों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, कर्नाटक से पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहाँ किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो, वहाँ प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा ।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, लाईफ कवर स्कीम के जिसे स्थापन पहले अपना चुका है, अधीन नहीं रह जाते हैं या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, उसे यह रद्द की जा सकती है।

10. यदि किसी कारणवश नियोजक उस नियत तारीख के भीतर प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है ।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अंतर्गत होते बीमा फायदों के संदाय का उत्तर दायित्व नियोजक पर होगा ।

12. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देशितियों/विधिक/वारिसों को बीमाकृत रकम का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में पन्द्रह दिन के भीतर सुनिश्चित करेगा ।

13. उक्त स्थापन स्टेट बैंक आफ इंडिया में पाँच लाख रुपये लाईफ कवर फण्ड के नाम से जमा करायेगा और इसमें से निकाली गई राशि को समय-समय पर पूरा करेगा। किसी भी समय यह राशि उपरोक्त फण्ड में पाँच लाख रुपये से कम नहीं रहनी चाहिए। अगर कभी भी यह पाया गया कि फण्ड की राशि पाँच लाख रुपये से कम है तो छूट रद्द की जा सकती है।

[संख्या एस-35014/159/84-एस. एस.-4]

MINISTRY OF LABOUR AND REHABILITATION

(Department of Labour)

New Delhi, the 20th December, 1984

S.O. 59.—Whereas Messrs. The Mysore Paper Mills Limited, Bhadravathi-577302, Regd. Office : 16/4, Ali Asker Road, P. B. No. 112, Bangalore-22 (KN/41) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of Section 17 of the Employees' Provident Funds & Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act).

And, whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Life Cover Scheme of the establishment in the nature of life insurance, which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme).

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of Section 17 of the said Act, and subject to the conditions specified in the schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Karnataka and maintain such accounts and provide for such facilities for inspection as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer in relation to the said establishment shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of Section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of inspection charges, shall be born by the employer of the said establishment.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Life Cover Scheme as approved by the Central Government and as and when amended the amendments thereof alongwith a translation of the salient features thereof in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Life Cover Scheme.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Life Cover Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Life Cover Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Nothwithstanding anything contained in the Life Cover Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Life Cover Scheme, shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Karnataka and where any amendment is likely to affect adversely the interests of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall, before giving his approval, give a reasonable oportunity to the employee to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Life Cover Scheme as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date and the Life Cover Scheme is allowed to discontinue, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium and responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the members covered under the Life Cover Scheme the employer of the said establishment shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/Legal heirs of the deceased member entitled for it and in any case within fifteen days from the receipt of claim complete in all respects from the claimants.

13. The said establishment shall deposit a sum of Rupees Five Lakhs in the State Bank of India under suitable entitlements (to be called Life Cover Fund) and the employer shall ensure by replenishment of the shortfall from time to time so that at no time the amount in the Life Cover Fund is less than rupees five lakhs. Where for any reason the employer fails to replenish the Life Cover Fund and the amount thereof is less than rupees five lakhs, the exemption is liable to be cancelled.

[No. S-35014/159/84 SS-IV]

नई दिल्ली, 26 दिसम्बर 1984

का. आ. 60.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स बाबा सत्यानारायणा होमगढ प्रा० लि० शाहपुर, तारकेशवर, हुगली (वैस्ट बंगाल) नामक स्थापन के सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1962 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए।

अतः, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए

उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है ।

[सं. एस-35017/103/84-एस.एस.-2]

New Delhi, the 26th December, 1984

S.O. 60.—Whereas it appears to the Cental Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs. Baba Satyanarayan Himghar Private Limited, Sahapur, Tarakeshwar, Hooghly (West Bengal) have agreed that the provision of the Employees' Provident Fund and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-Section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S-35019/103/84-SS-II]

का. आ. 61.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स आर. एम. ट्रेडिंग कम्पनी, 17 गणेश चन्द्र एवेन्यु, कलकत्ता-13, नामक स्थापन के सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए ।

अतः केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है ।

[सं. एस-35017/104/84-एस. एस. -2]

S.O. 61.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs. R. M. Trading Company, 17, Ganesh Chandra Avenue, Calcutta-13 have agreed that the provision of the Employees' Provident Fund and Miscellaneous Provisions Act. 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-Section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S-35017/104/84-SS-II]

शुद्धि पत्र

का. आ. 62.—श्रम और पुनर्वास मंत्रालय (श्रम विभाग), भारत सरकार की अधिसूचना संख्या का. आ. 52, दिनांक 17 दिसम्बर, 1983 जो भारत के राजपत्र के भाग-2, खण्ड 3 उप खण्ड (ii) के पृष्ठ 34 पर दिनांक 7 जनवरी, 1984 को प्रकाशित हुई थी, की तीसरी पंक्ति में "गावत्री टाईल्स" के स्थान पर "गायत्री टाईल्स" पढ़ें ।

[सं. एस-35019/351/83-पी. एफ.-II]

CORRIGENDUM

S.O. 62.—In the notification of the Government of India in the Ministry of Labour and Rehabilitation, (Department of Labour), No. S.O. 52 dated the 17th December, 1983 published at page 34 of the Gazette of India, Part II, section 3, sub-section (ii), dated the 7th January, 1984; in line 3, for "Gavatri Tiles" read "Gayatri Tiles".

[No. S-35019/351/83-PF-II(SS. II)]

का. आ. 63.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स वोस्ट एलपाईन इंडिया प्रा. लि. 39, गोल्फ लिंक्स, नई दिल्ली । नामक स्थापन के सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए ।

अतः, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है ।

[सं. एस-35019(486)/84-एस. एस.-2]

S.O. 63.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs. Voost Alpine India Private Limited, 39, Golf Links, New Delhi have agreed that the provision of the Employees' Provident Fund and Miscellaneous provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-Section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S-35019/486/84-SS-II]

का. आ. 64.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स सुदेश मशीन सर्विसिज, 822, जोशी पथ, करोल बाग, नई दिल्ली । नामक स्थापन के सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए ।

अतः, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है ।

[सं. एस-35019/487/84-एस. एस.-2]

S.O. 64.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs. Sudesh Machine Services, 822, Joshi Path, Karol Bagh, New Delhi, have agreed that the provision of the Employees' Provident Fund and Miscellaneous Provisions Act. 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-Section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S-35019/487/84-SS. II]

का. आ. 65.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स देहली हिन्दुस्तानी मर्कन्टाइल एसोसिएशन (रजि.) 1210-16, चांदनी चौक देहली-6 नामक स्थापन के सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए ।

अतः, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है ।

[सं. एस-35019(488)/84-एस. एस. 2]

S.O. 65.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs. Delhi Hindustani Mercantile Association (Regd.), 1210-16, Chandni Chowk, Delhi-6, have agreed that the provision of the Employees' Provident Fund and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-Section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S-35019/488/84-SS-II]

का. आ. 66.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स श्री मेपीलाई विनयागर ट्रांसपोर्ट, जी. एस. टी. रोड, पाईकारा, मदुराई-17, तमिलनाडु नामक स्थापन के सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए ।

अतः, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है ।

[सं. एस-35019 (489)/84-एस. एस. 2]

S.O. 66.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs. Sri Mappilai Vinayagar Transport, G.S.T. Road, Pykara, Madurai-17, Tamil Nadu, have agreed that the provision of the Employees' Provident Fund and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-Section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S-35019/489/84-SS-II]

का. आ. 67.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स डोर सेश कंसल्टेंटस नं. 5, इण्डस्ट्रीयल लेआउट, कोरामंगला, बंगलौर-560034, कर्नाटका नामक स्थापन के सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए ।

अतः, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है ।

[सं. एस-35019(490)/84-एस. एस. 2]

S.O. 67.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs. Dore Sesh Consultants, No. 5, Industrial Layout, Koramangala, Bangalore-560034 (KN/6893) Karnataka, have agreed that the provision of the Employees' Provident Fund and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-Section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S-35019/490/84-SS-II]

का. आ. 68.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स स्कोप इलेक्ट्रोनिक्स प्राइवेट लिमिटेड, 6-3-1086/ए, राजभवन रोड, सोमाजीगुडा, हैदराबाद-500482 और इसके दो कार्यालय (1) 6-3-864/5, अमीरपेट ग्रीनलैंडस हैदराबाद-16(2) ए-1-53, शान्थी कालोनी, अन्नानगर मद्रास-600040 सहित, नामक स्थापन के सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए ।

अतः, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के उपबध उक्त स्थापन को लागू करती है ।

[सं. एस-35019/491/84-एस. एस. 2]

S.O. 68.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs. Scope Electronics Private Limited, 6-3-1086/A, Raj Bhavan Road, Somajiguda, Hyderabad 500482 including its office at (1) 6-3-864/5, Ameerpet, Greenlands, Hyderabad-16 (2) AI-53, Shanthi Colony, Annanagar, Madras-600040, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Fund and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-Section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S-35019/491/84-SS-II]

का. आ. 69 :—मैसर्स आर. एस. मैटल प्राईवेट लिमिटेड इन्डस्ट्रीयल इस्टेट, 22 गोदाम, जयपुर (आर/1474) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन अनुज्ञेय हैं;

अतः, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, राजस्थान को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर निर्दिष्ट करे।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा-17 की उपधारा (3क) के खंड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करे।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अंतर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अंतरण, निरीक्षण प्रभारों का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति, और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद, संस्थान के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक, सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाये जाते हैं तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय है।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नाम निर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबंधों में कोई भी संशोधन प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, राजस्थान के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की सम्भावना हो, वहां प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है अधीन नहीं रह जाते हैं, या उस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह रद्द की जा सकती है।

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक उस नियत तारीख के भीतर, जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है, और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो, छूट रद्द की जा सकती है।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अंतर्गत होते, बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा।

12. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक, इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देशितियों/विधिक वारिसों को बीमाकृत रकम का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के सात दिन के भीतर सुनिश्चित करेगा।

[सं. एस-35014/137/84-एस. एस. 4]

S.O. 69.—Whereas Messrs. R. S. Metals Private Limited, Industrial Estate, 22, Godam, Jaipur (RJ/14/4) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of Section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Rajasthan and maintain such accounts and provide such facilities for inspection as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of account, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme, shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Rajasthan and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium and responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the members covered under the Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/Legal heirs of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claim complete in all respects.

[No. S-35014/137/84-SS-IV]

का. आ. 70:—मैसर्स हरियाणा स्टील ग्लास लि ग्राम—सेवली, पो. एन.—राय, जिला—सोनीपत (पी एन/6129) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय हैं;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, हरियाणा को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर निर्दिष्ट करे।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा-17 की उपधारा (3क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करे।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अंतर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अंतरण, निरीक्षण प्रभारों का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति, और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद, संस्थान के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी

स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक, सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा।

4. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाये जाते हैं तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस / नाम निर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबंधों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, हरियाणा के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो, वहां प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है अधीन नहीं रह जाते हैं, या उस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह रद्द की जा सकती है।

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक उस नियत तारीख के भीतर, जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है, और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो, छूट रद्द की जा सकती है।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में, उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अंतर्गत होते, बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा।

12. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक, इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देशितियों/विधिक वारिसों को बीमाकृत रकम का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के सात दिन के भीतर सुनिश्चित करेगा।

[सं. एस-35014/141/84-एस. एस.-4]

S.O. 70.—Whereas Messrs. Haryana Steel Glass Limited, Village Sevli, Police Station Rai, District, Sonepat (PN/6129) (herein-after referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of Section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corpiration of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees then the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Haryana and maintain such accounts and provide such facilities for inspection as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of account, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme, shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Haryana and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium and responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the members covered under the Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/Legal heirs of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claim complete in all respects.

[No. S-35014/141/84-SS-IV]

का. ग्रा. 71:—मैसर्स पलानी ग्रन्डावर मिल्स लि., 236, धाल्ली रोड, उडुमालपेट, कोयम्बटूर डिस्ट्रिक्ट (टी. एन/49) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि ग्रौर प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है;

ग्रौर केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक ग्रभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं ग्रौर ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय हैं;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए ग्रौर इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, तमिलनाडू को ऐसी विवरणियां भेजेगा ग्रौर ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर निर्दिष्ट करे।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा-17 की उपधारा (3क) के खंड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करे।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अंतर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अंतरण, निरीक्षण प्रभारों संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति, ग्रौर जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद, संस्थान के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक, सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा ग्रौर उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाये जाते हैं तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नाम निर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबंधों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, तमिलनाडु के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा ग्रौर जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो, वहां प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है अधीन नहीं रह जाते हैं, या उस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह रद्द की जा सकती है।

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक उस नियत तारीख के भीतर, जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है, ग्रौर पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो, छूट रद्द की जा सकती है।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में, उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अंतर्गत होते, बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा।

12. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक, इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देशितियों/विधिक वारिसों को बीमाकृत रकम

का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के सात दिन के भीतर सुनिश्चित करेगा।

[सं.एस-35014/142/84-एस. एस.-4]

S.O. 70.—Whereas Messrs. Palani Andavar Mills Limited, 236, Dhally Road, Udumalpet, Coimbatore, District (TN/49) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of Section 17 of the Employees' Provident Funds & Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And, whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Tamil Nadu and maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme, shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Tamil Nadu and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner, shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium and responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the members covered under the Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/legal heirs of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claim complete in all respects.

[No. S-35014/142/84—SS-IV]

का. आ. 72 :—मैसर्स पंजाब स्टोन फोरजिंग एण्ड एग्रो इंडस्ट्रीज, जी. टी. रोड़, मंडी गोविन्दगढ़-147301 (पंजाब) (पी. एन./3328) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय हैं;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, पंजाब को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर निर्दिष्ट करे।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा-17 की उपधारा (3क) के खंड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करे।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अंतर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अंतरण, निरीक्षण प्रभारों संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति, और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद, संस्थान के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक, सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाये जाते हैं तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नाम निर्देशितों को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबंधों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, पंजाब के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की सम्भावना हो, वहां प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण का युक्तियुक्त देगा

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है अधीन नहीं रह जाते हैं, या उस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह रद्द की जा सकती है।

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक उस नियत तारीख के भीतर, जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है, और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है, तो छूट रद्द की जा सकती है।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में, उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अंतर्गत होते, बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा।

12. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक, इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देशितियों/विधिक वारिसों को बीमाकृत रकम का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के सात दिन के भीतर सुनिश्चित करेगा।

[सं. एस-35014/143/84-एस. एस.-4]

S.O. 72.—Whereas Messrs Punjab Steel Forging and Agro Industries, G.T. Road, Mandi Gobindgarh-147301 Punjab (PN/3328) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of Section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Povisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Punjab and maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from timt to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17, of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accouts, payment of inspection charges etc. shall bt borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available

under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme, shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Punjab and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium and responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the members covered under the Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/Legal heirs of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claim complete in all respects.

[No. S-35014/143/84-SS. IV]

का.आ. 73.—मैसर्स भाटिया स्टील इंडस्ट्रीज, आयरन एंड स्टील रोलिंग मिल्स, मंडी गोबिन्दगढ़-1, पंजाब, नार्थ रेलवे (पीएन/3878) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण अधिनियम, 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए यह फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय हैं;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त पंजाब को ऐसी विवरणियाँ भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार समय-समय पर निर्दिष्ट करे।

2. नियोजक ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा-17 की उपधारा (3क) के खंड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करे।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में जिसके अंतर्गत लेखाओं का रखा जाना विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अंतरण, निरीक्षण प्रभारों संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार, द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति, और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद, संस्थान के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक, सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाये जाते हैं तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप में वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नाम निर्देशिति को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबंधों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, पंजाब के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहाँ किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की सम्भावना हो, वहाँ प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है अधीन नहीं रह जाते हैं, या उस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह रद्द की जा सकती है।

10. यदि किसी कारण वश, नियोजक उस नियत तारीख के भीतर, जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है, और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है, तो छूट रद्द की जा सकती है।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में, उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अंतर्गत होते, बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा।

12. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक, इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देशितियों/विधिक वारिसों को बीमाकृत रकम का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के सात दिन के भीतर सुनिश्चित करेगा।

[एस०-35014/145/84-एसएस. 4]

S.O. 73.—Whereas Messrs Bhatia Steel Industries, Iron and Steel Rolling Mills, Mandi Govindgarh-1, Punjab, Northern Railway (PN/3878) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of Section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act) ;

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme) ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Punjab and maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17, of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefit available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme, shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Punjab and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium and responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the members covered under the Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/Legal heirs of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claim complete in all respects.

[No. S-35014/145/84-SS. IV]

का.आ. 74.—मैसर्स मेटल बॉक्स इंडिया लिमिटेड, 249, वार्ली रोड, वार्ली बम्बई—400018 (एम.एच/553) एण्ड इनकी इकाई ओल्ड बी, पी. टी. रोड, माहूल चैम्बर्स, ट्राम्बे बम्बई—74 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है ;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहित बीमा स्कीम अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा

रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसमें उसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय हैं;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, बम्बई को ऐसी विवरणियाँ भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर निर्दिष्ट करे।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा-17 की उपधारा (3क) के खंड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करे।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अंतर्गत लेखाओं का रखा जाना विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अंतरण, निरीक्षण प्रभारों, संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति, और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद, संस्थान के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक, सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाये जाते हैं तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय है।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नाम निर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबंधों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, बम्बई के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की सम्भावना हो, वहां प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है अधीन नहीं रह जाते हैं, या उस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह रद्द की जा सकती है।

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक उस नियत तारीख के भीतर, जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है, और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो, छूट रद्द की जा सकती है।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में, उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा।

12. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक, इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देशितियों/विधिक वारिसों को बीमाकृत रकम का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के सात दिन के भीतर सुनिश्चित करेगा।

[एस-35014/146/84-एस.एस.-4]

S.O. 74.—Whereas Messrs Metal Box India Limited, 249 Worli Road, Worli, Bombay-400018 (MH/553) including its one Unit at Old B. P. T. Road, Mahul Chambers, Trombay, Bombay-74, (MH/9529) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of Section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the

Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Bombay, and maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from timt to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission, payment of inspection charges etc. shall be borne by account, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employees, who is already a member of the Employets' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme, shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Bombay and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium and responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the members covered under the Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/Legal heirs of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claim complete in all respects.

[No. S-35014/146/84-SS. IV]

का.ग्रा. 75.—मैसर्स पहल इन्जिनियरिंग एण्ड कांस्ट्रक्शन कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, 86, नेहरु प्लेस, नई दिल्ली-19। (डी.एल. 5597) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा, स्कीम, 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय हैं;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, दिल्ली को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर निर्दिष्ट करे।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3क) के खंड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करे

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसमें अंतर्गत लेखाओं का रखा जाना विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अंतरण, निरीक्षण प्रभारों संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार, द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति, और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी बातों का अनुवाद, संस्थापन के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक, सामूहिक बीमा स्कीम

के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा ।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाये जाते हैं तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं ।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नाम निर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा ।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबंधों में कोई भी संशोधन, प्रदेशिक भविष्य निधि आयुक्त, दिल्ली के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की सम्भावना हो, वहां प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा ।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है अधीन नहीं रह जाते हैं, या उस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते है, तो यह छूट रद्द की जा सकती है ।

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक उस नियत तारीख के भीतर, जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है, और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो, छूट रद्द की जा सकती है ।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में, उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अंतर्गत होते, बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा ।

उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक, इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देशितियों/विधिक वारिसों को बीमाकृत रकम का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के सात दिन के भीतर सुनिश्चित करेगा ।

[सं एस० 35014/149/84-एस.एस. 4]

S.O. 75.—Whereas Messrs Chahl Engineering and Construction Company Private Limited, 86, Nehru Place, New Delhi-19 (DL5597), (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of Section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act) ;

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme) ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme, for a period of three years.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Delhi and maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17, of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charge etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Govtrnment and as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme, shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Delhi and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium and responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the members covered under the Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/Legal heirs of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claim complete in all respects.

[No. S-S-35014/149/84-SS-IV]

का. आ. 76.—मैसर्स आदर्श पेंकर्स, 35, आनन्द लोक, नई दिल्ली-49 (डी. एल./3962) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय हैं;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन के तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, दिल्ली को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर निर्दिष्ट करे।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा-17 की उपधारा (3क) के खंड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करे।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अंतर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अंतरण, निरीक्षण प्रभारों का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति, और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद, स्थापन के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक, सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाए जाते हैं तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नाम निर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबंधों में कोई भी संशोधन प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, दिल्ली के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो, वहां प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जिसे स्थापन पहले अपना चुका है अधीन नहीं रह जाते हैं, या उस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह छूट रद्द की जा सकती है।

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक उस नियत तारीख के भीतर, जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है, और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो, छूट रद्द की जा सकती है।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में, उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई

होती तो उक्त स्कीम के अंतर्गत होते, बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा।

12. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक, इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देशितियों/विधिक वारिसों को बीमाकृत रकम का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के सात दिन के भीतर सुनिश्चित करेगा।

[सं एस. -35014/150/84-एस एस 4]

S.O. 76.—Whereas Messrs Adarsh Packers, 35, Anand Lok, New Delhi-49 (DL/3962) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of Section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act) ;

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Delhi and maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heirs/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme, shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Delhi and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium and responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the members covered under the Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/Legal heirs of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claim complete in all respects.

[No. S-35014/150/84-SS-IV]

का. आ. 77.—मैसर्स अंकुर एक्सपोर्ट प्रोडक्ट लिमिटेड भवानी सिंह रोड, जयपुर (आर. जे./2500) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय हैं;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, राजस्थान को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी

सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर निर्दिष्ट करे।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की ( ) के खंड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करे।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अंतर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अंतरण, निरीक्षण प्रभारों संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति, और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद संस्थान के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक, सामूहिक बीमा स्कीम के ससदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमिमिय भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाये जाते हैं तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नाम निर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबंधों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, राजस्थान के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की सम्भावना हो, वहां प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापना के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है अधीन नहीं रह जाते हैं, या उस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह रद्द की जा सकती है।

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक उस नियत तारीख के भीतर, जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है, और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में में, उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अंतर्गत होते, बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा।

12. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक, इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देशितियों विधिक वारिसों को बीमाकृत रकम का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के सात दिन के भीतर सुनिश्चित करेगा।

[सं. एस.-35014/160/84-एस.एस-4]

S.O. 77.—Whereas Messrs Ankur Exports Private Limited, Bhawani Singh Road, Jaipur (RJ|2500) (herein-after referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of Section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Rajasthan and maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc., shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance

Scheme as approved by the Central Government and as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir|nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme, shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Rajasthan and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium and responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the members covered under the Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee|Legal heirs of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claim complete in all respects.

[No. S-35014|160|84-SS-IV]

का. आ. 78.—मैसर्स होटल वैलकम ग्रुप मानसिंह, संसार चन्द्रा रोड, जयपुर (आर.जे. 2583) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19), (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारीयों के लिए ये फायदे इन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम 1976 (जिसे इसमें पश्चात उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय हैं।

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, राजस्थान को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर निर्दिष्ट करे।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3क) के खंड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करे।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अंतर्गत लेखाओं का रखा जाना विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना बीमा प्रीमियम का संदाय लेखाओं का अंतरण, निरीक्षण प्रभारों संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति, और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद, संस्थान के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक, सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारीयों को उपलब्ध फायदे बढ़ाये जाते हैं तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारी के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नाम निर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबंधों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, राजस्थान के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारीयों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की सम्भावना हो, वहां प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारीयों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है अधीन नहीं रह जाते हैं, या उस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फ़ायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह रद्द की जा सकती है।

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक उस नियत तारीख के भीतर, जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है, और पालिसी, को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अंतर्गत होते बीमा फ़ायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा।

12. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक, इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देशितियों/विधिक वारिसों को बीमाकृत रकम का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के सात दिन के भीतर सुनिश्चित करेगा।

[सं. एस-35014/162/84-एस. एस.-4]

S.O. 78.—Whreas Messrs Hotel Welcome Group Mansingh, Sansar Chandra Road, Jaipur (RJ|2583), (herein-after referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of Section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952(19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme):

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Rajasthan and maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits ava lable to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir|nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme, shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Rajasthan and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium and responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the members covered under the Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee|Legal

heirs of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claim complete in all respects".

[No. S-35014|162|84-SS-IV]

का. आ. 79.—मैसर्स इण्डियन आयल कार्पोरेशन लिमिटेड 254-सी, डा. एनी बेसेंट रोड, प्रभावती, मुम्बई—400025 (एम. एच. 2579) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है, की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय हैं;

अत: केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के संबंध में नियोज प्रदेशिक भविष्य निधि आयुक्त, महाराष्ट्र को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर निर्दिष्ट करे।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा-17 की उपधारा (3क) के खंड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करे।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अंतर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अंतरण, निरीक्षण प्रभारों संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद, संस्थान के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो नियोजक, सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम, भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाये जाते हैं तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नाम निर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबंधों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, महाराष्ट्र पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की सम्भावना हो, वहां प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा।

9. यदि किसी कारणवश स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है अधीन नहीं रह जाते हैं, या उस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह रद्द की जा सकती है।

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक उस नियत तारीख के भीतर, जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है, और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो, छूट रद्द की जा सकती है।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में, उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशितियों या विधिक/वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अंतर्गत होते, बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा।

12. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक, इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देशितियों/विधिक वारिसों को बीमाकृत रकम का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा

निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के सात दिन के भीतर सुनिश्चित करेगा।

[सं. एस.-35014/163/84-पी.एफ-2]

S.O. 79.—Whereas Messrs. Indian Oil Corporation Limited, 254-C, Dr. Annie Besant Road, Prabhadevi, Bombay-25 (MH|2579) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section 2A) of Section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Maharashtra and maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir|nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme, shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Maharashtra and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium and responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the members covered under the Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/Legal heirs of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claim complete in all respects".

[No. S-35014/163/84-SS-IV]

का. आ. 80.—मैसर्स गुजरात मिनिरल डेवेलपमेन्ट कारपोरेशन लिमिटेड, खानजी भवन, आपोजिट नेहरू ब्रिज, आश्रम रोड-अहमदाबाद-9 (जी. जे.-2610) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय हैं;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है।

अनुसूची

3. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, गुजरात को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर निर्दिष्ट करे।

2. नियोजक ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3क) के खंड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करे।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अंतर्गत लेखाओं का रखा जाना विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अंतरण, निरीक्षण प्रभारों संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा।

4. नियोजक केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति, और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद संस्थान के सूचनापट्ट पर प्रदर्शित करेगा।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन का भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक, सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाए जाते है तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नाम निर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबंधों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त गुजरात के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की सम्भावना हो, वहां प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा।

9. यदि किसी कारणवश स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के जिसे स्थापन पहले अपना चुका है अधीन नहीं रह जाते हैं, या उस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह छूट रद्द की जा सकती है।

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक उस नियत तारीख के भीतर जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है, और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो, छूट रद्द की जा सकती है।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में, उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अंतर्गत होते बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा।

12. उक्त स्थापन के सम्बंध में नियोजक इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देशितियों/विधिक वारिसों को बीमाकृत रकम का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के सात दिन के भीतर सुनिश्चित करेगा।

[सं. एस-35014/164/83-पी.एफ.-2]

S.O. 80.—Whereas Messrs Gujarat Mineral Development Corporation Limited, Khanji Bhavan, Opposite Nehru Bridge, Ashram Road, Ahmedabad-9 (GJ|2610) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of Section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Gujarat and maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspector charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir|nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme, shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Gujarat and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium and responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the members covered under the Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee|Legal heirs of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claim complete in all respects".

[No. S-35014|164 |84-SS-IV]

का. आ. 81.मसस ओटिस एलीवेटर कम्पनी (इंडिया) लिमिटेड, गेटवे बिल्डिंग, अपोलो बन्दर, बम्बई–400039 (म. ह./4154) और इसकी फैक्टरी अकुर्ली रोड, कन्डीवली (ईस्ट) बम्बई–4000101, (म. ह./2295) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है ;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय हैं ;

अतः केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इस उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि, के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त बम्बई को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार समय-समय पर निर्दिष्ट करे।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3क) के खंड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करे।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अंतर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय लेखाओं का अंतरण निरीक्षणों के प्रभार संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति, और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद संस्थान के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा।

5 यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन से नियोजित किया जाता है तो, नियोजक, सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाये जाते हैं तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए

सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हो जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं।

सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता, तो नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नाम निर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, बम्बई के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की सम्भावना हो, वहां प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के जिसे स्थापन पहले अपना चुका है अधीन नहीं रह जाते हैं, या उस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह रद्द की जा सकती है।

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक उस नियत तारीख के भीतर, जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में, उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो, उक्त स्कीम के अंतर्गत होते, बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा।

12 उक्त स्थापन में नियोजक, इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य कि मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देशितियों/विधिक वारिसों को बीमाकृत रकम का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमा कृत रकम प्राप्त होने के सात दिन के भीतर सुनिश्चित करेगा।

[सं० एस- 35014/166/84 एस एस-4]

S.O. 81.—Whereas Messrs Otis Elevator Company (India) Limited, Gateway Building, Apollo Bunder, Bombay-400039 (MH|4154) and its factory at Akurli Road, Kandivli (East), Bombay-400101 (MH|2295) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section 2A) of Section 17 of the Employees' Provident Funds & Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Bombay and maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspector charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir|nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme, shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner Bombay and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium and responsibility for payment of

assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the members covered under the Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/legal heirs of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claim complete in all respects".

[No. S-35014/166/84-SS-IV]

का. आ. 82 यतः मै० तमिल अरासु प्रेस, गवर्नमेंट इस्टेट मद्रास-2 (टी-एन/8726) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम 1952 (1952 का 19) की धारा 17 की उपधारा (1-क) के अन्तर्गत कर्मचारी कुटुम्ब पेंशन स्कीम, 1971 से छूट प्राप्ति के लिए आवेदन किया है।

और यतः केन्द्रीय सरकार की राय में केन्द्रीय सरकार कुटुम्ब पेंशन स्कीम, 1964 के अन्तर्गत कुटुम्ब पेंशन के रूप में देय लाभ उपरोक्त स्थापन के कर्मचारियों पर लागू होते हैं और वे लाभ कर्मचारी कुटुम्ब पेंशन स्कीम, 1971 के अन्तर्गत देय लाभों से किसी भी रूप में कम नहीं हैं।

अतः अब, उपरोक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1-क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और विनिर्दिष्ट शर्तों के आधार पर केन्द्रीय सरकार उपरोक्त स्थापना को कर्मचारी कुटुम्ब पेंशन स्कीम, 1971 के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से 3 वर्ष की अवधि के लिए छूट प्रदान करती है।

शर्तें :

(1) स्थापनाओं के कुटुम्ब पेंशन स्कीम में किसी बात के होते हुए भी यदि किसी सदस्य की मृत्यु होने पर देय पेंशन राशि कर्मचारी कुटुम्ब पेंशन स्कीम, 1971 के अन्तर्गत देय पेंशन राशि से कम होती है तो नियोक्ता को कर्मचारी कुटुम्ब पेंशन स्कीम, 1971 के अन्तर्गत देय कुटुम्ब पेंशन की दर से पेंशन मंजूर करेगा।

(2) नियोक्ता को केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए निदेशानुसार लेखे तैयार करने होंगे विवरणियां जमा करानी होंगी तथा निरीक्षण के लिए आवश्यक सुविधाएं प्रदान करनी होंगी।

उपरोक्त स्थापना के कुटुम्ब पेंशन स्कीम से संबंधित सभी खर्चों को नियोक्ता को वहन करना होगा जिसमें लेखे तैयार करना, लेखे और विवरणियां जमा कराना, लेखों का अन्तरण करना आदि भी शामिल होंगे।

(4) उपरोक्त स्थापना के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित कर्मचारी कुटुम्ब पेंशन स्कीम तथा उसमें किए संशोधन यदि कोई हो, तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या द्वारा समझी जाने वाली भाषा में उसकी महत्वपूर्ण बातों के अनुवाद की एक प्रति नियोक्ता को सूचनापट्ट पर लगानी होगी।

(5) स्थापना की कुटुम्ब पेंशन स्कीम के नियमों में कोई भी ऐसा संशोधन जो कर्मचारियों के हितों को बुरी तरह प्रभावित करता हो केन्द्रीय सरकार के श्रम मंत्रालय तथा केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जायेगा। केन्द्रीय सरकार तथा केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त अपनी अनुमति देने से पूर्व कर्मचारियों को अपने विचार प्रकट करने के लिए समुचित अवसर प्रदान करेंगे।

[फाईल सं. एस-35012/2/84-एस.एस-4]

S.O. 82.—Whereas the M/s. Tami Arasu Press, Government Estate, Madras-2 (TN/8726) has applied for exemption from Employees' Family Pension Scheme, 1971, under sub-section (1A) of section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952).

And whereas, in the opinion of the Central Government the benefits in the nature of Family Pension under the Central Government Family Pension Scheme, 1964 and applicable to the employees of the said establishment are not less favourable than the benefits provided under the said Act, and the Employees' Family Pension Scheme, 1971.

Now, therefore in exercise of the powers conferred by sub-section (1A) of section 17 of the said Act, and subject to the conditions specified hereunder, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all provisions of the Employees' Family Pension Scheme, 1971 for a period of three years.

CONDITIONS :

(1) Notwithstanding anything contained in the Family Pension Scheme of the establishments if the amount of pension payable in respect of any member upon his death is less than the amount of family pension payable if he were a member of the Employees' Family Pension Scheme, 1971 the Employer shall sanction the family pension which is admissible under Employees' Family Pension Scheme, 1971.

(2) The employer shall maintain such accouts, submit such returns and provide for such facility for inspection as the Central Government may from time to time direct.

(3) All expenses involved in the administration of the Family Pension Scheme of the said establishment including maintenance of accounts, submission of accounts and return, transfer of accounts, shall be borne by the employer.

(4) The employer shall display on the notice board of the establishment a copy of the rules incorporating therein all amendments, if any of the Family Pension Scheme of the said establishment as approved by the Central Government alongwith a translation of the salient featuress thereof in language understood by the majority of the employees.

(5) No amendment of the rules of the Family Pension Scheme of the establishments adversely affecting the interests of the employees shall be made without the prior approval of the Central Government in the Ministry of Labour and the Central Provident Fund Commissioner. The Central Government and the Central Provident Fund Commissioner will, before giving therein approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

[No. S-35012/2/84-SS-IV]

का. आ. 83 :—कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा 1 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा 30 दिसम्बर, 1984 को उस तारीख के रूप में नियत करती है, जिसको उक्त अधिनियम के अध्याय 4 (धारा 44 और 45 के सिवाय जो पहले ही प्रवृत्त की जा चुकी है) और अध्याय 5 और 6 (धारा 76 की उपधारा (1) और धारा 77, 78, 79 और 81 के सिवाय जो पहले ही प्रवृत्त की जा चुकी है) के उपबन्ध उड़ीसा राज्य के निम्नलिखित क्षेत्र में प्रवृत्त होंगे, अर्थात् :—

"जिला कटक में नुआपटना पी. एस. टीगिरिया के राजस्व ग्राम के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र।"

[सं. एस-38013/24/84-एस० एस.-1]

S.O. 83.—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 1 of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), the Central Government hereby appoints the 30th December, 1984 as the date on which the provisions of Chapter IV (except sections 44 and 45 which have already been brought into force) and Chapters V and VI (except sub-section (1) of section 76 and sections 77, 78, 79 and 81 which have already been brought into force) of the said Act shall come into force in the following areas in the State of Orissa, namely:—

"The area comprised within the revenue village of Nuapatna Police Station Tigiria in the District of Cuttack."

[No. S-38013/24/84-SS-I]

का. आ. 84.—कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा 1 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा 30 दिसम्बर, 1984 को उस तारीख के रूप में नियत करती है, जिसको उक्त अधिनियम के अध्याय 4 (धारा 44 और 45 के सिवाय जो पहले ही प्रवृत्त की जा चुकी है) और अध्याय 5 और 6 (धारा 76 की उपधारा (1) और धारा 77, 78, 79 और 81 के सिवाय जो पहले ही प्रवृत्त की जा चुकी है) के उपबन्ध तमिलनाडु राज्य के निम्नलिखित क्षेत्र में प्रवृत्त होंगे, अर्थात् :—

"जिला कोयम्बतूर में कोयम्बतूर तालुक के वीरापाण्डी के राजस्व ग्राम के अन्तर्गत आने वाला क्षेत्र।"

[सं. एस-38013/23/84-एस-एस-1]

S.O. 84.—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 1 of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), the Central Government hereby appoints the 30th December, 1984 as the date on which the provisions of Chapter IV (except sections 44 and 45 which have already been brought into force) and Chapters V and VI (except sub-section (1) of section 76 and sections 77, 78, 79 and 81 which have already been brought into force) of the said Act shall come into force in the following areas in the State of Tamil Nadu, namely:—

"The area comprised within the Revenue village of Veerapandi in Coimbatore Taluk in Coimbatore District."

[No. 38013/23/84/SS-I]

नई दिल्ली, 28 दिसम्बर, 1984

शुद्धिपत्र

का. आ. 85 :—भारत सरकार, श्रम और पुनर्वास मंत्रालय (श्रम विभाग) की अधिसूचना संख्या का० आ० 2172, तारीख 19 जून, 1984, जो भारत के राजपत्र, भाग 2, खंड 3, उपखण्ड (ii) में तारीख 7 जुलाई, 1984 को प्रकाशित हुई थी, में लाइन 4 में "एनवायरड" के स्थान पर "एनवायरो" पढ़ें।

[संख्या एस-35019/110/84-पी एफ-ii]

ए. के. भट्टाराई, अवर सचिव

New Delhi, the 28th December, 1984

CORRIGENDUM

S.O. 85.—In this notification of the Government of India in the Ministry of Labour and Rehabilitation (Department of Labour) No. S.O. 2172, dated the 19th June, 1984 published in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (ii), dated the 7th July, 1984 in line 4, for "Envired" read "Enviro".

[No. S-35019(110)/84-PF.II]

A.K. BHATTARAI, Under Secy.

New Delhi, the 20th December, 1984.

S.O. 86.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal No. 2, Dhanbad in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Kusunda Colliery of M/s. Bharat Coking Coal Limited and their workmen which was received by the Central Government on the 15th December, 1984.

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL (NO. 2), DHANBAD

Reference No. 72 of 1984.

In the matter of an industrial dispute under S. 10 (1) (d) of the I.D. Act, 1947.

Parties:

Employers in relation to the management of Kusunda colliery of M/s BCCL and their workmen.

APPEARANCES:

On behalf of the employers : None.

On behalf of the workmen : None.

STATE : Bihar

INDUSTRY : Coal.

Dhanbad, the 10th December, 1984

AWARD

This is an industrial dispute under S.10 of the I.D. Act, 1947. The Central Government by its order No. L- 20012 (247)/84-D.III(A) dated 29th September, 1984 has referred this dispute to the Tribunal for adjudication with the following schedule :

The Schedule

"Whether the demand of Rastriya Colliery Mazdoor Sangh that S/Shri Gouri Shankar Singh, Ramlakhan Singh, Ramkrit Thakur, Hare Ram Dhobi, Amira Singh and Rajendra Nonia of Kusunda Colliery of M/s Bharat Coal Ltd. P.O. : Kusunda, District Dhanbad should be placed in the pay scale of clerical grade-III as Munshis with effect from

January, 1978 is justified? If so, to what relief these workmen are entitled?"

2. The reference was received by this Tribunal on 10th October, 1984. The union which had raised the dispute did not file the statement of claim, with relevant documents, list of reliance and witnesses with the Tribunal within 15 days of the receipt of the order of reference and also did not forward any copy of the same to the opposite party involved in this dispute. A notice was also, issued to the union concerned but inspite of there adjournments the union did not file the statement of claim, etc. with the Tribunal nor sent any copy to the management and as such, no written statement has been filled on behalf of the management as well. On 20-11-84 again notice was issued though messenger which was received by the office of the union. But even then no step was taken on behalf of the union. However, another adjournment was given to comply with the provisions of law and 7th December, 1984 was the date fixed for compliance. But on that date no step was taken on behalf of the union.

3. It is for the sponsoring union to file the statement of claim, etc. within 15 days of the receipt of the order of reference. But the Tribunal took special care to give them notice to comply with the provisions of law in time as the amended rules are new. As the union is taking no step and has not even cared to file the statement of claim, etc. it appears that they have no case and as such, the statement of claim, etc. have not been filed by them.

In view of the above, I hold that the demand of Rastriya Colliery Mazdoor Sangh that S|Shri Gouri Shankar Singh, Ramlakhan Singh, Ramkrit Thakur, Hare Ram Dhobi, Amira Singh and Rajendra Nonia of Kusunda Colliery of M|s Bharat Coking Coal Ltd. P.O. Kusunda, District Dhanbad should be placed in the pay scale of clerical grade-III as Munshis with effect from January, 1978 is not justified. Consequently the workmen are entitled to no relief.

This is my award.

I.N. SINHA, Presiding Officer

[No. L-20012(247)/84-D-III (A)]

S.O. 87.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal No. 2, Dhanbad in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Loyabad Regional Store, in Area No. V of M|s. Bharat Coking Coal Ltd., Post Office Sijua, District Dhanbad and their workmen, which was received by the Central Government on the 15th December, 1984.

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL (NO. 2) AT DHANBAD

Reference No. 64 of 1982

In the matter of Industrial Disputes under Section 10(1)(d) of the I. D. Act, 1947

PARTIES :

Employers in relation to the management of Loyabad Regional Store in Area No. V of Messrs Bharat Coking Coal Ltd. Post Office Sijua, District Dhanbad and their workmen.

APPEARANCES

On behalf of the employer—Shri G. Prasad, Advocate.

On behalf of the workmen—Shri J. D. Lal, Advocate.

STATE : Bihar INDUSTRY : Coal

Dhanbad, the 11th December, 1984

AWARD

The Government of India in the Ministry of Labour in exercise of the powers conferred on them under Section 10(1)(d) of the I. D. Act, 1947 has referred the following dispute to this Tribunal for adjudication under Order No. L-20012(65)/82-D-III (A), dated, the 6th July, 1982.

SCHEDULE

"Whether the demand of the workmen of Loyabad Regional Store in Area No. V of Messrs Bharat Coking Coal Limited Post Office Sijua, District Dhanbad. for gradation of Shri Chitu Mahato, Crane Operator in Technical Grade-B, is justified? If so, to what relief is the said workman entitled?"

After issuance of notices, the parties appeared and filed their respective W.S. and rejoinder. The reference was being adjourned from date to date for hearing but it appears that the workman was not reporting himself to the learned Advocate who was representing his case and ultimately when the concerned workman did not turn up and his learned Advocate was not ready in his absence the evidence was closed and the learned Advocate appearing on behalf of the management was heard.

It will appear from the schedule of the reference that it was for the workman to establish their demand for the gradation of the concerned workman in Technical Grade-B. As no evidence was adduced on behalf of the workman and there is no material on the record to justify the demand of the workman. I hold that the demand of the workman of Loyabad Regional Store in Area No. V of M/s. B.C.C. Ltd. for gradation of the concerned workman Shri Chitu Mahato, Crane Operator in Technical Grade-B is not justified and he is not entitled to any relief. As the reference has not been contested there will be no order for costs.

this is my Award.

I. N. SINHA, Presiding Officer

[No. L-20012(65)/82-D.III (A)]

S.O. 88.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal No. 2, Dhanbad in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Bhatdee Colliery of M/s. Bharat Coking Coal Limited, and their workmen, which was received by the Central Government on the 15th December, 1984.

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL (NO. 2) DHANBAD

Reference No.69 of 1984.

In the matter of an industrial dispute under S. 10(1)(d) of the I. D. Act, 1947

PARTIES :

Employers in relation to the management of Bhatdee Colliery of M|s. Bharat Coking Coal Ltd. and their workmen.

APPEARANCES :

On behalf of the employers—None

On behalf of the workmen—None.

STATE : Bihar INDUSTRY : Coal

Dhanbad, the 10th December, 1984

AWARD

This is an industrial dispute under S. 10 of the I. D. Act, 1947. The Central Government by its Order No. L-20012(234)/84-D.III (A) dated 25th September, 1984 has referred this dispute to this Tribunal for adjudication with the following schedule :

SCHEDULE

"Whether the action of the management of Bhatdee Colliery of Messrs Bharat Coking Coal Ltd. in putting Shri Manu Lohar, a permanent Loader as Badli Loader, is justified? If not, to what relief the workman is entitled?"

2. The reference was received by this Tribunal on 10-10-84. The union which had raised the dispute did not file the statement of claim, with relevant documents, list of reliance and witnesses with the Tribunal within 15 days of the receipt of the order of reference and also did not forward any copy of the same to the opposite party involved in this dispute. A notice was also issued to the union concerned but inspite of three adjournments the union did not file the statement of claim, etc. with the Tribunal nor sent any copy to the management and as such, no written statement has been filed on behalf of the management as well. On 20-11-84 again notice was issued through messenger which was received by the office of the union. But even then no step was taken on behalf of the union. However, another adjournment was given to comply with the provisions of law and 7th December, 1984 was the date fixed for compliance. But even on that date no step was taken on behalf of the union.

3. It is for the sponsoring union to file the statement of claim, etc. within 15 days of the receipt of the order of reference. But the Tribunal took special care to give them notice to comply with the provisions of law in time as the amended rules are new. As the union is taking no step and has not even cared to file the statement of claim, etc. it appears that they have no case and as such the statement of claim, etc. have not been filed by them.

In view of the above I hold that the action of the management of Bhatdee Colliery of M/s. Bharat Coking Coal Limited in putting Shri Manu Lohar, a permanent Loader as Badli Loader is justified. Consequently, the workman is not entitled to any relief.

This is my award.

J.N. SINHA, Presiding Officer

[No. L-20012(234)/84-D.III (A)]

New Delhi, the 26th December, 1984

S.O. 89.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal No. 2 Dhanbad in the industrial dispute between the employers in relation to the management to Govindpur Colliery of Messrs Bharat Coking Coal Limited, Post Office Sonardih, District Dhanbad and their workmen which was received by the Central Government on the 19th December, 1984.

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL (NO. 2) AT DHANBAD

Reference No. 118 of 1982

In the matter of Industrial Disputes under Section 10(1)(d) of the I. D. Act, 1947

PARTIES :

Employers in relation to the management of Govindpur Colliery of Messrs Bharat Coking Coal Limited, Post Office Sonardih, District Dhanbad and their workmen.

APPEARANCES :

On behalf of the employers—Shri B. Joshi, Advocate.

On behalf of the workmen—Shri B. B. Pandey, Advocate.

STATE : Bihar INDUSTRY : Coal

Dhanbad, the 11th December, 1984

AWARD

The Government of India in the Ministry of Labour and Rehabilitation in exercise of the powers conferred on them under Section 10(1)(d) of the I. D. Act, 1947 has referred the following dispute to this Tribunal for adjudication under Order No. L-20012(121)/82-D.III (A), dated, the 11th December, 1982.

SCHEDULE

"Whether the demand of the workmen for re-employment of 37 ex-Wagon Loaders of Khas Mehtadih Section of Govindpur Colliery (listed in the Annexure) by the management of Bharat Coking Coal Limited, Post Office Sonardih, District Dhanbad in their Govindpur Colliery is justified ? If so, to what relief are the workmen concerned entitled ?"

ANNEXURE

Sl. No.	Name
1.	Shri Chhota Ram Beldar
2.	Smt. Satiya Kamin
3.	Shri Ram Saroop Beldar
4.	Smt. Dhanpatiya Kamin
5.	Shri Mugesar Beldar
6.	Shri Mahabir Beldar
7.	Smt. Parbati Kamin
8.	Smt. Vadhani Kamin
9.	Smt. Srimati Kamin
10.	Shri Kuldip Paswan
11.	Smt. Etwariya Kamin
12.	Shri Murari Prasad
13.	Smt. Parwati Kamin
14.	Shri Kail Dusadh
15.	Smt. Reshmi Kamin
16.	Smt. Jirwa Kamin
17.	Shri Devnandan Beldar
18.	Smt. Pachiya Kamin
19.	Shri Ram Adhar Singh
20.	Shri Dulal Chandra Pramanik
21.	Shri Surendar Sah
22.	Shri Basudeo Sah
23.	Shri Haribansh Prasad
24.	Shri Sitaram Beldar
25.	Shri Satendra Prasad
26.	Shri Raman Lal
27.	Shri Ramanuj Prasad
28.	Shri Janardhan Prasad
29.	Shri Krishna Beldar
30.	Smt. Sumitry Kamin
31.	Smt. Rajpaty Kamin
32.	Smt. Sam Kumari Kamin
33.	Shri Ram Das Beldar
34.	Shri Sahadeo Beldar
35.	Smt. Fulmani Majhian
36.	Smt. Rajmani Kamin
37.	Shri Deo Saran Beldar.

The case of the workmen is that the concerned 37 workmen named in the schedule were working as Wagon loaders at Khas Mehtadih Colliery since long before June, 1970 when the said colliery was owned by the erstwhile management. The concerned workmen were retrenched from service with effect from 30-5-70 by the erstwhile employer vide letter dated 30-4-70. The erstwhile management had assured the concerned workmen to be taken back on job when there would be work in future. The concerned workmen were paid due retrenchment compensation as per section 25-F of the Industrial Disputes Act, 1947. The said Khas Mehtadih Colliery was subsequently taken over w.e.f. 17-10-71 and was nationalised with effect from 1-5-72 and Khas Mehtadih Collitry was merged with Govindpur Colliery. Now the said Khas Mehtadih Colliery forms section of Govindpur Colliery under the ownership of M/s. B.C.C. Ltd. There are requirement of permanent wagon loaders in Govindpur Colliery but the management is applying unfair means to get the work done through new hands. The concerned workmen approached the management several times themselves and through their union for their re-employment but they were not provided with the employment. The union gave notice to the management vide Regd. The union gave notice to the non-employment of retrenched wagon loaders of Khas Mehtadih Section of Govindpur Colliery. There are enough work for wagon loader which are being done by new persons ignoring the right and claim of the concerned workmen who are retrenched workmen. The retrenched employees are entitled to their re-employment from the management of the Colliery

under the Coking Coal Mines (Nationalisation) Act and the said Act has given all protection to the retrenched workmen. It is submitted that the concerned workmen are entitled to be re-employed from the date from which new persons have been employed in their place in 1973 and that they are also entitled for full back wages and other consequential benefits.

The case of the management is that there was no relationship of employer and employee between the concerned workmen and the management of M/s. B.C.C. Ltd. and as such the present reference is invalid in law. Khas Mehtadih Colliery was taken over with effect from 17-10-71 and was nationalised with effect from 1-5-72 and it was merged with Govindpur Colliery and forms a section of Govindpur Colliery of M/s. B.C.C. Ltd. The concerned workmen were not in employment of Khas Mehtadih Colliery immediately before the taken over or nationalisation of Khas Mehtadih Colliery. As per Coking Coal Mines (Nationalisation) Act, 1972 the management of BCCL are under no obligation to re-employ any workmen whose services had either been terminated or were not in the employment of the Colliery on the date of take over on nationalisation. The concerned workmen had been retrenched by the erstwhile management long before the take over or nationalisation of Khas Mehtadih Colliery and as such the concerned workmen cannot claim re-employment under section 25-H of the Industdial Disputes Act. Since none of the 37 concerned workmen was in the employment of Khas Mehtadih Colliery at the time of take over or nationalisation the management is not at all legally bound or under any legal obligation to re-employ them. After the take over of Khas Mehtadih Colliery no new wagon loader has been appointed in the Colliery and there is no necessary for appointment or increase in the present strength of wagon loader in the colliery. There is not even sufficient work for the old existing wagon loader and as such they have to be kept engaged sometime by giving them alternative jobs. The management is not aware that the concerned workmen were in the employment at Khas Mehtadih Colliery at the time of erstwhile employer. The management had allowed all the workmen who were on the roll of Khas Mehtadih Colliery on the appointed day to work with the same conditions of service. The casual wagon loaders were allowed to continue as casual Wagon loaders till they were made permanent according to the rules of the management. The claim of the concerned workmen is belated and it has been raised very late by the union with the ulterior motive to induct false persons by manufacturing some documents. On the above plea it has been submitted on behalf of the management that the Award be made in their favour.

The only question to be considered is whether the concerned workmen are entitled to be re-employed in Govindpur Colliery.

The workmen have examined five witnesses in all. Out of them WW-1 Sri R. K. Ojha is Head Clerk of C.M.P.F. Office and is a formal witness. The remaining witnesses WW-2 to WW-5 are concerned workmen out of the lot of the 37 concerned workmen. The management has examined only one witness who is a Loading Supervisor. The concerned workmen have also exhibited three retrenchment notices issued to three concerned workmen and are marked Ext. W-1 to W-1/2. The management has exhibited Ext. M-1 which is Form B Register of Khas Mehtadih Colliery.

The case of the concerned workmen is that they were retrenched from service by the erstwhile employer of Khas Mehtadih Colliery with effect from 20-5-70 and that the erstwhile employer vide their letter dated 30-4-70 had retrenched them after payment of due retrenchment compensation as per section 25-F of the I.D. Act. The concerned workmen now claim re-employment from the present management of BCCL under section 25-H of the I. D. Act on the plea that they are old retrenched worker of Khas Mehtadih colliery and that the management requires wagon loaders and has actually appointed new persons as Wagon loders and did not give job to the concerned workmen. Although the management do not accept that the concerned workmen are retrenched workmen of Khas Mehtadih Colliery, it is submitted that even if the concerned workmen were retrenched workmen of Khas Mehtadih Colliery the present management is not bound under any law to give employment to the concerned workmen. The management has referred to Section 17 of the Coking Coal Mines (Nationalisation) Act, 1972 which relates to the provisions relating to the employees of Coking Coal Mines and Coke Oven Plants. Section 17 provides as follows :—

1. "Every person who is a workmen within the meaning of the Industrial Disputes Act, 1947, and has been immediately before the appointed day, in the employment of a Coking Coal Mine, shall become on and from the appointed day employee of the Central Government or, as the case may be of the Government company in which right, title and interest of such mine have vested under this Act and shall hold office or service in the Coking Coal Mines on the same terms and conditions and that the same rights to Pension Gratuity and other matters as would have been admissible to him if the rights in relation to such Coking Coal Mines had not been transferred to and vested in, the Central Government or the Government Company and continue to do so unless and until his employmet in such Coking Coal Mines in duly terminated or untill his remuneration terms and conditions of employment are duly altered by the Central Government or the Government company.

2. The Central Government or the Government company in which the right, title and interest in relation to a Coking Coal Mines have vested, may employ, on mutually acceptable terms and conditions in person who is not a workman within the meaning of I.D. Act and who has been immediately before the appointed day, in the employment of Coking Coal Mines, and on such employment the said person shall become an employee of the Central Government or the Government Company, as the case may be.

3. Save as otherwise provided in Sections 1 and 2 the services of every person employed by the owner or occupier of a Coking Coal Mines before the appointed day shall stand terminated on and from the specified date".

It will thus appear from the provisions made in Section 17 of the Coking Coal Mines (Nationalisation) Act that all those workmen who were immediately before the nationalisation in the employment of a Coking Coal Mines became an employee of the Central Government. The case of the concerned workmen is admittedly not covered under section 17 of the Act as they were admittedly retrenched by the erstwhile management long before the take over and nationalisation of the Coking Coal Mines. Clause 3 of Section 17 clearly provides that save as otherwise provided in sub-sections (1) and (2) of Section 17, the services of every person employed by the owner or occupier of a Coking Coal Mine before the appointed day shall stand terminated on and from the specified date. The provisions of the Coking Coal Mines Act, 1972 came into force on 1-5-1972 and the concerned workmen had been retrenched with effect from 30-5-70. Thus, according to clause (3) of Section 17 of the Act the services of all workmen not covered under clause 1 and 2 of Section 17 of the Act are terminated from 1-5-72.

Section 28 of the Coking Coal Mines (Nationalisation) Act deals with the effect of this Act on other laws. It provides that the provision of this Act shall have effect notwithstanding anything inconsistent therewith contained in any other law for the time being in force or in any instrument having effect by virtue of any law other than this Act, or in any decree or order of any Court, Tribunal or other authority. It is submitted on the basis of the provision of Section 28 of the Act by the management that this Act overrides the provision of the Industrial Disputes Act in respect of retrenchment as after nationalisation, the erstwhile management ceased to be the employer of Khas Mehtadih Colliery. On behalf of the management Section 25-FF of the I. D. Act has also been referred to in this connection. Section 25-FF deals with compensation to workmen in case of transfer or undertakings. It provides that where the ownership or the management of an undertaking is transferred whether by agreement or by operation of law, from the employer in relation to that undertakng to a new employer, every workman who has been in continuous service for not less than one year in that undertaking immediately before such transfer shall be entitled to notice and compensation in accordance with the provision of Section 25-FF. as if the workman had been retrenched. On the basis of this section it has been submitted on behalf of the management that the ownership of Khas Mehtadih Colliery has been transferred by operation of law and what

the workmen were entitled was to get notice and compensation in accordance with the provision of Section 25-FF and none of the workmen were thereafter entitled to claim employment under the new owner of the Coal Mines. Although Section 25-FF deals with compensation to workmen in case of transfer of undertaking, the principle underlying the said provision is that the workmen of the erstwhile management cannot claim any right from the new owner after the transfer of the Coal Mines. On careful reading of the entire scheme of the Coking Coal Mines (Nationalisation) Act, 1972, it appears that all the liabilities and obligations of the erstwhile management remained with the erstwhile management after this Act came into force from 1-5-72 and the Government took the responsibilities of taking the employees in service of only those employees who were in the employment of the Coking Coal Mines of the erstwhile management immediately before the nationalisation of take over. Thus it appears to my mind that although retrenched workmen could have claimed for re-employment if the said management had continued to own the said Coking Coal Mines provided that the said owner was in need of the workmen. The concerned workmen who were retrenched workmen of the erstwhile management cannot claim re-employment from the new owner on the plea that they were retrenched workmen of the erstwhile management. Considering the matter on the aspect of law discussed above, I hold that the concerned workmen are not entitled to claim re-employment from the management of BCCL.

On question of facts the case of the workmen is that about 400 new persons were appointed as casual workers in 1973 by the present management out of whom 350 have been made permanent but the concerned workmen who were retrenched have not been taken when there was need for wagon loaders. The case of the management, on the other hand, is that they had not made any new recruitment in the year 1973 as casual wagon loaders and that out of them 350 persons were not made permanent. WW-2, WW-3, WW-4 and WW-5 have stated that the management have made new appointment of Wagon loaders. MW-1 is a loading supervisor of the management who had been working in Khas Mehtadih Colliery in the capacity of Loading Chaprasi, Loading Clerk and Loading Supervisor since 1-10-53. He has stated that the concerned workmen S/Shri Chota Ram Beldar, Ram Saroop Beldar, Kali Dosadh, Deonandan Beldar, Pachiya Kamin and Deosaran Beldar were temporary wagon loaders and they were employed only on those days on which there were large number of supply of wagons. He has also stated that temporary and permanent workmen were all members of C.M.P.F. before take over and also after take over of the collieries. He has stated that those persons who were working as Wagon loaders under the contractor prior to nationalisation were taken as casual Wagon loaders after abolition of the contract system. But he does not say that any new person was appointed as Wagon loader after nationalsation. Ext. M-1 is the Form B Register of Khas Metadih Colliery of the erstwhile management as stated by MW-1. MW-1 stated that the last entry in this Form B Register is in respect of Raju Bhuia whose date of first appointment with the present owner is stated to be 26-2-74 but he does not appear to be the Wagon loader. Some other workmen from Sl. Nos. 543 to 575 and from 578 to 609 in Ext. M-1 are entries of Wagon loaders from which it will appear that some of them were first appointed by the present owner after the date of nationalisation. There is no definite evidence that these persons were loaders who were working under the Contractors prior to the nationalisation or whether they are completely new persons. In the absence or materials it is not possible to hold that the management had made new appointments of Wagon loaders after nationalisation. This question of fact, of course, was not very necessary for decision in this case in view of the findings made in the above para that the concerned workmen were not entitled to re-employment in view of the fact that they were retrenched long before the taking over and nationalisation of Khas Metadih Colliery.

In view of the discussions made above, I hold that the demand of the workmen for re-employment of the concerned 37 workmen listed in the schedule of reference for their re-employment in Govindpur Colliery of M/s. BCC Ltd. is not justified and the concerned workmen are entitled to no relief.

This is my Award.

I. N. SINHA, Presiding Officer
[No. L-20012(121)/82-D.III (A)]

S.O. 90.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal No. 2 in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Benedih Colliery of M/s. Bharat Coking Coal Ltd., and their workmen, which was received by the Central Government on the 15th December, 1984.

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL (NO. 2) DHANBAD

Reference No. 70/84

In the matter of an industrial dispute under S. 10(1)(d) of the I. D. Act, 1947.

PARTIES :

Employers in relation to the management of Benedih Collery of M/s. BCCL and their workmen.

APPEARANCES :

On behalf of the employers—None.

On behalf of the workmen—None.

STATE : Bihar INDUSTRY : Coal

AWARD

Dhanbad, the 10th December, 1984

This is an industrial dispute under S. 10 of the I. D. Act, 1947. The Central Government by its order No. L-20012 (245)/84-D.III (A) dated 25th September, 1984 has referred this dispute to this Tribunal for adjudication with the following terms :

SCHEDULE

"Whether the action of the management of Benedih Colliery of M/s. Bharat Coking Coal Ltd. in not regularising S/Shri Parsuram Dusadh, Jagdish Dusadh, Mutukdhari Dusadh, Laxman Das, as Drillers, Shri Ram Saroop Das as Explosive Carrier; Shri Madan Rewani as Pump Operator, Shri Krit Dusadh and Shri Bhusan Ram as General Mazdoors, Shri Hardayal Dusadh and Huba Mahato as Line Mistries and Shri Kaleshwar Dusadh as Fireman, with retrospective effect, is justified ? If not, to what relief these workmen are entitled ?"

2. The reference was received by this Tribunal on 10-10-84. The union which had raised the dispute did not file the statement of claim, with relevant documents list of reliance and witnesses with the Tribunal within 15 days of the receipt of the order of reference and also did not forward any copy of the same to the opposite party involved in this dispute. A notice was also issued to the union concerned but in spite of three adjournments the union did not file the statement of claim, etc. with the Tribunal nor sent any copy of to the management. However, written statement has been filed on behalf of the management. On 20-11-84 again notice was issued through messenger which was received by the office of the union. But even then no step was taken on behalf of the union. However, another adjournment was given to comply with the provisions of law and 7th December, 1984 was the date fixed for compliance. But even on that date no step was taken on behalf of the union.

3. It is for the sponsoring union to file the statement of claim, etc. within 15 days of the receipt of the order of reference. But the Tribunal took special care to give them notice to comply with the provisions of law in time as the amended rules are new. As the union is taking no step and has not even cared to file the statement of claim, etc. it appears that they have no case and as such, the statement of claim, etc. have not been filed by them.

In view of the above I hold that the action of the management of Benedih Colliery of M/s. Bharat Coking Coal Ltd. in not regularising S/Shri Parsuram Dusadh, Jagdish Dusadh Matukdhari Dusadh, Laxman Das as Drillers; Shri Ram Saroop Das as Explosive Carrier; Shri Madan Rewani as Pump Operator, Shri Krit Dusadh and Shri Bhusan Ram as General Mazdoors, Shri Hardayal Dusadh and Huba Mahato as Line Mistries and Shri Kaleshwar Dusadh as Fireman, with retrospective effect is justified. Consequently, the concerned workmen are entitled to no relief.

This is my award.

I. N. SINHA, Presiding Officer
[No. L-20012(245)/84-D.III (A)]
A. V. S. SARMA, Desk Officer

New Delhi, the 22nd December, 1984

S.O. 91.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal, New Delhi in the industrial dispute between the employers in relation to the Punjab & Sind Bank, Limited and their workmen, which was received by the Central Government on the 12th December, 1984.

BEFORE SHRI O. P. SINGLA, PRESIDIN GOFFICER, CENTRAL GOVT. INDUSTRIAL TRIBUNAL, NEW DELHI

I.D. No. 99 of 1978.

In the matter of dispute

BETWEEN

Shri Satnam Singh,
S|o S. Partap Singh,
r|o 546, Mukeempura,
Subzi Mandi, Delhi.

VERSUS

The Management of Punjab & Sind Bank Ltd. 'B' Block, Cannaught Place, New Delhi.

APPEARANCES :

Shri Jagat Arora—for the Management.

Shri Tara Chand Gupta—for the workmen

AWARD

The Central Government, Ministry of Labour, vide Order No. L-12012|68|78-D.II.A. dated 16|18th November, 1978, made the reference of the following dispute to this Tribunal for adjudication:—

"Whether the action of the management of Punjab & Sind Bank Ltd. in terminating the services of Shri Satnam Singh, Clerk, Malkaganj Branch of the Bank in Delhi, w.e.f. 11-2-78 is justified? If not, to what relief is the workmen entitled?"

2. The workman, Shri Satnam Singh was employed as apprentice clerk vide Management's letter dated 4-2-77 on a monthly salary of Rs.250|-. He joind at Branch Office Naraina w.e.f. 7-2-77. On 18-2-77 he applied for regular employment in the bank. By letter dated 23-8-77 he was appointed on six months probation with retrospective effect from 12-8-77 and signed a service agreement on 29-9-77. His services were transferred to Malkaganj Branch on 27-1-78 and were terminated on 11-2-78 by a letter of the same date.

3. The workman's case is that he had completed 240 days of service prior to the date of termination of service and retrenchment compensation was due to be paid to him under Industrial Disputes Act and that not having been done the termination of service was void ab initio. He claimed reinstatement in service with full back wages and continuity of service.

4. The Management contested the claim and asserted that the termination of service was during probation and the workman could not be allowed the earlier period 4-2-77 to 9-8-77 towards continuous service for the purposes of this reference and that no retrenchment compensation was due to be paid to him at all.

5. The following issues were framed :—

1. Whether the period of service between 7-2-77 to 9-8-77 should count towards continous service for the purposes of this reference.
2. As in the order of reference.

6. The evidence of the parties has been led and written arguments filed by the workman and oral arguments of the Management have been heard.

7. There is no reason whatsoever in not counting 7-2-77 to 8-9-77 towards continuous service of this workman and to add it to his service on probation. In so far as section 25-F of the I.D. Act, 1947 is concerned; there is no Authority for such a view and the Management plea has to be negatived on this point.

8. There is a decision of the Presiding Officer of National Industrial Tribunal, Bombay by Hon'ble Mr. Justice C. T. Dighe in Reference No. NTB-1 of 1979 in the award dated 4th December, 1981 published in Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-Section (ii) dated 16-1-1982. The national Industrial Tribunal was dealing with the dispute between the Management of the Reserve Bank of India and their Clase III employees. Regulation 25 (2) of the Staff Regulations of the Reserve Bank of India allowed the Bank to determine the services of an employee, after giving him notice or pay in lieu thereof. The National Industrial Tribunal examined the case law on the point including the Supreme Court's judgements in "State Bank of India Vs. Sundermani" reported in 1976 I LLJ 478, "Hindustan Steel Limited Vs. State of Orissa" reported in 1977 I LLJ page 1 ; "Santosh Gupta Vs. State Bank of Patiala" reported in 1980 II LLJ 72; and "Mohan Lal Vs. Bharat Heavy Electricals Limited" : 1981 II LLJ 70. The National Industrial Tribunal came to the conclusion that the conflict between the Staff Regulation and the special legislation, Industrial Disputes Act, 1947, should be resolved in the manner that they should yield to the provisions of Section 25-F of the Industrial Disputes Act, and the staff regulations granting power to terminate the services should be subject to Section 25-F of the Industrial Disputes Act in respect of workman governed by the said Act. His Lordship referred to the ruling in "L.I.C. Vs. D. J. Bahadur" reported in 1971 I LLJ 1" where the provisions of Section 25-F of the I.D. Act were made to govern the provisions of the LIC Act.

9. In view of this position of the law, the provisions of 'Sastry Award' modified by 'Desai Award' and 'Bi-partite Settlement' have also to yield to the Statutory provisions contained in Section 25-F of the Act, and the action under that provision must be subject to the observance of the provisions of Section 25-F of the I.D. Act, 1947.

10. It is not the case where the Management could not terminate the services of the workman, but the requirement is that in case of workman who had completed 240 days, the requirement of Section 25-F regarding notice and payment of retrenchment compensation should be complied with.

11. The Management did not follow this law, which was obligatory for the Management to do, and, therefore, the termination of services of the workman is illegal and void on account of transgression of provisions of Section 25-F of the Industrial Disputes Act, 1947, which takes within its fold all types of termination of services except those specifically exempted in it. However, it would be no use of appointing this workman in service to have his services terminated at the next opportunity by the Management on payment of retrenchment compensation and notice-pay. Therefore, it is a proper case where the compensation may be paid in the sum of Rs. 33,000/- by way of compensation in lieu of reinstatement in service and back wages to the workman. I, therefore, direct that the Management should pay Rs. 33,000/- to the workman as compensation for the termination of his services which was not in accordance with the provisions of Section 25-F of the I.D. Act and which provision was applicable to the workman, but the claim of of the workman for reinstatement in service with full back wages in declined.

12. The Award is made in the terms aforesaid.

Further ordered that the requisite number of copies may be forwarded to the Central Government for necessary action at their end.

December 7, 1984.

O. P. SINGLA, Presiding Officer

[No. L-12012/68/78/DII(A)/D.IV(A)]

New Delhi, the 27th December, 1984

S.O. 92.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal, Hyderabad in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Visakapatnam Port Trust, Visakhapatnam and their workmen, which was received by the Central Government on the 17th December, 1984.

BEFORE THE INDUSTRIAL TRIBUNAL (CENTRAL) AT HYDERABAD)

PRESENT :

Sri J. Venugopala Rao, Industrial Tribunal (Central).
Industrial Dispute No. 39 of 1982

BETWEEN

Workmen of Visakhapatnam Port Trust, Visakhapatnam.

AND

The Management of Visakhapatnam Port Trust, Visakhapatnam.

APPEARANCES :

Sri G. Bikshapathi, Advocate—for the Workmen.

Sri K. S. Murthy and Miss G. Sudha, Advocates—for the Management.

AWARD

The Government of India, Ministry of Labour, New Delhi through Order No. L-34011(10)/82-D.IV(A) dated 14-10-1982 referred under Sections 7 and 10(1)(d) of the Industrial Disputes Act, 1947, the following dispute existing between the Management of Visakhapatnam Port Trust, Visakhapatnam and its workmen, to this Tribunal for adjudication :

"Whether the action of the Management of Visakhapatnam Port Trust in refusing to supply shoes to Grade II Drivers of M. V. Section is justified?

If not to what relief are the concerned workmen entitled?"

2. This reference was registered as Industrial Dispute No. 39 of 1982 and notices were issued to all parties, mentioned in the order of reference.

3. The workmen represented by General Secretary, Port and Dock Employees' Association, Visakhapatnam filed this Claims Statement stating that the Management of Visakhapatnam Port Trust, Visakhapatnam represented by its Chairman is having fleet of vehicles light and heavy and for the purposes of operation of their vehicles they employed Drivers. It is mentioned that there are about 10 vehicles in all and the posts of Drivers are divided into Grade I and Grade II Drivers with different pay scales (Rs. 450—700 Grade I and Rs. 425—535 Grade II respectively). It is mentioned that 10 per cent of the posts are made as Grade I Drivers for promotional opportunities and the scales were implemented from 1-1-1974 as recommended by Wage Revision Committee. It is their case that it is recommended that the Motor Drivers of both the scales should be functionally inter-changeable.

4. It is mentioned that there are 18 Grade I Drivers and 73 Grade II Drivers in the Motor Vehicle Section of the Management Port Trust. All these Drivers are rotated once in a year on light and heavy vehicles for the purpose of operation.

5. While so, the Management is supplying Safety Shoes only to Grade I Drivers and Grade II Drivers are denied the said facility of Safety Shoes. According to Workmen, both the categories of Drivers are performing the same nature of duties and they are liable for rotation every year from one vehicle to another and the nature of work of Drivers with reference to the operation of all vehicles is the same and the Grade of scales of pay is immaterial for discharging their duties efficiently. Incidentally it is mentioned that Grade II Drivers who are working at Ore Handling Complex were supplied with shoes and it is also mentioned that all the Private and Public Section Industries are also providing such shoes to their Drivers. So it is the request of the Workmen that the Grade II Drivers of M. V. Section are justified in demanding shoes as provided to Grade I Drivers.

6. As the required formalities failed in getting the sanction of the shoes to Grade II Drivers which is reasonable and justified, they wanted a direction should be given to the Management to provide shoes to Grade II Drivers of Motor Vehicle Section with two pairs of shoes while they drive heavy vehicles and one pair of shoes when thye are posted on light vehicles per year.

7. In the counter, the Management stated that the scope of reference is only about the claim of Grade II Drivers of Motor Vehicle Section for shoes or for any other alternative relief and any other than specific reference made by the Government to the Tribunal is beyond the scope of the jurisdiction of the Tribunal. So it is mentioned that this Tribunal should not pass any award directing the Management to provide shoes to Grade II Drivers of Ore Handling Complex with two pairs per year when they are posted on heavy vehicles and one pair when they are posted on light vehicles. So it is mentioned that any claim of the Grade II Drivers of Ore Handling Complex in this case is beyond the jurisdiction of the Tribunal and the same is liable to be dismissed in limini. It is admitted by the Management that it is maintaining various types of vehicles to ply in different work spots for which Drivers are engaged. According to him the working conditions of the Drivers vary depending upon the type of vehicle and the place where the vehicles have to be operated. It is mentioned further as a matter of policy that the Grade I Drivers are posted on work of staff cars, Ambulances, Mini Buses and the functions of these drivers will mainly come in contact with the public and distinguished visitors and guests of the Management. According to him in order to maintain the image of the Management in eyes of public and distinguished guests and V.I.Ps., they are provided with Uniform as well as foot wear i.e. leather shoes so as to avoid soling and to maintain full upkeep and decorum for physical appearance. It is pointed out that it is not necessary to maintain such up-keep and decorum in so far as Grade II Drivers are concerned who are posted on lorries, jeeps etc. and as such they are only supplied with Uniforms and there is no need or necessity to provide shoes to Grade II Drivers of Motor Vehicle Section.

8. It is also mentioned that the Grade I Drivers are appointed on the basis of seniority and suitability and on passing the Trade Test from among the Grade II Drivers and as such Grade I Drivers will have better privileges compared to that of Grade II Drivers. I is contended that the same privilege canont be extended to Grade II Drivers.

9. It is incidentally pointed out that the Grade II Drivers working in Ore Handling Complex are provided with Safety Shoes but not leather shoes which is the subject matter of the reference. It is also mentioned that the working condition of Grade II working in Ore Handling Complex differ from working condition of other Grade II a drivers working in Motor Vehicle Section and than Grade II of M. V. Section are not eligible for supply of even Safety Shoes also. According to him there were three grades in Motor Vehicles Drivers in the Visakhapatnam Port Trust Management on scale (1) Rs. 150-225; (2) Rs. 150-253 and (3) Rs. 170-290. The Drivers of Scales (1) and(2) above are treated as one group for the purpose of rotation and the drivers of Scale (3) above were treated as another group for the purpose of deployment and rotation. Thus it is their case that there is interchangeability within the same group but not between the two groups. It is also mentioned that interchangeability between Grade II and Grade I Drivers is not automatic and there is no interchangeability. Finally it is mentioned that there is no justification for the supply of either of two pairs or a pair of shoes to Grade II Drivers of Motor Vehicle Section and wanted this reference to be answered in favour of the Management.

10. On behalf of the Workmen two witnesses were examined. W.W. 1 (A. Rahman) and W.W. 2 (B. H. Jaidev) W.W. 1 is the General Secretary of the Port Dock Employees' Association while W.W. 2 is the Grade II Driver in Motor Vehicle Section of the Port Trust. They marked Ex. W1 which is a letter dated 31-5-1982 addressed by the Assistant Labour Commissioner, Visakhapatnam to the Secretary to Government of India, Ministry of Labour, New Delhi with reference to 20 demands made by the

Employees' Association of the Port Trust. Demand No. 19 of the same refers to supply of shoes to the Drivers of Motor Vehicle Section. W.W. 1 deposed that their Association is a registered Trade Union. According to him there were two grades of Drivers Grade I and Grade II in the Port Trust, Visakhapatnam after the Wage Revision Committee Recommendations for the purpose of driving motor vehicles. According to him, the Wage Revision Committee recommended for all the Drivers as interchangeable functions and 20 per cent of Grade II Drivers should be promoted to Grade I Drivers having higher scales of pay. It is also mentioned that Paras 10.29 of the Wage Revision Committe refers to this aspect. It is his case that both Grade I and Grade II Drivers are supplied with Rain Coats, Caps, Uniforms and Grade II Drivers working at Ore Handling Complex are also provided with shoes. It is his case that Grade II Drivers working in other sections are not supplied with shoes while Grade I Drivers are supplied with shoes. He mentioned that there will be heat at the engine and for protection of legs, shoes are required and shoes would also provide grip over the brakes, accilator and gear. He denied that shoes are meant for decoration purpose and that they are required for protection and safety. According to him shoes are essential for driving vehicles and more so for heavy vehicles. He pointed out that he made representation to the Management also. According to him there are 60 vehicles in the Port Trust in different sections. He further ordered that Grade II Drivers also work on those vehicles driven by Grade I Drivers whenever Grade I drivers apply leave and thus they are also driving the Staff Cars, Mini Buses and Ambulances. He asserted that the working conditions are same for all the vehicles and also pointed out that it did not vary from vehicle to vehicle and from place to place. He admitted that leather shoes are given to Grade I drivers and Safety shoes are also made of leather. According to him all the drivers come into contact with public and higher officials and it is not correct to say that only for decorum that Grade I drivers are provided with shoes.

11. W.W. 2 is the Grade II driver by name Sri B. H. Jaidev. He deposed that he is Grade II Driver in Moto Vehicle Section and that he is driving jeeps, cars, ambulances, Road Rollers and other heavy vehicles. It is his case that the Management did not provide them with shoes while they are supplying the same to grade I drivers and that shoes are required for safety and protection and he denied that the suggestion that the shoes are provided for the purpose of ornament.

12. On the other hand, for the Management the Personnel Officer of the Visakhapatnam Port Trust by name Shri Y. Bhadrachalam was examined as M.W.1. He explained that there are two types of drivers in the Port Trust since 1-1-1974 and Grade I drivers are paid the scale of Rs. 450-700 and Grade II drivers are paid in the scale of Rs. 425-655. He admitted that the present existing strength of Grade I drivers are 18 and Grade II drivers are 73. According to him the Grade I drivers are specially allocated and posted to drive the vehicle of Staff Cars (5), Vans (6) Mini-buses (2) and Ambulances (3). It is his case that other Grade II drivers are posted on other types of vehicles namely jeeps, Tractors, Trekkars, Lorries, Trippers and Road Rollers. He also admitted that Uniforms and caps are given to all the drivers irrespective of the grades. According to him Grade I drivers are provided with shoes also since they are posted on the vehicles involving of receiving of guests, visitors and V.I.Ps in order to give a better appearance decency and decorum and also to up-keep image of the Company. He asserted that Grade II drivers are not posted in the place of Grade I drivers. Of course he admitted that whenever Grade I drivers are absent or when they are on leave for short period, Grade II drivers who have already passed the Trade Test are posted in these vacancies temporarily. He produced Ex. M1 as order providing safety shoes to all the workers including the Ore Handling Complex drivers. He tried to explain the nature of work of Grade II drivers did not warrant wearing of shoes. In his cross examination he admitted that he had no experience of driving. He conceded that there is no Circular to show that Grade I drivers alone should be provided shoes on the ground that they have to meet the V.I.Ps. etc. He admitted that to protect Grade II drivers from sailing the clothes uniforms are given and he could not say whether there is any difference in the quality of uniform supplied to Grade I and Grade II drivers. He expressed his ignorance whether the Trekkars, Lorries and Trippers generate more heat at the engine than the small cars and Mini-buses.

13. *So it is necessary to decide whether the action of the* Management of Visakhapatnam Port Trust in refusing to supply shoes to Grade II drivers of Motor Vehicle Section is justifiable ?

14. The facts are very simple. Admittedly there are grades of drivers maintained by Visakhapatnam Port Trust Management. Pursuant to the Wage Revision Committee which came into force on 1-1-1974 drivers of Grade I are paid Rs. 450-700 and Grade II drivers are paid Rs. 425-555 per month. It is also correct to say that there is a percentage of reservation for Grade II drivers being promoted as Grade I basing upon the seniority and also when they passed required Trade Test. It is also not in dispute that Grade I drivers are allocated and posted to drive the staff Cars, Vans, Mini-buses and Ambulances in all numbering 16 as per the evidence of M.W.1. The petition filed by the workmen would show that there are about 70 vehicles in all maintained by the Visakhapatnam Port Trust and there are 18 Grade I drivers and 73 Grade II drivers in Motor Vehicle Section working in Visakhapatnam Port Trust. This averment in the statement filed by the Workmen Union is not denied in the counter. On the other hand M.W.1 admitted that there are 16 vehicles which are driven by Grade I drivers and other vehicles are driven by Grade II drivers. Thus the fact how many vehicles are there, used as Staff Cars, Vans, Mini-buses and Ambulances and how many are the Jeeps, Trakkers, Lorries, Trippers Tractors and Road Rollers is not the point. It is the admitted case that Grade I drivers are used for driving Staff Cars, Vans, *Mini-buses and ambulance while the other vehicles i.e. jeeps,* Trekkers, Lorries, Trippers, Tractors and Road Rollers are driven by Grade II drivers. It is also admitted that all the drivers are provided with uniforms. The Management's witness or the counter filed by the Management did not show that there is any separate classification of uniforms or whether there was any difference in the quality of uniforms supplied to Grade I and II drivers. In the counter also it is mentioned that both Grade I and II Drivers are supplied with uniforms. In the evidence of W.W.1 and W.W.2 as well as M.W.1 it is admitted that uniforms and caps are given to all drivers irrespective of their grades and it is also conceded that the Ore Handling Complex employer including drivers therein are given safety shoes. How the Grade II drivers remaining are deprived of the shoes which are provided to Grade I drivers on the ground that firstly the working conditions of these drivers vary depending upon the type of vehicles and the place where the vehicle has to be operated, secondly Grade I drivers are posted to Staff Cars, Mini-buses, Vans and ambulance and thus they come in contact with public, thirdly to maintain the image of the Management in the eyes of public and distinguished guests and fourthly they maintain full up-keep and decorum for physical appearance. It is the case of the Management that on these grounds the Grade II drivers who drive the other vehicles are not entitled for shoes in the Motor Vehicle Section. The entire dispute relates to about 18 Grade I drivers who are supplied with shoes and about 73 Grade II drivers who are not supplied with said shoes.

15. It is to be borne in mind that either in the Claims Statement or in the reference or in their demands under Ex. W1 the workers were not questioning the maintenance of separate scales of pay for Grades of drivers in the Motor Vehicle Section. For being promoted as Grade I drivers one has to pass the Trade Test and must be senior Grade II drivers. There is a certain percentage of promotion from Grade II to Grade I drivers. The scales of pay are different.

16. The case of the Management is that there is no justification for supplying the shoes for the drivers of Grade II in the Motor Vehicle Section as per the four reasons mentioned. The Claims Statement as well as the evidence of WW 1 and WW 2 and then evidence of MW 1 would reveal that these four reasons mentioned by the Management have no substance and they do not stand to reason. The Management contend that the working conditions of these *drivers vary on the ground that they work in different types* of vehicles and the places where the vehicles operate. These cannot be any dispute or questioning the right of Management for preferring Grade I drivers as a matter of policy to work on staff cars, ambulance, Mini-buses and vans but

to say that the working conditions regarding the operation of the vehicles very simply because one drives the staff car and another drives jeep or a lorry or hevy vehicle or Mini-bus and ambulance seems to be not having any nexus to the driving aspect as a technical skill with reference to the working conditions. It is not as if the ambulance and Mini buses and the lorries and jeeps vary in the gear system or mechanical system. There is no such evidence at all. Even for the driving of staff cars it is not contended by any legal evidence to say that the driving conditions which are operative for moving the vehicles are different. On a careful consideration of the mechanism of driving the vehicles, I have no hesitation to reject the contention of the Management that there are separate skills or separate working condition of operation for those drivers who are on staff cars, ambulance, mini-buses and vans on one side and those who drive the lorries, jeeps, trekkers, tractors, and road-rollers. Actually the mini buses, ambulances, vans and the lorries jeeps, Trekkers, Tractors are all light heavy vehicles having the similar gear system and operative methods. The staff cars are light vehicles they do not have any separate operational mechanism. Even the staff cars which are meant for better comfort do not have any separate operational mechanism so as to say that the working conditions of mechanism are different. It is said that the vehicles driven by Grade I drivers are meant to maintain the image of the Management in the eyes of public and distinguished V.I.Ps. If the Management thinks that their image in the eyes of the public can be improved only by providing Grade I drivers with shoes so as to distinguish them from Grade I drivers especially when both types of drivers are provided with same uniform and caps. It looks pedentic that the Management is of opinion that public and distinguished guests are more particular to see the shoes of the drivers than the vehicle in which they were driving with devoted workers. After all it is not correct to say that the distinguished visitors or V.I.Ps. who come to see the Port Trust Management as their guests will only sit in the office where the Management sits and they do not go to the work-spot to see what is happening. There is no such evidence even to show that the V.I.Ps only sit in the Management Headquarters office and they did not go to the work spot where the iron ore is handled and other places of Ore Handling Complex etc. So to classify and distinguish the drivers who are driving the staff cars ambulance and mini-buses from those drivers who are driving other vehicles on the pretext to maintain the image of the Management in the eyes of public and distinguished guests seems to be not tenable.

17. The Management in fact mentioned that all the Grade I drivers are provided with uniforms as well as foot wear i.e. shoes to avoid soiling and to maintain full up-keep and decorum in physical appearance. Then this is required for Grade II drivers also. It is beyond fair and reasonable and legal comprehension to think that the Grade II drivers who are also provided with uniforms in the Motor Vehicle Section should not maintain their full up-keep and decorum in physical appearance. It is interesting to note incidentally that Grade II drivers are provided with safey shoes while they are working in Ore Handling Complex. When this is looked from the evidence of W.W. 1 and W.W. 2 that these shoes provided to the Grade I drivers cannot be treated as ornamental but they are required for safety and protection and when there is evidence from W.W. 1 and W.W. 2 that beat will be generated from the engine and that they require protection of the legs and also there is grip over the brakes, accilator and gear when shoes are used and when the same is not rebutted by any legal evidence, having been satisfied that all these vehicles have got same working operative conditions and when the full up-keep and decorum in physical appearance require shoes for Grade I drivers and when it is asserted that it is required for avoiding soiling for them, much more so that the Grade II drivers also require the shoes when they are provided with uniforms and caps along with Grade I drivers for their up-keep and also to avoid soiling their vehicles and maintain their physical fitness as the same is required for protection and safety. It cannot be accepted that shoes are provided to Grade I drivers as ornamental.

18. The arguments of the Management is that the salary differs and the nature of work differs and the vehicles they are driving are different and thus there is a specific classification and that such discrimination between the Grade I drivers and Grade II drivers maintainable is not correct. Gradation of senior skilled drivers and junior skilled drivers on the basis of Trade test and seniority is not in dispute. But to say the nature of work differs on the basis of the centres and the vehicles which they drive seems to be palpably incorrect. There is no evidence to show how the work differs either operational or from the point of safety of the person who are being carried; anybody who is in the vehicle sitting in the vehicle must be carried safely. Simply if one is V.I.P.; it cannot be said that the said driving requires safely driving. Either poor or rich whether he is V.I.P. or ordinary worker who is in the employment must be safely taken. It is not the case of the Management that Grade II drivers are unskilled drivers. Moreover the vehicles names are different but conditions and operation-wise requirements do not differ. The other aspects that Grade I drivers in some centres while the other Grade II drivers work in the work-spot is only a matter of policy. Suppose an accident takes place at the work-spot are not the ambulance/vehicles going to the work-spot to carry the injured or sick whoever it is? The mini-buses and the vans and the jeeps, lorries, road rollers and other trekkers have same conditions of operation. Therefore I am not able to agree that such a discrimination for the sake of shoes alone is maintainable between the Grade I and Grade II drivers.

19. The next argument that shoes are not part of Uniform and that the shops are entirely distinct and different item or perquisite and if the same is allowed other workers will also demand shoes, is preposterous. Grade I drivers are provided with uniforms and caps similarly Grade II drivers are provided with uniforms and caps and there is no rule or circular that Grade I drivers alone should be provided with shoes on the ground that they should meet the V.I.Ps. or on the ground that they are on a higher category. M.W. 1 who is examined for the Management is not a man experience in driving. He conceded that there would be heat in the engine of the motor vehicles and he also conceded that Grade II drivers are provided with uniforms and caps in order to avoid soiling of clothes and he could not say whether there is any difference in quality of uniforms supplied to Grade I and Grade II drivers. Therefore to say that the nature of work of Grade II drivers did not warrant wearing the shoes seems to be having no legal basis. It is a clear discrimination. The interchangeability of drivers amongst themselves i.e. drivers of Grade I within Grade I and drivers of Grade II within Grade II amongst themselves and not vice versa, is only a matter of posting with reference to the work adjustment. But when there is no circular for providing shoes to Grade I drivers alone to say that shoes are not part of the uniform is a discrimination especially when there is a clear evidence that the shoes are required for safety and protection and that shoes are provided to all either saefty shoes or leather shoes except the Grade II drivers who are not working at Ore Handling Complex. It is the admitted case of the Management that the drivers who are at Ore Handling Complex are provided wih safety shoes. So only those Grade II drivers among these 73 drivers who are not at the Ore Handling Complex are tried to be discriminated without leather shoes or safety shoes on the basis that they do not require the up-keep and decorum of the physical appearance of the drivers. I am unable to accept the same to be reasonable discrimination or fair and justifiable.

20. Moreover it is not the case of the Management that the financial position of the employer cannot bear with the burden involved in the said perquisite with reference to Grade II drivers of the Motor Vehicle Section.

21. Miss G. Sudha relied upon Burmah-Shell etc.. Oil Cos v. Their workmen & ors. [1961 (II) LLJ, Page 124] contended that the order of reference must be construed with reference to the refusal to supply shoes to Grade II drivers of Motor Vehicle Section and the same should not be extended to any other claim of Grade II drivers of Motor

vehicle Section beyond the scope of the reference. In other words in the prayer part of the claim petition they requested to pass an award directing the Management to provide shoes to Grade II drivers of Ore Handling Complex with two pairs per year when they are posted on heavy vehicles and one pair when they are posted on light vehicles. So it is pointed out that any claim of Grade II drivers of Ore Handling Complex in this case is beyond the context of reference and outside the scope of enquiry. Firstly the citation has no relevance. It was a case with reference to the two categories of workmen of two unions in respect of service conditions of clerical staff and the operatives. In the instant case the Grade II drivers of Ore Handling Complex are already provided with safety shoes. This reference is about refusal of supply of shoes of the entire Grade II drivers of Motor Vehicle Section which includes evidently Ore Handling Complex drivers of Grade II also. There is no specific evidence before me from the Management that Grade II drivers are of two kinds and one of them is only working in Ore Handling Complex and the other section of Grade II drivers are working on the lorries, jeeps, trekkers, tractors and road rollers. The reference relates to all Grade II drivers of Motor Vehicle Section to be provided with shoes on par with Grade I drivers or not. The Motor Vehicle Section of the Port Trust Management consists of two types of drivers pursuant to the Wage Revision Committee dated 1-1-1974. Both these Grade I and Grade II drivers are part of Motor Vehicle Section and therefore it is not correct to say that the Ore Handling Complex Grade II drivers are excluded from the purview of the reference. Firstly they are also part and parcel of the Motor Vehicle Section. Motor Vehicle Section consists of two grades of drivers Grade I and Grade II. There is evidence to show that the Grade II drivers are interchangeable amongst themselves even according to M.W. 1. So some times the Grade II drivers of the Motor Vehicle Section who are driving jeeps, trekkers, tractors, lorries and Road rollers will be working in the Ore Handling Complex also and vice versa. When they are working in the Ore Handling Complex they are necessarily provided already with safety shoes. There is no reference with reference to Safety shoes. The reference before this Tribunal is with reference to providing leather shoes or ordinary shoes provided to Grade I drivers should be provided to Grade II drivers of Motor Vehicle Section or not. Therefore this reference applies to all Grade II drivers of Motor Vehicle Section wherever they work irrespective of the work spot. In other words the Ore Handling Complex Grade II drivers also should be provided with leather shoes as any other Grade II drivers of Motor Vehicle Section just as Grade I drivers of Motor Vehicle Section. It is pointed out by Miss Sudha relying upon the decision reported in Singareni Collieries Co. Ltd. v. Salim M. Merchant [1972(1) An. W.R. Page 165] that the award should not go beyond the reference and there should not be any grant of lesser relief by way of cash as an alternative relief when the main relief is not maintainble. In fact I have already held that Grade II drivers are entitled for the main relief of being provided with leather shoes or similar type or same type of shoes as Grade I drivers. Hence the question of granting some amount alternatively did not arise. Hence it has no application. Miss Sudha relied upon the decision in Chiriniri Colliery v. Thtir workmen [1951 (II) LLJ, Page 59] and contended that the supply of uniforms is a privilege of the Management and the same cannot be insisted. It was a case where an incompetent person representing the Management agreed for supply of uniforms and subsequently went back in supplying the uniforms and the same was referred to the Tribunal, and that was a case when there was no referenc in the previous agreement that the Chowkidar should be supplied with Blankets as provided for workers. On the available data thereafter observing that the Management would be responsible enough to provide the clothing and uniforms wherever the work in the colliery is likely to suffer on account of non-supply of uniforms and on the available material therein it was held that it was not a case made out to provide for uniforms to Chowkidar and Peons. But it was not so in this case. In the instant case though Motor Vehicle Section Grade I drivers are provided with shoes they are varying to discriminate Grade II drivers of the same Motor Vehicle Section on unreasonable and unjustifiable grounds. Then Miss Sudha for Management relied on the decision of Express Newspapers (Private) Ltd. v. Union of India (Indian Factories Journal Vol. XIV 1958-59 page 211) and contended that the demand for shoes to Grade II driver, has no relevance to the concept of minimum living wage or basis wage and they cannot seek for a comfort level wage. It is not a case where the said Management is unable to pay to its workmen atleast a bare minimum wage. There is no rule showing that only Grade I drivers should be provided with separate leather shoes and the reasons specified for such discrimination are not based upon the distinction drawn therein. All these drivers Grade I and Grade II belong to the same Motor Vehicle Section and Grade I drivers are not distinct from Grade II drivers for this perquisite by providing leather shoes to Grade I drivers without any rationale with reference to a minimum living wage or basic wage. Hence it has no relevancy. She relied on the decision in The Associated Cement Companies Sevalia Cement Works v. their workmen [1953 (I) LLJ, Page 611] and contended that the Management while granting uniforms to various types of workers and employees like Filters, Turners, Welders, Moulders, etc held that the lorry drivers and loco drivers and motor drivers are not entitled to uniforms. Firstly it was a case where different types of employees were being discussed about the desirability of being given uniforms. It is not a case where Turners, Welders, Moulders etc., are distinct on the basis of Grade I and Grade II for uniforms amongst themselves or that the lrory drivers and Loco-drivers and Motor drivers Grade I were given uniforms while Grade II drivers in the same were refused Uniforms on the basis of grades in same posts. The uniforms were found required with reference to the nature of job and not with reference to the same job because of Grades on the basis of decorum and image of the Management. Hence it has no application. Miss Sudha for Management relied on Kashi Iron Foundry & Others v. Their workmen [1952 (1) LLJ, page 199]. It was a case where the workers demanded in addition to the tight fitting garments provided by the Factory Act they wanted supply of uniforms to all persons working on machines consisting of one shirt and one shirt twice a year. While considering the scope of the provisions of the Factory Act, it was held that there was nothing to show that all the workmen other than those mentioned in the Factory Act have to run the risk and therefore their demand was negatived. In fact if the principles of Factory Act are applied here when there is evidence that these people require shoes for protection and safety it must be held that they should be provided with shoes also along with uniforms. Therefore the said decision has no relevance. Finally Miss Sudha relied on the decision reported in Oriental Motor Co. Ltd., Lucknow v. Their employees [1950 (II) LLJ, page 606] and contended that the workers cannot be allowed to claim uniforms as a matter of right. While following the decisions I have no hesitation to say that the facts therein have no relevance to the present facts. It was a case where uniforms were ordered to be supplied to different types of workers by the Regional Conciliation Board while considering their demands. In that context the following observation was made. It is observed therein as follows :—

> "If of course any employer chooses to dress his workers in uniforms to make them look smarter, he is at liberty to do so, but the workers cannot be allowed to claim uniforms as a matter of right. In the present case the employers were willing to supply uniforms to peons, gatemen night watchmen and sweepers, but did not wish to give any to electricians and cleaners; and in my opinion they were fully entitled to make this discrimination."

It was a case where separte employers of various types were being given uniforms. But it was not a case where among some type of workmen on account of grades some workmen were distinguished in supplying uniforms. If Grade I drivers of the Motor Vehicdle Section with uniforms including shoes should look smarter, then there cannot be any discrimination by not supplying similar shoes to Grade II drivers of the same Motor Vehicle Section, as they are not separate class of employees though they are having grades for the purpose of salary. Therefore this reference is answered holding that the Management of Visakhapatnam Port Trust was not right and refusing to supply the shoes to all Grade II

drivers of Motor Vehicle Section. They are further directed to grant leather shoes or similar shoes to Grade II Drivers of Motor Vehicle Section irrespective of the place of work as provided to Grade I drivers of Motor Vehicles Section.

Dictated to the Stenographer, transcribed by him, corrected by me and given under my hand and the seal of this Tribunal, this the 3rd December, 1984.

Sd/- Illegible

Industrial Tribunal

APPENDIX OF EVIDENCE

Witnesses examined for the workmen

W.W.1—A. Rahman

W.W.2—B. M. Jaidev.

Witnesses examined for the Management

M.W.1—Y. Bhadrachalam.

Documents marked for the Workmen

Ex. W1...Letter No. 16/10/1982—ALC dated 31-5-82 addressed by Assistant Commissioner (C) Visakhapatnam, to the Secretary to the Government of India, Ministry of Labour, New Delhi, regarding the failure of conciliation report.

Documents marked for the Management

Ex. M1—Order No. A/1500/76 dated 12-2-82, regarding the sanction for the Safety Shoes to the staff of O.H.C.

J. VENUGOPALA RAO, Industrial Tribunal

[No. L-34011/10/82-/D.IV(A)]

New Delhi, the 27th December, 1984

S.O. 93.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal, Calcutta in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Calcutta Port Trust, Calcutta and their workmen, which was received by the Central Government on the 11th December, 1984.

CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL, CALCUTTA

Reference No. 5 of 1980

PARTIES:

Employers in relation to the management of Calcutta Port Trust, Calcutta.

AND

Their Workman.

PRESENT:

Mr. Justice M. P. Singh, Presiding Officer.

APPEARANCES:

On behalf of Management—Mr. D. K. Mukherjee, Industrial Relation Officer.

On behalf of Calcutta Port Shramik Union—Mr. D. L. Sengupta, Vice President with Mr. Paresh Bose, Assistant Secretary.

On behalf of National Union of Waterfront Workers (I)—Mr. Satyan Das, Secretary.

STATE: West Bengal. INDUSTRY: Port & Dock.

AWARD

By Order No. L 32012/8/79-D.IV(A) dated 10th January 1980 the Government of India, in the Ministry of Labour & Rehabilitation (Department of Labour) referred the following dispute to this Tribunal for adjudication :

"Whether the management in relation to Calcutta Port Trust, Calcutta are justified in altering the seniority of Shri Ram Ranjan Chatterjee, Dock Tindal (Actg) and allowing Sarvashri Satya Bhushan Chakraborty and Dilip Kumar Dhar, Lascars, to supersede him? If not, to what relief is the concerned workman entitled?"

2. Before I enter into the facts of the case I would like to mention that this Tribunal passed an award in this very case on 7th August 1982 but the same was set aside by the hon'ble High Court Calcutta in writ jurisdiction by order dated 18-7-1983 on the ground that the National Union of Waterfront Workers also should be heard. That union was not a party to the reference but in view of the order of the hon'ble High Court Calcutta it was made a party to the reference and has been heard. It has taken up the cause of Mr. Satya Bhusan Chakraborty.

3. The short facts are these : Mr. Ram Ranjan Chatterjee joined as second class lascar under the earstwhile Port Commissioners of Calcutta on 18th January 1957 in the pilot service in PV Bengal on temporary basis in leave vacancy, he continued upto 11-6-1957. Thereafter he was appointed in PV Hooghly on 1 January 1958 as second class lascar. He was confirmed on that post after a year i.e. on 1-1-1959. Afterwards he was promoted to the post of first class lascar on 9th June 1958 against a temporary vacancy and was later absorved on permanent basis. The other two employees namely, Mr. Satya Bhusan Chakraborty and Mr. Dilip Kumar Dhar were appointed as second class lascar on 1 Dec., 1957 in the pilot vessel Hooghly (now Samudra from 22 September 1964). They were confirmed on that post on 1 December 1958. Thus these two employees were appointed one month earlier than Mr. Ram Ranjan Chatterjee on the pilot vessel Hooghly and were also confirmed earlier. However, the management treated Sri Chatterjee as senior to these two employees and name of Mr. Ram Ranjan Chatterjee was shown as senior in the seniority list (Ext W-1). Mr. Chatterjee was posted as a Deck Tindal from 3rd October 1974 to 31 October 1974 and again from 3rd December 1974 to 13th December 1974. It seems that his officiating pay was withheld and so he made representations for it. After some correspondence the harbour master again posted him as acting tindal for one year with effect from 8th March 1977. The other two employees Mr. Chakraborty and Mr. Dhar were also allowed to officiate during leave vacancy in the post of dock tindal from 16th May 1977 and 18th April 1979 respectively.

4. I may mention here that the dispute regarding seniority of Mr. Chatterjee arose as early as in the year 1974: vide Exts M-1, M1 and M-2 but unfortunately it has not yet been finally settled though 10 years have passed. It appears that after about 5 years of the raising of the dispute the management decided in the year 1979 that Mr. Chatterjee was junior to the other two employees, namely Mr. Satya Bhushan Chakraborty and Mr. Dilip Kr. Dhar (vide Ext M-9 dated 9-1-1979). This led to the present dispute.

5. have already said that the management had treated him as senior to Mr. Chakraborty and Mr. Dhar as it so appears from the seniority list (Ext W-1). It so appears from the further fact that he was given officiating post as Deck Tindal from time to time. Even the present reference proceeds on the basis that he was senior to the other two employees and the issue is to whether the alteration of his seniority is justified. Unfortunately the order of the deputy chairman dated 29-12-1978 by which the seniority of Ram Ranjan Chatterjee was altered and he was declared to be junior to the other two employees has not been filed by any of the parties, the management should have filed it. This Tribunal therefore is not in a position to know the exact reasons on the basis of which the seniority of Ram Ranjan Chatterjee was altered. Ext M-9 dated 9-1-1979 and M-13 are merely office memos through which the alteration of seniority was communicated to Sri Chatterjee.

6. Mr. Satyan Das secretary of the National Union of Waterfront Workers supporting the case of Mr. S.B. Chakraborty vehemently contended that Sri Chakraborty was senior to Ram Ranjan Chatterjee because Mr. Satya Bhusan Chakraborty was appointed as second class lascar on 1-12-1957 whereas Mr. Chatterje was appointed as second class lascar on 1-1-1958 on P. V. Hooghly. He also urged that total length of service should be counted in the sense of continuity of service and that the earlier period of about six months service as second class lascar of Mr. Chatterjee (18-1-57 to 11-6-57) cannot be considered in counting the total length of service. He argued that seniority is counted vesselwise and in the present case seniority ought to be determined in respect of the vessel

Hooghly. He referred to Das Gupta Award in reference No. 1 of 1956 in which it was held that seniority is to be determined unit-wise. Sri Satyan Das also contended that the present dispute relates to inter se seniority of the three employees in the Pilot Vessel Samudra and as such seniority is to be determined in the light of the total length of service in that vessel and hence Mr. Chatterjee was rightly made juniormost of the three in the grade of lascar in the Pilot Vessel Samudra by the secretary under his letter dated 29th December, 1978. In my opinion even if Sri Satyan Das be correct, the fact appears to be otherwise. It seems to me that the management treated Mr. Ram Ranjan Chatterjee as senior to the other two employees otherwise Mr. Chatterjee would not have been shown senior in the seniority list (Ext. W-1) which was prepared in August 1958 seen after the seniority have been framed. The said seniority list (Ext. W-1) has not yet been quashed either by the management or by any Tribunal or by any Court. In that seniority list, Mr. Ram Ranjan Chatterjee is No. 32, Mr. Satya Bhusan Chakraborty is No. 33 and Mr. Dilip Kr. Dhar is No. 34. The position therefore is that Ram Ranjan Chatterjee has been treated and considered to be senior for about 20 or 21 years. His seniority was altered only in about the year 1978. In such a situation it will not at all be proper and just to nullify his seniority. Another thing to be noted in this connection is that the reference itself proceeds on the basis that Sri Ram Ranjan Chatteerjee was senior to the other two employees and that his seniority was altered by the management. Sri Satyan Das therefore cannot be permitted to argue that Mr. Ram Ranjan Chatterjee was not senior. That would be enlarging the scope of the reference. As per terms of the reference this Tribunal is only to see whether alteration of the seniority is justified. Mr. D. K. Mukherjee for the management has taken a nutral attitude and he has said that he will abide by the decision of this Tribunal and that the management is not interested in any particular candidate. Sri Satyan Das vigorously argued that Mr. Satya Bhusan Chakraborty was appointed in the Pilot Vessel Hooghly (now Samudra) a month earlier to the appointment of Mr. Ram Ranjan Chatterjee. I have already said that Mr. Chakraborty was appointed on 1-12-1957 as second class lascar whereas Mr. Chatterjee was appointed on 1-1-1958 as second class lascar on that vessel but there are further facts also to be considered. Mr. Ram Ranjan Chatterjee was made a first class lascar on P. V. Hooghly on 9th June, 1958. He also officiated on several occasions in the post of Desk Tindal The first pilot vessel namely P. V. Bengal was condemned and all categories of employees of vessel were transferred to P. V. Sagar along with seniority as admitted by Mr. Satya Bhusa nChakraborty (WW-1). In view of all these facts I think Das Gupta Award in reference No. 1 of 1956 will not apply to this case. It is needless to repeat here again that the question is not as to who is senior and as to how the seniority is to be determined but the question is whether the alteration of seniority is justified. On the evidence on record I do not find any good reason for altering the seniority of Mr. Ram Ranjan Chatterjee, clearly therefore alteration of seniority is not justified.

7. In the result, my award is that the action of the management of Calcutta Port Trust is unjustified in altering the seniority of Mr. Ram Ranjan Chatterjee. Deck Tindal (actg.) and in allowing Mr. Satya Bhusan Chakraborty and Mr. Dilip Kumar Dhar to supersede him. The result will be that Mr. Ram Ranjan Chatterjee will remain senior to the other two employees i.e., Satya Bhusan Chakraborty and Dilip Kumar Dhar and his seniority will be maintained for purposes of future promotions or any other purpose. It follows that the two concerned workmen, namely, Mr. Satya Bhusan Chakraborty and Sri Dilip Kumar Dhar are not entitled to any relief.

Dated, Calcutta,

The 26th November, 1984.

M. P. SINGH, Presiding Officer

[No. L-32012/8/79-D.IV(A)]

S.O. 94.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal, Chandigarh in the industrial dispute between the employers in relation to the management of United India Fire & General Insurance Company Limited New Delhi and their workman, which was received by the Central Government on the 15th December, 1984.

BEFORE SHRI I.P. VASISHTH, PRESIDING OFFICER, CENTRAL GOVERNMENT, INDUSTRIAL TRIBUNAL CHANDIGARH

Case No. I.D. 56 of 1979 (N. Delhi), 130 of 1983 CHD

PARTIES :

Employers in relation to the United India Fire & General Insurance Company.

AND

Their workman : Shri M. R. Narula

APPEARANCES :

For the Employer—Sh. P. P. Malhotra

For the workman—Sh. J. C. Verma

Activity : Insurance State : Punjab

AWARD

Dated the 12th of December, 1984

The Central Govt., Ministry of Labour, in exercise of the powers conferred on them under Section 10(1)(d) of the Industrial Disputes Act, 1947, hereinafter referred to as the Act, per their Order No. L-17012(11)/79-D.IV(A) dated the 24th September, 1979 read with S.O. No. S-11025(2)/83 dated the 8th of June, 1983 referred the following industrial dispute to this Tribunal for adjudication :—

"Whether the action of the management of United India Fire and General Insurance Company Limited (now known as United India Insurance Company Limited), New Delhi in terminating the services of Shri M. R. Narula, Assistant/Typist with effect from the 25th October, 1976, is justified? If not, to what relief is the concerned workman entitled?"

2. Brief facts of the case, according to the petitioner/workman, are that he served the Respdt. Company as an Assistant/Typist on the following occasions in temporary capacity.

S.No.	Appointment order	Period From	Period To	Duration
(i)	NDM-PAS/Per-75-2780 dt. 5-11-1975	29-10-75	27-12-75	60 days
(ii)	NDM/PAS/76-Per dt. 5-1-76	7-1-76	6-3-76	60 days
(iii)	NDM/PAS/76-438 dt. 12-3-76	12-3-76	10-4-76	30 days
(iv)	NDM/PAS/76-Per-700 dt. 13-4-76	15-4-76	28-4-76	14 days

3. On 10-5-76 the petitioner again joined a tenure service for 60 days per letter No. NDM/PAS/76/Per/841 dated 8-5-76 issued by the Divisional Office, Chandigarh of the Respondent Company. However, in the meanwhile the Company's Head Office vide their letter No. HO/Per/APT/N/44-76 dated 28-5-76 placed him on probation for a period of six months. But before he could complete the probationary period, his services were terminated under Order dated 20-10-76 served on him on 25-10-76 even though there had been no left up in his work or conduct. The petitioner agitated against his termination and placarde that being violative of the beneficiary provisions of Section 25-F, G and 25-H of the Act, it was void ab initio. He avered that no terminal benefits were given to him and that a number of his juniors were retained in service, whereas some fresh hands were also recruited even after his disengagement without affording him any opportunity of re-employment.

4. Since the Management was found unresponsive to his demand, therefore, the petitioner raised an industrial dispute which however defied an amicable settlement despite the intervention of the Conciliation Officer, and hence the Reference.

5. Resisting the proceedings, the Management questioned the propriety of the Reference on the plea that the petitioner was not such an employee who could qualify as a 'workman'

under the Act; because his engagement had through out been on temporary and short term assignments.

6. On facts, the petitioner's claim of having put in the above noted length of service was conceded and it was not denied that no terminal benefits were given to him. But according to them he was not eligible for recruitment because even at the time of his initial appointment, which itself was obtained in league with the Local Officers, he was overage; and as and when it came to their notice; they terminated his services during the probationary period.

7. Keeping in view the comprehensive nature of the Reference, my learned predecessor called upon the parties to adduce evidence in support of their respective pleadings which appeared to be fully covered by its terms. Thus the petitioner examined himself whereas the Management produced their present Divisional Manager Sh. C. L. Narula, of course both the parties filed a number of documents also whose authenticity was not contested by either of them.

8. I have carefully gone through the entire available data and heard the parties. Drawing my attention towards clause 14 of the Recruitment rules contained in the circular Exb. M2 the learned counsel for the Respondent Company focussed on the petitioner's admission during his cross examination that he was more than 26 years of age at the time of his initial recruitment and that in his case no relaxation order was ever passed by the Company or any of its Authorised Representative. It was further submitted that on his own showing the petitioner was related to the Assistant to then Branch Manager Sh. C. B. Lal who had arranged his temporary assignment for 60 days on a simple application per order Exb. P1 in November, 1975 even though he was not sponsored by any Employment Exchange and there was no formal advertisement of the post. I was also referred to some other admissions made by the petitioner to the effect that he was given such temporary assignments by the same vary Divisional Manager without observing the Recruitment rules on any occasion.

9. Elaborating his point, the Ld. counsel contended that actually the petitioner was in league with their Divisional Manager who kept the Head Office in the dark about his eligibility to join service and that when he was placed on probation, (during his last temporary assignment in the month of may, 1976) the Head Office had accorded him the benefit, in pursuance of a Policy decision to absorb all the temporary employees in the Regular cadre, on the assumption that he was otherwise an eligible candidate. It was argued that since the very foundation of the petitioner's service originated in deceipt and fraud, therefore, he was not entitled to seek any relief from this Tribunal.

10. Despite its seeming attraction the submission failed to carry conviction with me. The pertinent point is that it is based on the assumption that there was any misrepresentation or concealment of facts by the petitioner; whereas it is not so. During his cross-examination the present Divisional Manager MWI Sh. C. L. Narula admitted that in his very first application for employment submitted to their Divisional Manager, through the Branch Manager, the petitioner had disclosed that he was 39 years of age at that time and that he had mentioned this fact in every subsequent application also. From his statement it further appears that the appointmants were given by the Divisional Manager and not by Branch Manager Sh. C. B. Lal on his own. This fact is further borne out from the relevant appointment orders Exb. P1 to P5. It, therefore, rules out the possibility of any foul play by the petitioner in seeking employment.

11. It is besides the point that if at all the Management had any reservation in the manner of giving employment to the petitioner on by-passing the normal channel of Employment Exchange, they could have pulled up their concerned officers i.e. the Branch Manager or the Divisional Manager, but no such step was taken, they accepted their recommendations and issued him formal appointment order dated 28-5-76 per Exb.p6 for his absorption in the regular cadre and meanwhile placed him on probation for six months. It was in pursuance to this arrangement that the petitioner was required to go through the drill of medical examination where once again he reiterated his correct age.

12 On behalf of the Management it was explained that there was an inadvertent clerical lapse in their office and perhaps, things might have gone un-noticed had there been no complaint by an outsider against the petitioner's employment; however in the ensuing enquiry they detected the truth and that was how that the petitioner was disengaged before completion of his probation.

13. I am not impressed with the Management's effort to wriggle out of the situation because the petitioner's does not appear to be the solitary instance of such recruitments. From the cross-examination of the present Divisional Manager Sh. C. L. Narula and the service record of one Gurdian Chander Sharma produced by him, on the asking of the petitioner, it appears that the said Sh. Sharma was also overage at the time of recruitment and has been allowed to continue in service even up-to-date without feeling the necessity of passing any order of exemption.

14. To me it appears that for some or the other reason there was some laxity in the matter of management and that was how that even overage persons were being freely appointed and retained in service; the exact reason for the impugned termination may be shrouded in mystery but it would be going too far to dump all the blame solely on the petitioner's door particularly when he never concealed the truth and the Management did not even like to initiate any domestic enquiry before passing the order of termination.

15. It goes without saying that no terminal benefits were accorded to the petitioner even though his total length of service had exceeded 240 days in 12 calendar months as per admitted case of the parties. The Management's contention that since he was always a temporary hand, serving on different occasions, and therefore, he was not a "Workman" within the ambit of the Act deserves summary rejection in view of the wide and comprehensive nature of the definition clause contained in Section 2(s). For my views I draw support from the ratio of Pilot Pen Company Madras (Pvt. Ltd.) Vs. Presiding Officer Additional Labour Court 1971 (1) LL.J 241 and Crompton Engineering Comp (Madras) Pvt. Ltd. Vs. Additional Labour Court Madras 1975 (1) L.L.J. 207.

16. In the light of what has been stated above, I return my Award, against the Management with the finding that their impugned action in terminating the petitioner's services had no justification in the eye of law. Accordingly he would be re-instated and allowed to continue in his post with all the attendant benefits except for the back-wages, which shall be restricted to 50 per cent of the dues in view of the intricate nature of the dispute.

Dated : 12-12-1984.

I. P. VASISHTH, Presiding Officer

Chandigarh

[No. L-17012/11/79-D.IV(A)]

New Delhi, the 28th December, 1984

S.O. 95.—In pursuance of section 17 of Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal, Hyderabad in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Food Corporation of India, Nizamabad and their workman, which was received by the Central Government on the 20th December, 1984.

BEFORE THE INDUSTRIAL TRIBUNAL (CENTRAL)

AT HYDERABAD

Industrial Dispute No. 24 of 1983

BETWEEN

Workmen of Food Corporation of India, Nizamabad.

AND

The Management of Food Corporation of India, Nizamabad.

APPEARANCES :

Sri G. Bikshapathi and Sri V. Ravinder, Advocates for the Workmen.

Sri M. V. Bharathi, Advocate for the Management.

AWARD

Under Sections 7A and 10(1)(d) of the Industrial Disputes Act, 1947 the Government of India, Ministry of Labour, New Delhi referred to this Tribunal the following dispute between the Workmen and the Management of Food Corporation of India, Nizamabad (A.P.) by its Letter No. L-42012(60)/82-D.II.B/IV.B, dated 15-10-1983 :

SCHEDULE

"Whether the management of Food Corporation of India, Nizamabad is justified in terminating the services of Shri Shaik Habeeb, Ex. Watchman, FCI, Nizamabad w.e.f. 1-10-1981? If not to what relief the workman is entitled to:"

2. This reference was registered as Industrial Dispute No. 24 of 1983 and notices were issued to both parties.

3. It is mentioned in the claims statement that he (Shaik Habeeb) was appointed as Casual Labour under Category IV at Sarangapur of the respondent-establishment with effect from 6-2-1975. According to him he was transferred to District Office, Nizamabad from 15-4-1976 and posted to work as Watchman. It is his case that all the personnel in the Food Corporation of India were intially appointed on daily rated basis. He further mentioned that the Food Corporation of India issued a Circular dated 20-12-1977 by which all the employees who were appointed on daily rate basis were given regular scales with retrospective effect from 8-1-1976 and the petitioner has been working as Watchman ever since he was transferred to Nizamabad. While so, it is his case that the Respondent passed an order on 21-2-1977 terminating his service with effect from 28-2-1977. According to him, aggrieved by the same, he approached the Conciliation machinery and then this Tribunal by filing I.D. No. 15 of 1980 and the Tribunal was pleased to hold the order is said to be illegal and violative and he was also reinstated into service with effect from 29-5-82 and he was paid back wages from 28-2-1977 to 28-5-1981. Therefore it is his case that his services were deemed to be continuous with effect from 6-2-1975. He was entitled to regular scales of pay but still he was given only daily rate of Rs. 6.00 per day. According to him while all other employees who were Watchman were given regular scales. He is the only man discriminated by paying daily rate wages. It is also his case that there was settlement entered upon by the Respondent Management with the petitioner workman herein agreeing to appoint him as Watchman in the scale of Rs. 210—290 and the same was not honoured. According to him while the matters stood thus the Petitioner was not allowed to join duty from 1-10-1981 without any reason and no order was issued to the Petitioner terminating the services. According to him during the conciliation proceedings, the Management tried to contend that they terminated for want of vacancy which is absolutely illegal and unlawful. He maintained that the same is contrary to Section 25(f) and (g) of the Industrial Disputes Act. He also mentioned that there was no misconduct alleged and no enquiry was conducted against the Petitioner. According to him the Petitioner hardly worked for three months for the second time and thus the Management has acted in a negative nature by exercising its power and it amounts to victimisation and unfair labour practice. He mentioned that he is un-employed ever since 1-10-1981 and he could not secure employment.

4. On the other hand, the Management mentioned that the Petitioner was over-aged at the time of appointment on 6-2-1975 by one year, six months eigtheen days and that there is no justification to continue him in service as casual labourer on being found surplus. overage an non-employment exchange candidate for an indefinite period. It is also their case that no industrial dispute arises under Section 25(f). According to them on humanitarian grounds he was put as Watchman and he had no service condition to carry. He maintained that Circular dated 20-12-1977 is irrelevent in so far as his age cannot and was not relaxed at an time. It is factually incorrect that similar persons were regularised in service. It is maintained that all others who were regularised in service fulfilled the requirements of the Circular dated 20-12-1977 It is denied that he is only the employee in the entire Food Corporation of India organisation who was paid daily rate wages, while others were regularised. According to them the Petitioner himself passed on the letter dated 22-9-1980 terminating the earlier settlement dated 29-5-1980. Hence the matter cannot be reagitated.

5. According to them the Respondent has every right to reduce the man power and cut off the dead-wood from time to time and this right is not questionable and justiciable in any court of law or in the proceedings as held by the Supreme Court and other High Court decisions. According to them this office establishment is registered under the Andhra Pradesh Shops Establishments Act and consequently Section 25F cannot be imported into the provisions of Shops and Establishments Act. Therefore the termination is lawfully affected and he had only remedy if any as the said A.P. Shops and Establishments Act. He asserted that the provisions of Section 25F and G of the I.D. Act do not apply in the instant case and it is also denied that there is any colourable exercise of power and also denied the allegation of victimisation.

6. The Petitioner examined himself as W.W.1 mentioned that he was appointed on 6-2-1977 by the District Manager of Food Corporation of India, Nizamabad as a Casual Labour on daily rated basis posted at Sarangapur Modern Rice Mill. According to him he was transferred to Nizamabad as Chowkidar after one year and when he was working there at Nizamabad he was discharged on 28-2-1977 and pursuant to the award passed in I.D. No. 15 of 1980 he was reinstated with back wages. According to him suddenly he was not allowed to come to duty from 1-10-1981. He was not given any order and was not also paid any compensation. It is his case that he was remaining unemployed since the date of removal and prayed for reinstatement with back wages. He admitted that his date of birth is 18-7-1948 and he could not deny that he was overaged by 1-1/2 years. He also conceded that he was not recruited through Employment Exchange. He denied the suggestion that 16 more persons were declared surplus. He denied the suggestion stating that he was not agreeable to Ex. W2 settlement.

7. For the Management M.W.1 who is Assistant Manager of F.C.I. Nizamabad deposed that under Ex. M1 originally the claimant Shaik Habeeb was appointed as per the terms and conditions. He also deposed that Ex.M2 is termination order issued by him. He also filed Ex. M3 as a statement showing the strength of the staff as on 31-12-1983. According to him Item 19 relates to the Watchman post and there were only 73 sanctioned strength of watchmen but there were 100 watchmen. Thus there were 23 surplus watchmen. He also mentioned that two persons covered under Ex.M2 termination order were not sponsored by the Employment Exchange including this petitioner. He mentioned that a man should not exceed 25 years of age for taking into service in the Food Corporation of India and the claimant was more than 25 years when he entered the service and after interviewing the Employment Exchange candidates they selected the required number of candidates. It is his case that the claimant was not selected in that way. According to the sanctioned strength of District Office for Peons is only four and 7th standard pass is the minimum qualification for appointment as Watchman. In the cross examination he conceded that prior to Ex. M1 this petitioner was appointed as casual labour at Modern Rice Mills, Sarangapur. He also conceded that Ex.M2 termination was set aside by the Tribunal and he was granted back wages. Ex. W3 is the order of reinstatement. According to him Ex. W3 is the settlement which is available in the office files Finally he conceded that the second termination was within four months after his reinstatement. M.W.2 is the District Manager. According to him on 1-10-1981 he removed the Petitioner from service. Ex.M4 is the copy of the order. It is his case that the same was sent by registered post acknowledgement due but it was refused returned unserved. Ex.M5 is the refused and returned cover. It is also his case that in the presence of other witnesses the claimant refused to receive the payment offered and refusal was noted by the witnesses and he filed the said paper as Ex.M6. The cover was opened and the original termination order is marked as Ex. M7. The order showed that the termination was done for want of vacancy According to him as the casual labour would not be continued in service for want of vacancy he was terminated. He also mentioned that Ex. M6 is with reference to the payment only and not for termination order. He also mentioned that overage of the workman was one of the causes of termination and he could not say whether his case was referred to the Zonal Office for relaxing the age

8. The point for consideration is whether the Management of Food Corporation of India is justified for terminating the services of Shaik Habeeb from 1-10-1981 and if so to what

relief?

9. The admitted facts are the workman Shaik Habeeb was appointed on 6-2-1975 by the District Manager, F.C.I. Nizamabad and posted to work at Modern Rice Mills, Sarangapur as Casual Labour on daily rate basis. While he was working at Nizamabad as Chowkidar he was discharged on 28-2-1977. He filed Industrial Dispute No. 15 of 1980 and he was directed to be reinstated by this Tribunal with back wages. He was reinstated on 25-5-1981 and the back wages were also paid. The previous award of this Tribunal in I.D. No. 15/80 called from the back-files and it is marked as Ex. C1. In that original termination of Shaik Habeeb with effect from 28-2-1977 by the Food Corporation of India, Nizamabad is held to be not just and legal and he was directed to be reinstated and also paid back wages at the daily rate of Rs. 4.00 till the date of reinstatement from the date of termination. In that award it was held that Section 25F of the I.D. Act is applicable even with regard to the temporary employee and the order of termination is treated as void as he was not given retrenchment compensation even though he worked for more than 240 days in a calendar year prior to 28-2-1977. Thus he was ordered to be reinstated with back wages. That is the sum and substance of the award passed in I.D. No. 15 of 1980. Now it is admitted that he was reinstated into service by an order dated 25-5-1981 by to District Manager and he was paid also back wages.

10. It is now found that he was again terminated by virtue of the order Ex. M7 dt 31-1-1981 from 1-10-1981 giving one month's notice in advance. The refused cover is marked as Ex. M5. Ex. M4 is the copy of the order marked. Ex. M7 is the original order which was marked by opening the cover in the Tribunal. The order disclosed that the termination would come into effect from 1-10-1981 for want of vacancy, and that he was ordered to be paid compensation also and one month's notice is given as required under Section 25F of the I.D. Act. It is further found that he was age barred by 1-1/2 years. He admitted that his date of birth is 18-7-1948. According to M.W.1 and M.W.2 that the maximum required age for being considered for appointment into service was one should not complete 25 years of age. The admission of M.W.1 that he was appointed on 6-2-1975 as Casual Labour when his date of birth was 18-7-1948 would show that by the time of his entering into service as casual Labour on daily rate basis he was over-aged by about 1-1/2 years. Now under Section 25F of the I.D. Act even under Ex. C1 Award also it was pointing out that he was not given notice as required under Section 25F. He should have been given one month's notice treating him as worker when he completed more than 240 days in a calendar year prior to 28-2-1977 which was the original date of termination. That was held to be illegal in Ex. C1. There was nothing like his appointment being held as regular or legal in Ex. C1.

11. His request under Ex. W1 dated 30-11-1981 subsequent to the second termination order stating that he was not paid one month's salary from September, 1981 and that he was terminated without complying with the provisions of Section 25F seems to be not correct. Ex. M5 is the registered letter with acknowledgement due returned from the sender on the ground that the same was refused. It is not the case of the said employee that the address given on the registered cover was not correctly mentioned. It is no where suggested to that effect. Ex. M2 was the original order of termination which was set aside in I.D. No. 15 of 1980 Ex. M4, M7 and M5 pertain to the present termination order which was refused. Ex. W1 is the representation and Ex. W2 is a Memorandum of Settlement arrived at between Shaik Habeeb and Management. and it is filed by the workmen himself. It was a Settlement to show that the appointment will be treated as fresh appointment the day he joins duty. Ex. W3 is the sanction order for reinstatement paying all the back wages. So Ex. W1, W2 and W3 only show that the previous award as passed by this Tribunal was complied with. Now Ex. M4 and M7 would show that his services were terminated for want of vacancy complying Sec. 25F.

12. The counsel for the Petitioner contended that the so-called over-age which is a point raised as an argument is not mentioned in the termination orders Ex. M7 and M5. According to him it is mentioned that the termination is for want of vacancy. Sri Bikshapathi contended that when the said so-called over-age is not a ground in the earlier industrial dispute and when he is working in the said Corporation in some capacity or other since 1975, the Management has got obligation to relax the Rules with reference to age and the settlement which was done under Ex. W2 though referred to the earlier industrial dispute would indicate that he was appointed knowing the said age and requirements and thus they cannot blow hot and cold being a statutory Corporation. Therefore the settlement condition for regular employee should be implemented. On the other hand Sri Bharathi for the Management contended that Ex. M3 was filed through M.W.1 and there is no cross examination with reference to Ex. M3 statement. It showed that there were 27 surplus watchmen in excess of the staff pattern. According to him under Section 25(g) the principle is that the person who first come will go last is not relevant here and the termination is to come into effect from 1-10-1981 and it must be seen whether Section 25F is complied with or not. According to him Section 25F was complied fully and therefore he should have no grievance. He asserted that the petitioner is only a workman on daily rate basis and he can be a watchman in the Mill or in the office. Even under I.D. No. 15 of 1980 the noncompliance of Section 25F of the I.D. Act was pointed out and the same was complied with and now he is found over-aged and he cannot be regularised against rules. According to him when there is no right for employment for over-aged man, the question of complying Section 25(G) of the I.D. Act. did not arise.

13. Thus having regard to these two arguments when there is nothing in Ex. C1 (previous Award) that he should be taken in and regularised in service and when the rules also show that one should not cross 25 years age; when Ex. W3 showed that there are 27 excess and surplus staff working beyond the staff pattern (it was not disputed), the question of reinstatement on a regular basis when there are no vacancy of posts did not arise. He cannot be compared to those who were called through Employment Exchange with a required qualification as per the Rules. If they are to be retrenched, it will give rise to further industrial disputes if regular eligible men are removed to keep a man who is found to be surplus who is overaged. In workmen of Subong Tea Estate (1954 I.F.L.R. page 91). It is laid down that it is for the Management to decide the strength of its labour force or the number of workmen required to carry out efficiently the work involved in the industry and it must be left to the discretion of the Management. When occasion arises when the number of employees may exceed the reasonable and legitimate needs of the undertakings and when the workmen become surplus, it would be open for the Management to retrench them and it is held in such case the Management would be justified in effecting retrenchment in its labour force. The question now is whether the person is retrenched capriciously without any reason at all. In the same citation i.e. Parry & Co. V. P. C. Pal (1964) I FLR page 183 it was held that an employer has the right to reorganise his business in any fashion he likes for the purpose of economy and convenience and nobody has right to question the propriety of such a course. In the instant case as per Ex. M3 they were 27 surplus watchmen and the right to reduce man power and to cut the dead-wood occasionally is not questionable and he was rightly directed to be terminated for want of vacancy as it is found that it is surplus. The previous award of this Tribunal did not come in the way. The evidence of M. Ws. 1 and 2 would show that the claimant refused to receive the payments offered as contemplated under Section 25F Ex. M6 note put up to show that the present Shaik Habeeb who was asked to receive compensation payment for 105 days at Rs 4.00 per day along with his duty period wages for 105 days totalling to Rs. 504.00. had refused to receive the same on 30-9-1981 at 4.45 P.M. and the same was done in the presence of other officials including the Cashier. So even now he can receive the said amount, if it is not already

paid to him or received by him. The right of the Management to terminate the services on account of want of vacancy (when he is also not qualified) having complied with section 25F of the I.D. Act is proper and according to law, simply because he is reinstated as per the Award in I.D. No. 15 of 1980, it cannot be said that he was appointed regularly without complying the required rules. In the crucial documents Exs. M5 and M7 it would show that he was given notice as required to comply the formalities of Section 25F and 25(g) of the I.D. Act has no application to the present facts of the case. The Order of termination is thus proper and refusal to receive the said order with the compensation calculated under Ex. M6 as deposed by M. W. 1 and 2 is believed to be true and correct. Therefore, I hold that the Management was right in terminating the services of Shaik Habeeb with effect from 1-10-1981 and he is entitled to receive those compensation as mentioned in Ex. M6 if it is not already received.

Award is passed accordingly confirming the Management termination order.

Dictated to the Stenographer, transcribed by him and corrected by me and given under my hand and the seal of this Tribunal this the 5th day of December 1984.

Sd/- Illegible

INDUSTRIAL TRIBUNAL

APPENDIX OF EVIDENCE

Witnesses Examined for the Workmen :	W.W.1—Shaik Habeeb.
	M.W.1—Qutubuddin Ahmed.
Witnesses Examined for the Management :	M.W.2—P.B. Shejwal.

Documents marked for the Workman :

Ex. W1—Representation dt. 30-11-81 made by Shaik Habeeb, to the Senior Regional Manager, Food Corporation of India, Hyderabad.

Ex. W2—True copy of the memorandum of Settlement dt. 29-5-80 arrived at between Shaik Habeeb Ex-Watchman, District Office, Nizamabad and the Management of Food Corporation of India, Regional Office, Hyderabad.

Ex. W3—Sanction Order No. A/RLC/79 dt. 19-6-81 issued by the District Manager, Food Corporation of India, Nizamabad to Shaik Habeeb.

Documents marked for the Management :

Ex. M1—True Copy of the Appointment Order dt. 15th/20-4-1976 issued by District Manager, Food Corporation of India, Nizamabad to Shaik Habeeb.

Ex. M2—True Copy of the termination order dt. 21-2-77 issued by the District Manager Food Corporation of India, Nizamabad to Shaik Habeeb.

Ex. M3—Abstract of Staff position as on 31st December, 1983 at Food Corporation of India, District Office Nizamabad.

Ex. M4—True Copy of the Termination Order dt. 31-8-1981 issued by the District Manager, Food Corporation of India District Office-Nizamabad to Shaik Habeeb.

Ex. M5—Refused returned cover No. A/R.L.C./79-80 by Shaik Habeeb.

Ex. M6—Note dt. 30-9-81 put up by S. Veera Swamy, Cashier to the District Manager, Food Corporation of India, Nizamabad.

Ex. M7—Office Order No. A/RLC/79-80 dt. 31-8-81 issued by District Manager, Food Corporation of India, District Office, Nizamabad to Shaik Habeeb, daily rated watchman termination of services with effect from 1-10-81 serving of one Month's notice in advance regarding.

Document marked by Tribunal

Ex. C1—Award of Industrial Tribunal, Andhra Pradesh, Hyderabad dated 19-2-1981.

J. VENUGOPALA RAO, Industrial Tribunal

[No. L-42012(60)/82-D.II(B)/D.V]

K. J. D. PRASAD, Desk Officer

New Delhi, the 26th December, 1984

S.O. 96.—In pursuance of section 17 of the Industrial Dispute Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal No. 2, Dhanbad in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Stewarts and Llyods of India Limited, Contractors of Messrs Indian Oil Corporation Limited, their sub-contractors, Messrs Ranjan Industries, Messrs Project Construction Services, Messrs Kalpana Construction Company, Messrs R. P. Roy, Messrs Aparajita Enterprises at Barauni Refinery Site and their workmen which was received by the Central Government on the 11th December, 1984.

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL (NO. 2) AT DHANBAD.

Reference No. 59 of 1984

In the matter of Industrial Disputes under Section 10(1)(d) of I.D. Act., 1947.

PARTIES : Employers in relation to the management of Stewarts and Lloyds of India Limited, Contractor of Messrs. Indian Oil Corporation Ltd. their sub-contractors, Messrs Indian Oil Corporation Ltd., their sub-contractors Messrs Ranjan Industries, Messrs. Project Construction Services, Messrs. Kalpana Construction Company, Messrs R.P. Roy, Messrs Aparajita Enterprises at Barauni Refinery Site and their workmen.

APPEARANCES:

On behalf of the employers M/s. Stewarts and Lloyds of India Ltd.	Shri S. Raha, Sr. Assistant.
On behalf of the workmen	None.
STATE : Bihar.	INDUSTRY : Oil.

Dhanbad, Dated, the 7th December, 1984

AWARD

The Government of India in the Ministry of Labour & Rehabilitation, in exercise of the powers conferred on them under Section 10(1)(d) of the I.D. Act, 1947 has referred the following dispute to this Tribunal for adjudication under Order No. L-30012/7/84-D.III(B)(ii) dated the 13th Sept., 1984.

THE SCHEDULE

"Whether the action of the management of Messrs. Stewarts and Lloyds of India Limited, Contractor of Messrs Indian Oil Corporation Ltd., Barauni, and their sub-contractors, namely, Messrs Ranjan Industries, Messrs Project Construction Services, Messrs Kalpana Construction Company, Messrs R.P. Roy, Messrs Aparajita Enterprises in retrenching their workmen with effect from 10th July, 1984, mentioned in the Annexure is legal and justified ? If not, to what relief are the workmen concerned entitled ?

ANNEXURE

Names and Particulars of Retrenched Workmen

Sl. No.	Names of Workmen	Designation	Date of joining.	Name of contractor
1	2	3	4	5
	SARVASHRI :			
1.	Kato Singh	Rigger	20-9-83	Messrs. Stewarts and Lloyds of India Limited.
2.	Mukesh Tanti	Rigger	20-9-83	
3.	Yogendra Rai	Rigger	28-9-83	
4.	Raj Kapoor Sharma	Helpar	1-11-83	
5.	Kurshid Alam	Helper	1-11-83	
6.	Shankar Pd. Bera	Helper	1-11-83	
7.	Jayant Chakraborty	Helper	7-11-83	
8.	Anand Mohan Taladhi	Helper	6-12-83	
9.	Shiv Pd. Gupta	Helper	12-12-83	
10.	P.K. Thakur	Helper	26-12-83	
11.	Dinesh Kumar Singh	Helper	16-1-84	
12.	Kapil Deo Sao	Helper	16-1-84	
13.	Badri Tanti	Helper	7-2-84	
14.	Vijay Kumar Mahato	Helper	7-2-84	
15.	Bijoy Singh	Helper	7-2-84	
16.	Md. Naimuddin	Helper	6-2-84	
17.	Md. Mahfuj Alam	Helper	6-2-84	
18.	Md. Sakir Khan.	Helper	25-2-84	
19.	A.K. Jana	Welder	4-5-83	Messrs. Kalpana Construction Company
20.	Chandrachur Singh	Welder	8-6-83	
21.	Md. Alin Hassa	Fitter	1-2-83	
22.	Mahatama Prasad	Fitter	3-3-83	
23.	D. N. Prasad	Fitter	2-4-83	
24.	Rameshwar Shukla	Fitter	4-4-83	
25.	Narayan Choudhary	Grinder	1-1-83	
26.	Srikant Jha	Grinder	12-1-83	
27.	Rambabu Sah	Grinder	2-4-83	
28.	Ram Deo Mahto	Grinder	2-4-83	
29.	Devender Pathak	Grinder	1-1-83	
30.	Ram Bahadur Singh	Rigger	4-4-83	
31.	Suresh Yadav	Rigger	19-4-83	
32.	Md. Akram	Rigger	15-6-83	
33.	R. N. Gupta	Rigger	22-6-83	
34.	Rambharose Singh	Rigger	23-6-83	
35.	Pawan Kumar Singh	Helper	18-4883	
36.	Ramadhar Singh	Helper	25-4-83	
37.	Manorath Singh	Helper	27-4-83	
38.	Ram Ratan Mahto	Khalasi	1-1-83	
39.	Suresh Rai	Khalasi	1-1-83	
40.	Thukeer Aalm Khan	Khalasi	1-1-83	
41.	Sukhdev Pathak	Khalasi	1-2-83	
42.	Kapleswar Singh	Khalasi	1-2-83	
43.	Fulena Tanti	Khalasi	2-3-83	
44.	Ram Ratan Singh	Khalasi	1-3-83	
45.	Mahesh Ram	Khalasi	1-3-83	
46.	Ram Jatan Singh	Khalasi	1-3-83	
47.	Surindra Tanti	Khalasi	2-4-83	
48.	Manik Chandra	Khalasi	1-5-83	
49.	Beena Das	Khalasi	1-3-83	
50.	Ra, Hilash Tanti	Khalasi	15-6-83	
51.	Hari Mahato	Khalasi	20-6-83	
52.	Kamli Rai	Khalasi	21-6-83	
53.	Arjun Sah	Khalasi	2-6-83	
54.	Umesh Ram	Khalasi	21-2-83	
55.	Hari Mahto	Khalasi	1-7-83	

1	2	3	4	5
	SARVASHRI :			
56.	Dashrath Sah	Khalasi	29-8-83	Messrs. Kalpana Construction Company
57.	Arjun Gupta	Khalasi	1-10-83	
58.	Chamru Sah	Khalasi	18-8-83	
59.	Ram Nath	Khalasi	26-8-83	
60.	Ram Nath Rai	Khalasi	29-8-83	
61.	S.N. Tanti	Khalasi	3-10-83	
62.	S. Alam	Helper	8-7-83	
63.	Sia Ram Rai	Helper	26-9-83	
64.	B.D. Rai	Helprer	1-11-83	
65.	Satya Deo Prasad	Helper	25-11-83	
66.	Rameshwar Jha	Helper	8-8-83	
67.	Ram Sharan Rai	Rigger	1-1-84	
68.	Dinesh Rai	Rigger	1-1-84	Messrs. R.P. Roy Contractors
69.	Poshan Rai	Rigger	1-1-84	
70.	R.B. Roy	Rigger	1-1-84	
71.	D.N. Rai	Rigger	1-2-84	
72.	Laddu Lal Rai	Grinder	27-2-84	
		(Gate Pass No. 2869)		
73.	Ganesh Jha	Grinder (w.e.f. 1-9-83)	22-2-83	Project Construction Service
74.	Suresh Rai	Grinder (w.e.f. 1-9-83)	3-2-83	
75.	Darshan Dey	Khalasi	16-4-83	
76.	H.N. Khan	T. Welder	23-12-83	
77.	Chamru Yadav	Welder	18-5-83	
78.	Md. Hassan	Fabricator	19-8-83	Messrs Ranjan Industries
79.	Vijay Kumar Jha	Helper	1-9-83	
80.	Manoj Pathak	Helper	22-9-83	
81.	Ram Shankar Singh	Helper	13-12-83	
82.	C. B. Singh	Welder	1-1-84	
83.	N.K. Jha	Khalasi	16-11-83	
84.	Md. Rakim	Khalasi	1-10-83	
85.	Ram Dular Singh	Khalasi	26-9-83	
86.	Umesh Singh	Khalasi	1-9-83	
87.	Kamleshwari Das	Welder	18-4-83	
88.	C.B. Singh	Welder	29-4-83	
89.	Dasrath Paswan	Welder	10-5-83	
90.	V. K. Jha	Welder	18-4-83	
91.	Lalan Singh	Fitter	17-3-83	
92.	Fate Alam	Fitter	16-3-83	
93.	Naresh Bhagar	Fitter	18-4-83	
94.	Deo Narayan Mahato	T./E.	27-4-83	
95.	Ratneswar Singh	T./E.	16-5-83	
96.	Anil Kumar Mishra	T.E/E.	11-9-83	
97.	Rabinder Pathak	Helper	14-3-83	
98.	Shankar Singh	Helper	11-4-83	
99.	Bhola Jha	Helper	19-4-83	
100.	Suresh Thakur	Helper	20-4-83	
101.	Madan Mohan Jha	Helper	15-6-83	
102.	Ganesh Bhagat	Helper	9-9-83	
103.	Hare Ram Sah	Grinder	21-4-83	
104.	Md. Rabban	Grinder	3-6-83	
105.	Rabindra Rai	Grinder	1-7-83	
106.	Ganga Yadav	Rigger	20-4-83	
107.	Ram Ashray	Khalasi	18-5-83	
108.	Harilal Singh	Khalasi	19-6-83	
109.	Rajendra Singh	Khalasi	20-6-83	
110.	Pasupati Singh	Khalasi	23-6-83	
111.	Sashibhushan Thakur	Khalasi	4-6-83	
112.	Sipoti Sah	Khalasi	4-4-83	
113.	Khurshid Akram	Fitter	29-8-83	
114.	Ram Anuj Singh	Khalasi	29-9-83	

1	2	3	4	5
115.	Sudha Nand Bhagat	Khalasi	1-11-83	
116.	Bijay Singh	Khalasi	26-9-38	
117.	Md. Asmat Rahi	Fabricator		
118.	Md, S.K. Yakub	Welder	20-7-83	
119.	R.N. Poddar	Rigger	23-9-83	
120.	Gajender Singh	Rigger	2-11-83	
121.	Rajendra Ram	Rigger	28-11-83	
122.	Ashok Ram	Helper	23-9-83	
123.	Md. Hussain	Rigger	28-11-83	
124.	S. N. Singh	Helper	1-10-83	Messrs. Aparajita Enterprises
125.	Kalicharan Rai	Helper	19-10-83	
126.	Sonelal Rai	Helper	19-10-83	
127.	Subodh Singh	Helper	19-10-83	
129.	R. S. Yadav	Helper	16-11-83	
130.	Md. Ifiazi Ahmed	Helper	18-11-83	
131.	Ram Babu Paswan	Helper	19-12-83	
132.	Mubarak Hussain	Helper	19-12-83	

Soon after the receipt of the Order of reference, notices were duly served upon the parties. The parties neither appeared nor filed their W.S. Thereafter several adjournments were granted. But ultimately on 22-11-84 Shri S. Raha, Senior Assistant of Messrs. Stewarts and Lloyds Co. files settlement. I have gone through the terms of settlement which appears to be fair and proper and beneficial to both the parties. I accept the same and pass an Award in terms of the settlement which form part of the Award as Annexure.

I.N. SINHA; Presiding Officer,
[No. L-30012(7)/84-D.III(B)]

Annexure

25th September, 1984.

The Secretary,
Govt. of India,
Ministry of Labour & Rehabilitation,
Deptt. of Labour,
Shram Shakti Bhavan,
Rafi Marg,
New Delhi-110001.

Dear Sir,

We hereby jointly send a photocopy of the settlement dated 8-9-1984 to you as required by the Industrial Disputes Rules.

Yours faithfully,

For Stewarts & Lloyds of India Ltd and their Sub-contractors, in respect of theirs site establishments at IOC-Barauni — Sd/- Stewarts & Lloyds of India Ltd.

For workmen represented by Barauni Telshodhak Mazdoor Union (Regd. No. 1081). Union Bhawan, PO Refinery Township Pin 851117, Distt. Begusarai (Bihar). — D.P. Choudhary, Sec. B.T.M.U. Barauni Telsodhak Mazdoor Union

Encl : as above.

Copy forwarded to :—

1. The Chief Labour Commissioner (Central), Shram Shakti Bhavan, Rafi Marg, New Delhi-11001.
2. Regional Labour Commissioner (Central), Mahalla-Hirapur at NPO Dhanbad, Distt. Dhanbad, Bihar.
3. Asstt. Labour Commissioner (Centra) New Area, Kadam Kuwa Patan-800003. Phone 20, Patan-504020.

N.O.T
C.C. : Project Manager IOCL, Barauni.
C.C. : RCM, BIL, Barauni.

N.O.T.
C.C. : C&M, HO, Calcutta, Personnel Manager, HO, Calcutta.

Sd/-
(I.N. Sinha)
Presiding Officer
Central Govt. Industrial Tribunal (No. 2) Dhanbad.

Barauni Oil Refinery September 8, 1984

MEMORANDUM OF SETTLEMENT

1. Name of the parties. :

(I) 1. M/s. Stewarts & Llyods of India Ltd.
2. M/s. Project Construction Services
3. M/s. Kurchi Engg. Corporation
4. M/s. R. P. Roy
5. M/s. Kalpana Constn Co.
6. M/s. Ranjan Industries
7. M/s. Aparajita Enterprises

(II) Their workmen represented by Barauni Telshodhak Mazdoor Union (Regd. No. 1081), Union Bhavan, PO Refinery Township-851117, Distt. Begusarai (Bihar).

2. Representing Employer :

1. Shri P. K. Chatterjce of Stewarts & Llyods of India Ltd.
2. Shri P. R. Ghosh of S & L
3. Shri Uma Shankar Singh of KCC
4. Shri Raghubir Singh of PCS
5. Shri Ajoy Singh of Ranjan Ind.
6. Shri A. Samaddar of Kurchi Engg.
7. Shri R. P. Roy of M/s. RP Roy

3. Representing Workmen :

1. Shri Ram Sagar Sinha, Dy. President, BIMU
2. Shri D. P. Chowdhary, Secretary
3. Shri V. K. Jha, Secretary
4. Shri Mukesh Tanti, C. E. Member
5. Shri H. S. Pathak, CE Member

6. Shri Azmat Rahi, CE Member

7. Shri Sakaldeo Singh. CE Member

8. Chandrachur Singh, CE Member

All of Barauni Telshodhak Mazdoor Union.

4. Short recital of the case.—M/s. Stewarts & Lloyds of India Ltd. and their above named sub-contractors (hereinafter referred to as the Management) at Barauni Oil Refinery vide its letter dated 9th July, 1984 retrenched a total number of 132 workmen w.e.f. 10th July, 1984. Thereafter the Union raised a dispute on retrenchment and the workmen went on agitation at site as a result of which the Management declared lock-out of its site establishment by its letter dated 21st July, 1984. In an atmosphere of mutual understanding and cooperation and with the help and assistance of M/s. IOCL and M/s. EIL, Bipartite talks were held at Barauni on 6th, 7th and 8th September, 1984. Finally, a settlement between the parties has arrived at as under.

5. Terms of Settlement :

(a) The Management has agreed, in order to minimise the hardship of the workmen and without creating any precedent to pay all workmen other than the workmen of M/s. Kurchi Engg. Corporation, an ex-gratia amount equivalent to one month's wages.

(b) In case of M/s. Kurchi Engg. Corprn. workmen, the Management has agreed to pay fifteen days' wages as ex-gratia payment.

(c) The Union and the workmen have agreed that they have no dispute with the Management in regard to

(i) Retrenchment of 132 workmen w.e.f. 10-7-1984 and

(ii) Lock-out at site w.e.f. 21-7-1984.

6. The lock-out will be lifted from 10th September, 1984.

7. This settlement disposes of all disputes between Management and the Union as far as the Retrenchment and Lockout is concerned.

8. The parties agreed to make all possible efforts to ensure completion of the work by December, 1984.

Sd/-
P. K. Chatterjee
Sd/-
P. R. Ghosh
Sd/-
Uma Shankar Singh
Sd/-
Raghubir Singh
Sd/-
Ajoy Singh
Sd/-
A Samaddar
Sd/-
R. P. Roy
Sd/-
Ram Sagar Sinha
Sd/-
D. P. Chowdhary
Sd/-
V. K. Jha
Sd/-
Mukesh Tanti
Sd/-
H. S. Pathak
Sd/-
Azmat Rahi
Sd/-
Sakaldeo Singh
Sd/-
Chandrachur Singh

New Delhi, the 27th December, 1984

S.O. 97.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal, Kanpur in the industrial dispute between employers in relation to the management of Messrs Magnesite and Minerals Limited, P.O. Ghandak, Distt. Pithoragarh, and their workmen, which was received by the Central Government on the 21st December, 1984.

IN THE COURT OF CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL CUM LABOUR COURT, KANPUR

PRESENT :

Sri R. B. Srivastav

In the matter of dispute

BETWEEN

Shri S. Prasad

V/s.

M/s. Magnesite And Minerals Limited (U.P.)

I.D. No. 41/84

The Central Government vide it order No. L-27012(1)/84-D. III(B) dated 10th April, 1984 sent the following reference for award.

"Whether the action of the management of M/s. Magnesite and Minerals Limited, P.O. Chandak, District Pithoragarh, in terminating the services of Shri S. Prasad, Chargeman (Mechanic) in their D.B.M. Plant (Calcination Plant) with effect from 26th November, 1983 is justified ? If not to what relief is the workmen concerned entitled ?"

Registered notices were sent to the workmen to file statement of claim, but despite that none appeared for the workmen. In the circumstances no claim award is given hereby.

R. B. SRIVASTAV, Presiding Officer

[No. L-27012/1/84-D. III(B)]

NAND LAL, Under Secy.

नई दिल्ली, 27 दिसम्बर, 1984

का. आ. 98:—केन्द्रीय सरकार ने यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना अपेक्षित था औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 2 के खण्ड (ढ) के उपखण्ड (vi) के उपबन्धों के अनुसरण में भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का. आ. 2211 दिनांक 20 जून, 1984 द्वारा बैंकिंग उद्योग को उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए 29 जून, 1984 से छः मास की कालावधि के लिए लोक उपयोगी सेवा घोषित किया था ।

और केन्द्रीय सरकार की राय है कि लोकहित में उक्त कालावधि को छः मास की और कालावधि के लिए बढ़ाया जाना अपेक्षित है,

अतः, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 2 के खण्ड (ढ) के उपखण्ड (vi) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त उद्योग को उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए 29 दिसम्बर, 1984 से छः मास की और कालावधि के लिए लोक उपयोगी सेवा घोषित करती है ।

[सं. एस. 11017/9/81 डी I(ए)]

भवानी सिंह मीना, उप-सचिव

New Delhi, the 27th December, 1984

S.O. 98.—Whereas the Central Government having been satisfied that the public interest so required had, in pursuance of the provision of sub-clause (vi) of clause (n) of section 2 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), declared by the notification of the Government of India in the Ministry of Labour S.O. No. 2211 dated the 20th June, 1984 the Banking Industry carried on by a Banking Company as defined in clause (bb) of section 2 of said Act to be a public utility service for the purpose of the said Act, for period of six months, from the 29th June, 1984.

And whereas, the Central Government is of opinion that public interest requires the extension of the said period by a further period of six months;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by the proviso to sub-clause (vi) of clause (n) of section 2 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby declares the said industry to be a public utility service for the purpose of the said Act, for a further period of six months from the 29th December, 1984.

[F. No. S-11017/9/81-D.I(A)]

B. S. MEENA, Dy. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064

AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1985